ई एफ ए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट

2011

सबके लिए शिक्षा

सारांश

गुप्त संकट: सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

गुप्त संकट: सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा

सारांश

यूनेस्को प्रकाशन

यह रिपोर्ट एक स्वतंत्र प्रकाशन है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से यूनेस्को द्वारा अधिकृत है। यह एक साझे प्रयास की परिणिति है जिसमें रिपोर्ट दल के सदस्य एवं अन्य बहुत सारे लोग, एजेंसियां, संस्थान एवं सरकारें सम्मिलित है।

इस प्रकाशन में प्रयुक्त पदाधिकारी एवं सामग्री का प्रस्तुतिकरण किसी एक व्यक्ति की विचार धारा को व्यक्त नही करतीं, जो भी यूनेस्को से उस देश, केन्द्रशासित क्षेत्र, शहर या क्षेत्र या प्राधिकरण की कानून स्थिति या उसकी सीमाओं / चार–दीवारी के परिसोमन से संबंद्ध है।

दि इएफए ग्लोबल मोनोटरिंग रिपोर्ट (सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट) टीम इस पुस्तक में समाहित तथ्यों तथा उसकी अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त किए गए विचार के लिए उत्तरदायी हैं, जोकि आवश्यक नहीं है कि यूनेस्को के हों और न ही संगठन की प्रतिबद्धता है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में प्रकट किए गए दृष्टिकोण एवं वयक्त विचारों के लिए इस रिपोर्ट के निदेशक जिम्मेदार हैं।

दि ई एफ ए ग्लोबल मोनीटरिंग रिपोर्ट टीम

निदेशकः केबिन वाटकिंस

शोधकार्यः समर अल–सामारई, निकोल बेला, स्टुअर्ट–कैमेरोन, अन्ना दास, फ्रैंकोइस लैकेरेक, इलिस लिगौल्ट, अनीस लोयजिलोन, कैरेन मूर, पैट्रिक मोंटनोरीडेस, पैलिन रोज

संचार एवं प्रसारः डाइएड्रिक डि जोंग, एन्ड्रू जोहंसटक, लीला लैपिस, मैरीसोल संजीनेस, सोफी स्कोलैंड्राफ, सेलिन स्टीयर

प्रचालन एवं उत्पादनः इरिन चेमेरी, जूलिया हेईस, मार्क फिलिप, बोआ लीइबनिट्स, जूडिथ रनड्रियानटोअवीना, मार्टीना सिमेटी, सुहाद वैरिन

रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी हेतु, कृपया संपर्क करें:

निदेशक
ई एफ ए ग्लोबल मोनीटरिंग रिपोर्ट टीम
द्वारा यूनेस्को
7, प्लेस डि फोन्टेनोय, 75352 पेरिस, 07 एस पी, फ्रांस
e-mail. : efareport@unesco.org
Tel.: +33 1 45 68 10 36
Fax: +33 1 45 68 56 41
www.efareport.unesco.org

यूनाइटेड नेशंस इजूकेशनल,
साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (यूनेस्को)
द्वारा वर्ष 2011 में प्रकाशित
7, प्लेस डि फोंटेनोय, 75352 पेरिस, 07 एस पी, फ्रांस.
ग्रॉफिक डिजाइन कर्ता – सिलवाइन बायेन्स
लेआउट : सिलवाइन बायेन्स
मुद्रकः यूनेस्को
प्रथम संस्करण 2011

© यूनेस्को 2011
नई दिल्ली में मुद्रित
संदर्भः ईडी–2008 / डब्लू एस / 51 जोब 3627.10

ED-2011/WS/1

पूर्ववर्ती सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोट (ई एफ ए ग्लोबल मोनीटरिंग रिपोर्ट्स)

2010 गरीबों तक पहुंचना
2009 असमानता से उबरनाः अभिशासन क्यों मायने रखता है।
2008 सबके लिए शिक्षा वर्ष 2015 तक– क्या हम इसे कर पाएंगे?
2007 सुदृढ़ नींव– प्रारंभिक बालपन (शैशव) की देखभाल एवं शिक्षा।
2006 जीवन के लिए साक्षरता
2005 सबके लिए शिक्षा– गुणवत्ता अत्यावशक
2003 / 04 जेंडर (लिंग) एवं सबके लिए शिक्षा– समानता हेतु छलांग
2002 सबके लिए शिक्षा– क्या विश्व रास्ते पर है?

कवर फोटो
उत्तरी यूगांडा में सरकारी सेनाओं एवं लॉर्डस रेसिसटेंस आर्मी के बीच फंस गए बच्चों के द्वारा देखे सच को पेंट के माध्यम से दर्शाया गया
© एक्संथोपौलोस डायमन / गाम्मा

प्राक्कथन

संयुक्त राष्ट्र का गठन दुनिया को युद्ध की विभीषिका से मुक्त करने के लिए किया गया था। यह भविष्य की इस प्रतिबद्धता 'भय से मुक्ति' के साथ डटा रहा। इस भविष्य को यथावत बनाए रखने के लिए 'यूनेस्को' का गठन किया गया। हमारे संविधान के मार्मिक शब्दों में, हमे अनिवार्य बनाया गया कि 'जीवन और उपायों में एक दूसरे की उपेक्षा' करते हुए शिक्षा के माध्यम से संघर्ष करते रहें जिसने कि सभी आयु वर्ग को सशस्त्र संघर्ष हेतु समृद्ध किया।

इस वर्ष सबके लिए शिक्षा (ईएफए) वैश्विक निगरानी रिपोर्ट इतिहास को एक समयवृद्ध अनुस्मारक उपलब्ध कराती है, जिन आदर्श विचारों एवं मूल्यों पर संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। यह मूल्य 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से और अधिक समृद्ध हुए। ये वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा अपनाए गए सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों में भी प्रतिबिंबित हुए। दुर्भाग्यवश, हम लोग अभी भी सार्वभौमिक घोषणा के विन्यासकारों के द्वारा विश्व के विचारों से पर्याप्त दूर है तथा शिक्षा के अपने साझे लक्ष्य से भी दूर हैं। और सशस्त्र संघर्ष के द्वारा लादी गई दुदर्मनीय चुनौतियों से टकरा पाने में सामूहिक रूप से असफल हो रहे हैं।

जैसा कि *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* का नया संस्करण स्पष्ट करता है कि युद्ध लगातार दुनिया भर के करोड़ों सर्वाधिक नाजुक लोगों के जीवन को विनष्ट कर रहे हैं। युद्ध–स्थिति शिक्षा के सुअवसरों को भी एक पैमाने पर नष्ट कर रहे हैं जिसकी अपूर्णतः को माना गया है। तथ्य बताते हैं कि युद्ध प्रभावित देशों के 40% बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं। इन्हीं देशों में से कुछ में व्यापक जेंडर (लिंग) भेदभाव है तथा दुनिया में सबसे ज्यादा निम्न साक्षरता स्तर भी है। मुझे आशा है कि अब तक शिक्षा में गुप्त संकट क्या है पर प्रकाश केन्द्रित करने से, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय स्तर उजागर कर के चार मुख्य क्षेत्रों में कार्रवाई करने में मददगार होगी।

सबसे पहले, हमें इस बात के लिए गंभीर होने की जरूरत है कि युद्ध– प्रभावित देशों में शिक्षा संकट के केन्द्र(मर्म) में घोर मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोका जाए। हम रातों–रात शांति पूर्ण समाज नहीं तैयार कर सकते हैं। लेकिन बच्चों पर होने वाले हमलों, व्यापक स्तर पर एवं क्रमबद्ध तरीके से लड़कियों एवं महिलाओं के साथ बलात्कार या फिर स्कूल सुविधाओं को विनष्ट करने जैसी घटनाओं को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है, जिसे कि हमने इस रिपोर्ट में अभिलेखित किया है। यह पूर्णतः अस्वीकार्य है कि यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित होने के बावजूद युद्ध में यौन आतंक (औरतों के लिए) एक हथियार बना हुआ है– एक ऐसा हथियार जिसमें औरतों एवं युवा लड़कियों के लिए अकथ्य प्रताड़ना, भय एवं असुरक्षा की पीड़ा एवं उनकी शिक्षा की अकथनीय क्षति छुपी होती है। मैं अपने सहकर्मियों के साथ संयुक्त प्रणाली के आधार पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूं जिससे संघर्षरत क्षेत्रों में फंसे बच्चों के लिए मानव अधिकार संरक्षण मजबूत हो।

दूसरे, मानवीय(आर्थिक) सहायता प्रणाली को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जब मैंने आपात्काल द्वारा प्रभावित देशों में दौरा किया, तो मैं अक्सर साधारण प्रयासों पर अटका, जिन्होंने शिक्षा को जारी रखा। दुर्भाग्यवश सहायता दानदाता उस संकल्प से मेल नहीं खाते हैं। शिक्षा क्षेत्र वर्तमान में मानवीय सहायता का केवल 2% हिस्सा प्राप्त करता है और मानवीय सहायता प्रणाली अपने आप में अपर्याप्त निधि युक्त है। हम सभी, जो सबके लिए शिक्षा की भागीदारी में सम्मिलित है, के लिए यह करना आवश्यक है कि मानवीय सहायता प्रयास की धुरी में शिक्षा को रखने का मामला बनाया जाए।

तीसरे, हमें यह करने की जरूरत है कि शांति के सुअवसरों के झरोखों का और अधिक प्रभावी तरीके से दोहन करें। संयुक्त राष्ट्र(यूनाइनेटड नेशंस) के महासचिव श्री बैन की–मून ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र संघर्ष से बाहर निकलने वाले देशों की खतरनाक यात्रा को समर्थित करने के लिए वर्तमान में आवश्यक प्रकम का अभाव है। परिणामस्वरूप, शांतिनिर्माण एवं पुनर्गठन के सुअवसर खो देते हैं। जोकि असीम मानव एवं वित्तीय मूल्य पर होता है। *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी*

रिपोर्ट ने निधियों के संग्रहण में एक वृद्धि हेतु एक केस बनाया है। मुझे विश्वास है कि दानदाता तथा संघर्ष प्रभावित राष्ट्र इस क्षेत्र में बढ़े हुए समन्वय से प्रर्याप्त लाभ पाने वाले हैं।

अंत में, हमें जरूरत है कि शांति के लिए शक्ति के रूप में काम करने हेतु शिक्षा की संपूर्ण संभावनाओं को मुक्त कर दें। यूनेस्को के संविधान की पहली पंक्ति भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करती है कि 'चूंकि युद्ध पुरूषों (एवं स्त्रियों) के दिमाग में शुरू होते है; और पुरूषों(एवं स्त्रियों) के दिमाग ही हैं जहां शांति के लिए मोर्चाबंदी अवश्य ही निर्मित होनी चाहिऐ'। जनता की प्रवृत्ति से अधिक कोई अन्य प्रतिरक्षा सुरक्षित नहीं है जो सहनशीलता, परस्पर भाई–चारे, सम्मान एवं संवाद हेतु प्रतिबद्धता में प्रतिस्थापित है। इन प्रवृत्तियों को पूरी दुनिया भर में प्रतिदिन प्रत्येक कक्षा में सक्रियता से पल्लवित किया जाना चाहिए। स्कूलों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए धर्मान्धता, अंध–देशभक्ति को बढ़ावा तथा अन्य लोगों का असम्मान करना न केवल एक बुरी शिक्षा का मार्ग है, बल्कि इसके साथ ही, यह एक हिंसा का रास्ता भी है। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि संघर्ष प्रभावित देशों में शिक्षा प्रणाली के पुनःनिर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाने में यूनेस्को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने वर्तमान काम के क्षेत्र का ध्यान अंतर–सांस्कृतिक संवाद, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक, प्रशिक्षण तथा पाठ्यपुस्तक सुधार जैसे कार्यक्रमों पर केन्द्रित किया है।

आज संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के लगभग पैंसठ साल पूरे हो चुके हैं। सशस्त्र संघर्षों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियां बदल चुकी हैं। आज भी संयुक्त राष्ट्र(संघ) प्रणाली को सहारा देने वाले सिद्धांत, मूल्य एवं संस्थान सदैव की भांति मान्य है। आइए हम सब शिक्षा में संघर्ष एक गुप्त संकट की थीम (विषय वस्तु) का उपयोग करते हुए एक साथ मिलकर काम करें और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जिसमें हर एक बच्चा और हर एक अभिभावक भय मुक्त जीवन जी सके।

इरिना बोकोवा के द्वारा प्राक्कथन
यूनेस्को की महानिदेशक

2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* से कुछ विशिष्टताएं

विश्व वर्ष 2015 तक सबके लिए शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर नहीं है। यद्यपि यहां पर बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति हुई है, तथापि 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* से कुल मिलाकर यह संदेश निकलकर आता है कि अधिकतर लक्ष्य एक व्यापक अंतर के साथ चूक जाएंगे। सशस्त्र संघर्ष से प्रयावित देश विशिष्ट भयानक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकारों को चाहिए कि वे एक दूरगामी व्यापक अत्यावश्यकता, संकल्प एवं एक सामान्य उद्देश्य प्रदर्शित करे, ताकि लक्ष्य पहुंच के दायरे में आएं।

2015 के लक्ष्य की दिशा में प्रगति

पिछले दशक ने विश्व के कुछ गरीबतम देशों में सबके लिए शिक्षा लक्ष्य की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति दिखी है।

- शैशव कल्याण में सुधार हो रहा है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है, उदाहरणार्थ; वर्ष 1990 में 12.5 मिलियन से घटाकर वर्ष 2008 में 8.8 मिलियन रह गई।

- वर्ष 1999 से 2008 तक 52 मिलियन बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पंजीकृत हुए। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या आधी हो गई। उप सहारा अफ्रीकी देशों में, पंजीकरण अनुपात एक तिहाई बढ़ा, बावजूद इसके कि प्राथमिक स्कूलों की आयुवाली जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई।

- प्राथमिक पंजीकरण में लिंग(जेंडर) भेद में, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ, जोकि दशक के शुरूआत में भारी जेंडर भेद के साथ शुरू हुआ था।

इन सकारात्मक विकासों के बावजूद, वर्ष 2000 में स्थापित किए गए सबके लिए शिक्षा लक्ष्य के बीच अभी भी भारी अंतर है और इस दिशा में सीमित अग्रिमताएं की गई हैं।

- भूख ने प्रगति को पीछे धकेला है। विकास शील देशों में, 5 वर्ष से कम आुय के 195 मिलियन बच्चों में से हर तीन में एक बच्चा कुपोषित है जिसके कारण उनके सहजात विकास तथा उनके दीर्घकालिक शिक्षा के परिदृश्य में असुधार्य क्षति होती है।

- स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में कमी बहुत धीमी गति से हो रही है। वर्ष 2008 में; 67 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर थे जिनकी सार्वजनिक पंजीकरण की प्रगति धीमी थी। यदि वर्तमान प्रवृति जारी रही, तो संभवतः 2015 में आज से कहीं अधिक बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे।

- बहुत सारे बच्चे अपना प्राथमिक शिक्षा चक्र पूरा करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। उप सहारा–अफ्रीका में ही अकेले, प्रतिवर्ष 10 मिलियन बच्चे प्राथमिक स्कूल छोड़ देते हैं।

- विश्व के लगभग 17% वयस्क–796 मिलियन लोग–आज भी प्राथमिक साक्षरता कौशल से वंचित है। इनमें से लगभग दो तिहाई औरतें हैं।

- शिक्षा की प्रगति को नुकसान पहुंचाने हेतु लैंगिक(जेंडर) भेदभाव निरंतर जारी है। क्या वर्ष 2008 में विश्व ने प्राथमिक स्तर पर लैंगिक समानता प्राप्त कर ली थी। यदि ऐसा होता तो प्राथमिक स्कूलों में लगभग 3.6 मिलियन अतिरिक्त लड़कियां स्कूलों में होतीं।

- पाकिस्तान में व्यापक असमानताएं अवसरों से प्रतिबंधित (विमुख) करती है जहां गरीब घरों के 7 से 16 वर्ष के लगभग आधे बच्चे स्कूल से बाहर है तुलनात्मक रूप में धनी घरानों के केवल 5% बच्चे स्कूल से बाहर हैं।

- लैंगिक भेदभव और पिछड़ापन जीवन घटाता है। उप सहारा अफ्रीका में औसत बाल मृत्युदर में यदि कमी आई है तो उन क्षेत्रो में जहां औरतें माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबद्ध हैं। यहां 1.8 मिलियन मौतें और भी कम हो सकती थीं।

- माध्यमिक शिक्षा प्राप्त औरतें बहुत संभव हद तक मां से शिशु में एचआईवी संचारण से बचाव के उपायों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं कि जो वर्ष 2009 में एचआईवी से संबद्ध बीमारियों में, अनुमानतः 260,000 मौतों में भागीदारी थी। मलावी में, माध्यमिक या इससे उच्च शिक्षा के साथ 60% माताएं जागरूक थी कि दवाइयां संचारण के जोखिम को घटा सकती हैं जबकि इसकी तुलना में शिक्षा रहित केवल 27% माताएं जागरूक थीं।

- बहुत सारे देशों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा अभी भी निचले स्तर पर है। करोड़ें बच्चे प्राथमिक स्कूलों से पढ़ने, लिखने एवं गणित/संख्या विषयक कौशल या ज्ञान के अपेक्षित स्तर से नीचे के उभर रहे हैं।

- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए वर्ष 2015 तक 1.9 मिलियन अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इनमें से आधे से ज्यादा की उप सहारा अफ्रीका में होगी।

सबके लिए शिक्षा वित्त सहायता

वैश्विक आर्थिक संकट ने राष्ट्रीय बजटों में दबाव बढ़ा दिया, फलतः विश्व के अधिकतर गरीबतम देशों ने शिक्षा योजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु अनेक प्रयासों से कम महत्व दिया। सहायता बजट भी दबाव में हैं। वर्ष 2015 की लक्ष्य तिथि में, पांच वर्ष से भी कम की अवधि के साथ, राष्ट्रीय सरकारों एवं दानदाताओं की जरूरत है कि सबके लिए शिक्षा के वित्तीय

अंतर को पाटने के लिए अपने प्रयासों को फिर से दुगुना कर दें।

- यद्यपि निम्न आय वाले देशों 1999 से शिक्षा पर अपनी राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी बढ़ाकर 2.9% से 3.8% कर दी है, तथापि कुछ क्षेत्रों एवं देशों में शिक्षा अभी भी उपेक्षित है। दक्षिण एशिया तथा उत्तर और पश्चिम एशिया शिक्षा पर सबसे कम निवेश करता है।

- बढ़े हुए राजस्व संग्रहण तथा शिक्षा के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता के साथ निम्न आय देश सबके लिए शिक्षा पर व्यय को 12 बिलियन यूएस डालर से बढ़ाकर 19 मिलियन यूएस डालर प्रतिवर्ष कर सकते हैं। जोकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 0.7% के बराबर वृद्धि है।

- शिक्षा बजट पर वित्तीय संकट ने एक भारी दबाव डाला है। निम्न आय वाले अठारह दशों में से सात देशों को इस रिपोर्ट हेतु सर्वेक्षित किया गया, जिन्होंने वर्ष 2009 में शिक्षा व्यय पर कटौती की है। इन देशों में 3.7 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं

- कुल मिलाकर 2002 से, प्राथमिक शिक्षा पर सहायता राशि 4.7 बिलियन यूएस डालर से दोगुनी हो चुकी है। जो उन नीतियों को समर्थित करते हैं जिनसे सबके लिए शिक्षा में प्रगति को बढ़ावा मिलता है। हालांकि वर्तमान सहायता राशि का स्तर 16 बिलियन यूएस डालर की वार्षिक आवश्यकता से काफी कम है जिससे निम्न आय अपने देश वित्तीय अंतराल को पाटने अंतराल के निकट पहुंच सकें।

- दानताओं ने अपनी प्रतिबद्धता नहीं निभाई जो कि वर्ष 2005 में उन्होंने सहायता बढ़ाने के लिए कहीं थी। ओईसीडी ने अनुमानित किया है कि प्रत्याशित वैश्विक लागत में प्रतिवर्ष 20 बिलियन यूएस डालर की कमी रहती है।

- वर्तमान सहायता प्रवृत्ति चिंता का विषय है। वर्ष 2007 से प्राथमिक शिक्षा हेतु विकास सहायता वहीं ठहरी हुई है। वर्ष 2008 से उप सहारा अफ्रीकी देशों में प्राथमिक शिक्षा सहायता में प्रति वर्ष प्राथमिक स्कूली आयु के प्रति बच्चे पर लगभग 6% की कमी आई है।

- अनेक प्रमुख दानदाता सहायता बजट को शिक्षा के उच्च स्तर की ओर मोड़ रहे हैं। यदि सभी दानदाता अपनी शिक्षा सहायता में कम से कम आधा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर संवितरित करते हैं तो प्रतिवर्ष 1.7 बिलियन अतिरिक्त डालर संसाधित संग्रहीत किए जा सकते हैं।

नया एवं नवोन्मेषी शिक्षा निधि समाधान सबके लिए शिक्षा वित्तीय अंतर को पाटने में सहायक हो सकता है। इसके साथ रिपोर्ट में अन्य प्रस्ताव ये हैं

- *शिक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा,* जो ठीक हेल्थ सेक्टर के मॉडल के समान आधारित हो, जो दानदाताओं को कठिन आर्थिक वातावरण में नए संसाधनों के संग्रहण में सहायक हो सकते हैं। वर्ष 2011 से 2015 तक के बीच बोंड (बंध पत्र) जारी करके 3 से 4 बिलियन यू.एस. डालर प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए संग्रहीत किए जा सकते हैं।

- यूरोप में मोबाइल फोन के लेनदेन में 0.5% अधिभार से प्रतिवर्ष 894 यूएस डालर उगाहे जा सकते हैं।

गुप्त संकटः सशस्त्र संघर्ष एवं शिक्षा

सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित देश सबके लिए शिक्षा लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा पीछे है और अभी तक उनकी शिक्षा चुनौतियां व्यापक रूप से बिना समाचार बने जा रही हैं। संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों में शिक्षा में गुप्त संकट एक वैश्विक चुनौती है जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की मांग करती है। इसके साथ ही साथ आर्थिक वृद्धि को तीव्रता प्रदान करने के संदर्शों, गरीबी को घटाने तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को कमजोर बनाता है तथा सशस्त्र संघर्ष असमानता, नैराश्य तथा शिकायतों को प्रबलित करते हैं जो देशों को हिंसा के चक्र में लपेट लेते हैं।

शिक्षा पर सशस्त्र संघर्ष का संघात

- वर्ष 2008 तक इस दशक में 35 से अधिक देशों ने सशस्त्र संघर्ष को झेला, जिनमें से 30 देश निम्न एवं निम्न मध्य आय वर्ग से हैं। निम्न आय देशो में हिंसात्मक संघर्ष की घटनाएं औसतन 12 वर्ष अवधि की थीं।

- संघर्ष प्रभावित गरीब देशों में दुनिया की 42% जनसंख्या रहती है जिसमें प्राथमिक स्कूल आयु वाले 28 मिलियन बच्चे स्कूल जाने से वंचित रहे।

- अन्य गरीब देशों की तुलना में संघर्ष प्रभावित गरीब देशों के बच्चों को अपनी पाचवीं वर्षगांठ तक दो गुना मृत्यु की संभावना रहती है।

- सघर्ष प्रभावित गरीब देशों में केवल 79% युवा लोग साक्षर है जबकि तुलनात्मक रूप में अन्य गरीब देशों के 93% युवा लोग साक्षर हैं।

- सक्षस्त्र संघर्ष में संलग्न राष्ट्रीय (राज्य) एवं गैर राष्ट्रीय पार्टिया वृहद रूप में सामान्य नागरिकों एवं नागरिक आधारभूत ढांचों को लक्षित करती हैं। स्कूल तथा स्कूली बच्चे व्यापक रूप से युद्धरत लोगों द्वारा एक यथार्थ या तर्कसंगत लक्ष्य के रूप में देखे जाते हैं जो स्पष्टतया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

- समाचारों के अनुसार 43 मिलियन से अधिक लोग सशस्त्र संघर्ष के कारण विस्थापित हुए, संभवतः वास्तविक संख्या इसे से अधिक भी हो सकती है। शरणार्थी तथा आंतरिक रूप से विस्थापित लोग प्रमुख रूप से शिक्षा की वाधा को झेलते हैं। वर्ष 2008 में यूएनएचसीआर के शिविरों में केवल 69% शरणार्थी स्कूली आयु के बच्चों ने प्राथमिक स्कूलों में भाग लिया।

संघर्ष प्रभावित देशों में शिक्षा पर व्यय

- सशस्त्र संघर्ष सार्वजनिक निधियों को शिक्षा की बजाय सैन्य व्ययों की ओर मोड़ देते हैं। 21 विकासशील देश वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में व्यय से अधिक शस्त्रों की खरीद पर व्यय कर रहे हैं। यदि वे अपने सैन्य खर्चों में 10% कटौती कर दें तो 9.5 मिलियन अतिरिक्त बच्चे स्कूलों में होते।

- सैन्य खर्चे सहायता संसाधनों को भी विचलित करते हैं।

दान–दाताओं द्वारा सबके लिए शिक्षा हेतु दिए जाने वाले 1.6 मिलियन यूएस डालर केवल 6 दिनों की सैन्य व्यय के बराबर है जो कि बाहय वित्तीय सहायता अंतर है।

- शिक्षा खाते के लिए मानवीय सहायता का केवल 2% आता है। और कोई अन्य क्षेत्र मानवीय अपील सहायता का इतना छोट हिस्सेदार नहीं है तथा शिक्षा की सहायता अनुरोध का केवल 38% भाग पूरा करता है। जोकि सभी क्षेत्रों का औसतन केवल आधा है।

बदलाव के लिए कार्यसूची

यह रिपोर्ट चार व्यवस्थागत असफलताओं से निपटने हेतु लक्षित बदलावों के लिए एक कार्यसूची स्थापित करती है।

- *संरक्षण की असफलता।* संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के माध्यम से काम करते हुए, सरकारों को व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए जो शिक्षा को प्रभावित करने वाले मानव अधिकार उल्लंघनों की निगरानी एवं रिपोर्ट करें तथा इन उल्लंघनों को रोकने के लिए लक्षित राष्ट्रीय योजनाओं को समर्थित करे और कुख्यात एवं बार–बार अपराध करने वालों पर लक्षित दंड लादे जाने चाहिए। बलात्कार एवं यौन हिंसा पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाना चाहिए, जिसके साथ एक अंतराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट सीधे तौर पर मुकदमेबाजी के मामलों के मूल्यांकरन में संलग्न हो। यूनेस्को को शिक्षा प्रणाली पर हमला करने वाले रिपोर्टिंग एवं निगरानी में सीधे तौर पर नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

- *प्रावधानों की असफलता।* यहां पर एक तत्काल आवश्यकता है कि मानवीय सोच को बदला जाए तथा संघर्ष से संबंधित आपात्स्थितियों के दौरान शिक्षा की महत्पवूर्ण भूमिका को पहचाना जाना चाहिए। मानवीय संग्रह निधियों हेतु वित्तीय सहायता लगभग 730 मिलियन यूएस डालर से बढ़ाकर 2 मिलियन यूएस डालर किया जाए। संघर्ष प्रभावित समुदायों को शिक्षा आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ीकृत किया जाना चाहिए। शरणार्थियों के लिए अभिशासन व्यवस्था को शिक्षा हेतु बेहतर पहुंच के लिए सुधारा जाना चाहिए। सरकारों को चाहिए कि आंतरिक(अंतरदेशीय) विस्थापित लोगों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए भी सुदृढ़ीकृत करें।

- *पुनर्निमाण या पुनर्गठन की असफलता।* दानदाताओं को आवश्यकता है कि मानवीय सहायता एवं दीर्घकालिक सहायता के कृत्रिम विभाजन को समाप्त कर दें। राष्ट्रीय संग्रहण निधि के माध्यम से अधिक विकास सहायताओं को प्रणालीकृत करना चाहिए। जैसे कि अफगानिस्तान में सफलतापूर्ण सूविधा। सुधारकृत सबके लिए शिक्षा फास्ट ट्रैक इनीसिएटिव (एफटीआई अर्थात् सबके लिए शिक्षा हेतु तीव्र पथ प्रयास) के माध्यम से काम करने हुए संग्रह निधि हेतु दानदाताओं को और अधिक प्रभावी बहु स्तरीय व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रचारित व्यवस्था के तुलनात्मक होना चाहिए। फास्ट ट्रैक इनीसिएटिव हेतु निधियों को 6 बिलियन यूएस डालर प्रतिवर्ष तक बढ़ाकर किया जाना चाहिए जो कि संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों हेतु समर्थन को सुविधाकृत बनाने हेतु लचीले नियमों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- *शांति निर्माण की असफलता।* शांति को पोषित करने के लिए शिक्षा की संभावनाओं को मुक्त करने हेतु सरकारों एवं दानदाताओं को जरूरत है कि भाषा पर नीति, पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा देर से बकाया शिकायतों के संभावित प्रभाव के मूल्यांकन के द्वारा विकेन्द्रीकृत सूचना प्राप्त होनी चाहिए। स्कूलों को पहला एवं महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां अत्यंत महत्वपूर्ण कौशलों, सहनशीलता, परस्पर आदर एवं दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने की क्षमता को प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण निधि के माध्यम से, यूनेस्को तथा यूनीसेफ के साथ अधिक समेकित शिक्षा हेतु व्यापक शांति निर्माण रणनीतियों के माध्यम से शिक्षा में 500 मिलियन यूएस डालर तथा 1 बिलियन यूएस डालर के बीच प्रणालित करने चाहिए।

कुछ प्रमुख संदेश

'युवा उभार (यूथबल्ज)' एवं शिक्षा में असफलता का संयोजन संघर्ष के जोखिम को प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे युद्ध प्रभावित देशों में शिक्षा प्रणाली युवाओं को वह कौशल नहीं प्रदान करती, जिससे वे गरीबी एवं बेरोजगारी से बच सकें। बहुत सारे संघर्ष प्रभावित देशों में 25 वर्ष की आयु से कम के युवाओं की संख्या जनसंख्या का 60% हिस्सा है और इससे उबरने के लिए एक अच्छी शिक्षा निर्णायक होती है जो कि प्रायः संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के गायब होने पर हिंसात्मक संघर्ष में भागीदारी निभाती है।

गलत प्रकार की शिक्षा हिंसात्मक संघर्ष को पल्लवित करती है शिक्षा में यह संभावना है कि वह शांति की एक शक्ति के रूप में काम करे, लेकिन बहुत बार प्रायः स्कूलों का उपयोग सामाजिक विभाजन, असहनशीलता एवं पूर्वाग्रहों को प्रबलित करने में होता है जो एक युद्ध का रूप ले लेते हैं। कोई भी देश तब तक शांति एवं समृद्धि से रहने की कामना नहीं रख सकता; जब तक कि आपस में अपने नागरिकों के बीच परस्पर विश्वास, सौहार्द न हो, जिसे कक्षा से ही शुरू किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सरकारें तथा अंतराष्ट्रीय समुदाय मानव अधिकारों को कायम रख पाने में असफल रही है। जो सरकारी एवं गैर सरकारी पार्टियां सशस्त्र संघर्ष में संलग्न हैं वे प्रायः स्कूली बच्चों, नागरिकों तथा स्कूलों को लक्ष्य बनाते हैं जो कि पूर्णतः अदंडित (संरक्षित) होते हैं। लेकिन यह बातः विशेषरूप से तब और सही है जहां औरतों पर बलात्कार एवं यौन शोषण के अन्यरूपों से संबद्ध मुद्दे हैं। सबके लिए शिक्षा के पणधारकों को चाहिए कि मानव अधिकारों के लिए और अधिक बलपूर्वक हिमायत करें।

प्रमुख दानदाताओं की राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यसूची के द्वारा सहायता प्रभावीपन के साथ समझौता। संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों ने भारी मात्रा में विकास सहायता को रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ दिया है विशेष रूप से अफगानिस्तान, इराक एवं पाकिस्तान। शिक्षा की सहायता को युद्ध प्रचालन उपयोग समर्थन से स्थानीय नागरिको, समुदायों, स्कूली बच्चों तथा सहायता कार्यकर्ताओं के लिए एक खतरा पैदा करता है। दानदाताओं को चाहिए कि वे सहायता को विसैन्यीकृत करें।

मानवीय सहायता प्रणाली असफलः संघर्ष में फंसे बच्चों हेतु। संघर्षों के दौरान शिक्षा को जारी रखने के लिए स्थानीय समुदाय ने महान संकल्प एवं नवाचारी प्रयासों का प्रदर्शित किया है। लेकिन ठीक यही बात दानदाताओं के लिए नहीं कही जा सकती है। मानवीय सहायता समुदायों को जरूरत है कि संघर्ष प्रभावित समुदायों की आकांक्षाओं के साथ खड़े हों।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रणाली शांति एवं पुनर्निमाण के सुअवसरों का दोहन करने के लिए संसाधित नहीं है बहुत सारे देशों जो संघर्ष से उबर रहे हैं, अपनी शिक्षा प्रणाली को पुनःनिर्मित करने वाले संसाधनों से अभाव ग्रस्त होते हैं। वर्तमान में सीमित एवं पूर्व अनुमान रहित मानवीय सहायता प्रवाह पर निर्भर रहते हैं। इन देशों को पूर्वानुमानित दीर्घ कालिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ताकि शिक्षा प्रणाली सहित अच्छी गुणवत्ता का विकास हो।

प्रस्तावना

सबके लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर आल) पर कार्यवाही के लिए डाकार रूपरेखा (ढांचे) को सभी सरकारों के द्वारा वर्ष 2000 में डाकार, सेनेगल में अधिगृहीत किया गया था, जिसको वर्ष 2015 तक प्राप्ति के उद्देश्य से छह व्यापक लक्ष्य एवं कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इस रूपरेखा में एक उपशीर्षक दिया गया था– अपनी सामूहिक प्रतिवद्धता को पाना'। दस वर्ष बाद, '2011 सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट' का कुल मिलाकर संदेश यह है कि दुनिया भर की सरकारें अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता निभाने में थोड़ा पीछे रह गई हैं।

लेकिन यह सख्त निष्कर्ष कुछ महत्वपूर्ण उपलिब्धयों से विमुख नहीं करती है। स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घटी है, लिंग भेद कम हो रहा है और अधिकाधिक बच्चे प्राथमिक स्कूलों से माध्यमिक शिक्षा एवं उससे आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के कुछ गरीबतम देशों ने प्रभावी लाभ दर्ज कराया है और यह प्रदर्शित किया है कि प्रगति को तीव्र करने में निम्न आय एक स्वाचालित बाधा नहीं है। यद्यपि, अभी भी डाकार घोषणा एवं उपलब्धि के बीच भारी अंतर शेष है और यहां पर चिंता के लक्षण यह है कि वह चौड़ी हो रही है। वर्तमान प्रवृत्ति में, शायद वर्ष 2015 में आज की तुलना में अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हो सकते हैं। इस चित्र को बदलने के लिए, बिना किसी सकेन्द्रित प्रयास के, विश्व के बच्चों हेतु डाकार की वचनबद्धता व्यापक रूप से टूट जाएगी।

डाकार में निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि की असफलता के बहुत दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। व्यापक सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एम डी जी एस) जैसे कि गरीबी उन्मूलन, पोषण, बाल उत्तरजीविता एवं मातृ स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में शिक्षा की तीव्र प्रगति इन्हें उपलब्ध करने के लिए निर्णायक होती है। इससे भी अधिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गहन अंतर को कम करने के लिए शिक्षा हेतु अवसर की असफलता आर्थिक वृद्धि को पीछे धकेलता है तथा वैश्वीकरण के असमान प्रतिमान को प्रतिबलित कर लादता है। अधिक ध्यान देने के लिए कोई मुद्दा ज्यादा मायने नहीं रखता। अभी तक शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में फिसलती रही है और आज बामुश्किल 'आठ देशों के समूह' (जी–8) या 20 देशों के समूह (जी–20) की संबद्धता में शिक्षा ने जगह पाई हैं।

2011 सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग दुनिया भर में शिक्षा की स्थिति पर एक झलक प्रस्तुत करता है। इसने अग्रताओं (प्रगतियों), आधातों एवं नीतिगत दखलंदाजी के दायरों को पहचाना है जो प्रगति को तीव्रतर कर सकते हैं। भाग दो सबके लिए शिक्षा लक्ष्य में झेले जाने वाली एक सबसे बड़ी बाधा को दिखलाता है, वह है दुनिया भर के गरीबतम देशों में सशस्त्र संघर्ष। यह रिपोर्ट उन नीतियों की असफलता को देखती है जिनके कारण बाधा प्रबलित हुई तथा उन्हें मिटाने की रणनीतियों को भी देखती है। इसके साथ ही संघर्ष को रोकने एवं शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु एक कार्यसूची तय की है। □

भाग 1. सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों की ओर प्रगति की निगरानी

छह सबके लिए शिक्षा लक्ष्य

बचपन या शैशव कालीन देखभाल एवं शिक्षा : स्वास्थ्य को बढ़ावा, भूख से संघर्ष

बच्चे के कक्षा में प्रवेश करने से बहुत पहले ही शिक्षा के सुअवसर आकृति पा लेते हैं। वे भाषाई, जन्मजात तथा सामाजिक कौशल प्रारंभिक जीवन (बचपन) में ही विकसित कर लेते हैं जो उनके जीवन भर के लिए वास्तविक नींव होते हैं। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण एवं उत्प्रेरकता की कमी इन आधारों (नींव) को कमजोर बनाते हैं और बच्चे जो हासिल कर सकते हैं उससे परिसीमित कर देते हैं। शैशव काल के दौरान आहार की कमी (भूख) के कारण होने वाली क्षति अपूरणीय होती है। जो वैश्विक स्तर पर निरंतर मानव की संभाव्यताओं (क्षमता) को नष्ट कर रही है।

बच्चों के बीच व्यापक स्वास्थ्य परिस्थितियों को बच्चों की मृत्युदर को देखकर मापा जा सकता है। मृत्युदर में गिरावट आ रही है जोकि वर्ष 2008 में 8.8 मिलियन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतें थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1990 में यह 12.5 मिलियन बच्चे थी। अभी तक उच्च बाल मृत्यु वाले 68 देशों में केवल उन्नीस देश सही रास्ते पर है जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एम डी जी) की दिशा में वर्ष 1990 से 2015 तक दो तिहाई कमी की उपलब्धि के लिए लक्षित है। कुपोषण अकेले ही प्रत्यक्ष रूप से 3 मिलियन बच्चों एवं 100,000/– माताओं को मौत के घेरे में लाया है।

शैशव कालीन कुपोषण के दुष्परिणामों को सरकारें सदैव कम आकलित करती रही है। विकासशील देशों के लगभग 195 मिलियन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, विश्व के कुल बच्चों में से एक तिहाई, भोजन की कमी के कारण बौनेपन अथवा आयु के हिसाब से लंबाई की कमी से जूझ रहे हैं जो उनके खराब पोषण का संकेत है। बहुत सारे बच्चों ने अपने जीवन के पहले कुछ सालों में गंभीर कुपोषण की कमी अनुभव की होगी। कुपोषण मानवीय (जीवन) कष्ट के साथ–साथ शिक्षा प्रणाली पर भी भारी बोझ डालता है। कुपोषित बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से अपनी पूर्ण संभाव्यता (क्षमता) पर नहीं पहुंच पाते हैं। वे संभवतः स्कूल भी कम जा पाते हैं और यदि एक बार स्कूल में प्रवेश भी पा जाते हैं तो अधिगम उपलब्धियां भी निचले स्तर की होती हैं। कुपोषण के लिए आर्थिक वृद्धि रामबाण (अचूक औषधि) नहीं होती। मध्य 1990 दशक से अब भारत ने लगभग दो गुना औसत आय पा ली है, जबकि कुपोषण में केवल कुछ प्रतिशत की कमी आई है। लगभग देश के आधे बच्चे गंभीर कुपोषित हैं तथा उपसहारा अफ्रीका हेतु ऊंचाई (लंबाई) के समानुपातिक भार में दो गुनी कमी है।

अब अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में बाल एवं मातृ स्वास्थ्य अधिक प्राथमिक स्थान पर है। पोषण, शिशु उत्तरजीविता, मातृत्व स्वास्थ्य बेहतरी आदि के वैश्विक प्रयास को 2009 में जी–8 सम्मेलन तथा 2010 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के सम्मेलन में स्वागत किया गया। हालांकि, वर्तमान एप्रोच (उपागम) से उत्प्रेरक भूमिका को पहचानने में असफल रहे, जिसमें शिक्षा विशेष रूप से मातृक या मातृवशीय शिक्षा–स्वास्थ्य लक्ष्य की दिशा में होनेवाली प्रगति में भूमिका निभा सकती है।

लड़कों एवं लड़कियों के लिए शिक्षा में समान व्यवहार एक मानव अधिकार है और साथ ही अन्य क्षेत्रों में लाभों को मुक्त करने का साधन भी है। शिक्षा बाल एवं मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, क्योंकि यह स्त्रियों को कुपोषण एवं बीमारियों के बारे में सूचना प्रक्रिया से संसाधित करती है और उन्हें अपने जीवन में चुनाव (विकल्प) करने एवं व्यापक नियंत्रण का मौका देती है।

पारिवारिक सर्वेक्षणों के परिणाम निरंतर संकेत देते हैं कि बच्चों की उत्तरजीविता के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव डालने वाला मातृक शिक्षा एक सुदृढ़तम घटक है। यदि उपसहारा अफ्रीकी देशों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त औरतों द्वारा बच्चे पैदा किए जाते तो औसत बाल मृत्यु में कमी आई होती और वहां पर 1.8 मिलियन कम बाल मृत्यु होती अर्थात् 41% की कमी होती (देखें चित्र–1)। केन्या

उप सहारा अफ्रीकी देशों में शिक्षा 1.8 मिलियन जिंदगियों को मृत्यु से बचा सकती थी

चित्र 1: शिक्षा लाभांश 1.8 मिलियन जीवन बचा सकता था
विभिन्न मातृत्व शिक्षा के अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु की मौतों की अनुमानित संख्या, उपसहारा अफ्रीका 2003–2008 में पूर्वानुमान

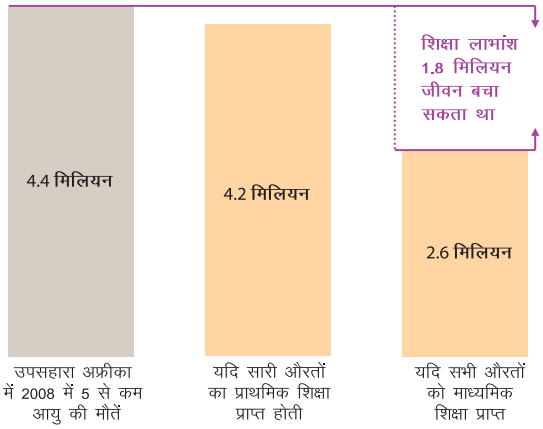

स्रोतः देखें चित्र 1.7, 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

में, जो बच्चे उन माताओं से पैदा हुए, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा नहीं पूरी की थी, उन माताओं, जिन्होंने माध्यमिक या उच्च शिक्षा पाई थी, की तुलना में उनके बच्चो की पांच वर्ष की आयु से पहले संभवतः दो गुनी मौतें हुईं।

बच्चों के लिए जीवन घातक स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ मातृक शिक्षा एक उच्च प्रभावी टीका है

2011 की *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* मातृत्व स्वास्थ्य के साथ जुड़े स्वास्थ्य लाभों पर प्रभावशाली नए साक्ष्य को उपलब्ध कराती है। पारिवारिक सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह पाया गया कि बहुत सारे देशो में, जो माताएं अधिक शिक्षित हैं, उन्हें काफी हद तक पता है कि मां के स्तनपान से शिशु में एचआईवी संचारित हो सकता है और यह कि गर्भावस्था के दौरान दवाएं लेकर मां से शिशु में एचआईवी संचार को कम किया जा सकता है। मलावी में, 60% वे माताएं, जो माध्यमिक या उच्च शिक्षित थी, उन्हें ज्ञात था कि दवाएं मां से शिशु में एचआईवी संचार को रोक सकती हैं, जबकि इसकी तुलना में केवल 27% शिक्षाहीन महिलाओं को ज्ञात था।

इस प्रकार के प्रमाण या साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि बच्चों के लिए जीवन घातक स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ मातृक शिक्षा एक उच्च प्रभावी टीका है। वर्ष 2009 में यूएनएड्स ने अनुमानित किया कि 15 वर्ष से कम आयु के लगभग 370,000 बच्चे एचआईवी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर वे बच्चे हैं जो एचआईवी धनात्मक माताओं से शिशु जन्म या गर्भावस्था में अथवा स्तनपान से एचआईवी के संपर्क में आए। इस रिपोर्ट के साक्ष्य यह सुझाते हैं कि इनमें से बहुत सारे संक्रमणों को औरतों को शिक्षित करके रोका जा सकता था (चित्र–2)।

चित्र 2: मातृ शिक्षा जीवन बचाती हैं।

आश्चर्यजनक नया उपचार मां से अजन्मे शिशु में एचआईवी संचार को कम कर सकता है, जोकि वर्तमान में प्रतिवर्ष 370,000 बच्चों को संक्रमित करता है।

इसे मातृत्व शिक्षा कहते है

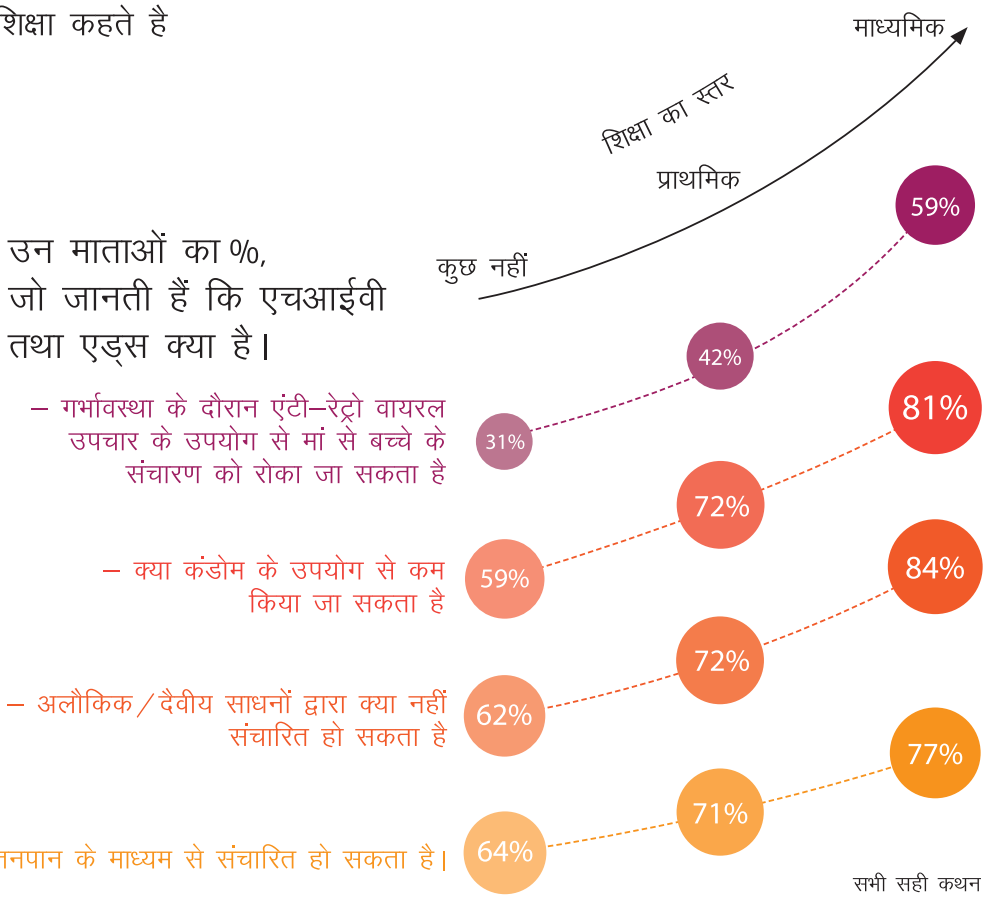

स्रोतः देखें चित्र 1.9. 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

शैशवकालीन कार्यक्रम बच्चों को स्कूल जाने, पारिवारिक हानियों के प्रभाव को न्युनीकृत करने, अभिभावकों से बच्चों में स्थानांतरित होने वाली शैक्षिक प्रतिकूलताओं को रोकने तथा आर्थिक वृद्धि के लिए परिदृश्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार करते हैं। अभी तक बहुत सारे विकासशील देशों में शैशव कालीन नीतियां लगातार निधियों की कमी, विखंडित नियोजन एवं असमानता से आक्रांतित हैं।

सर्वाधिक सुविधाहीन परिवारों के बच्चों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से अधिकाधिक लाभ पाना चाहिए, किन्तु ये प्रायः बहुत कम प्रतिनिधित्व पाते हैं। कोट डि आइवोरि में एक चौथाई बच्चे समृद्ध घरों के पूर्व विद्यालयों में भाग लेते हैं; जबकि गरीबतम परिवारों के बच्चे न के बराबर भाग लेते हैं। मोजांबिक जैसे देशों ने यह प्रदर्शित किया है कि साम्यता के लिए एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता अत्यंत साधन हीन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पूर्व–प्राथमिक स्कूलों के द्वारा खोल सकती है। (बाक्स–1)।

बाक्स 1: मोजांबिक का पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) लक्षित कार्यक्रम

मोजांबिक में इस्कोलिनहास् पूर्व स्कूली कार्यक्रम को 3 से 5 वर्ष आयु के सुकुमार बच्चों जोकि गरीबी युक्त या एचआईवी युक्त विशेष लक्षित जीवन वाले हैं, के लिए चलाया गया है। सामुदायिक स्वयं सेवियों के साथ प्रति कक्षा से दो शिक्षक खेलों, कला, संगीत का उपयोग करते हुए सहजात उत्प्रेरणों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आधारभूत नर्सरी एवं पाठन कौशल विकसित करते हैं। इस कार्यक्रम में अभिभावकों हेतु स्वास्थ्य, पोषण निर्देश एवं समर्थन समाहित होता है। यह उच्च गुणवत्ता एवं निम्न लागत की सेवाएं उपलब्ध कराता है जिसमें यह संभावित क्षमता है कि अन्य देशों में अपनाया जा सकता है।

स्रोतः देखें बाक्स–13, 2010 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट में।*

सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षाः चूक रहे लक्ष्य

पिछले दशक ने प्राथमिक स्कूलों में भर्ती (पंजीयन) में सुस्पष्ट अग्रिमताएं देखी है। बहुत सारे देश, जिन्होंने उक्त प्रवृत्ति के साथ दशक की शुरूआत की थी वे वर्ष 2015 तक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य से काफी पीछे छूट जाएंगे, लेकिन अब लक्ष्य की प्राप्ति का वास्तविक परिदृश्य सामने है। हालांकि अग्रिमता की गति असमान है और शायद धीमी पड़ रही है। वर्तमान प्रवृत्ति से कार्यवाही हेतु डाकार रूपरेखा के पारिभाषित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को विश्व नहीं प्राप्त कर पाएगा।

जब रूपरेखा (फ्रेमवर्क) को अपनाया गया था, तब लगभग 106 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर थे। वर्ष 2008 तक यह आंकड़े गिरकर 67 मिलियन तक आ गए। भारत में एक सुदृढ़ अग्रक अभियान के साथ, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया ने स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या को आधा कर लिया। उप सहारा अफ्रीका ने भी स्कूली आयु के बच्चों में भारी वृद्धि के बावजूद स्कूलों में पंजीकरण (भर्ती) अनुपात लगभग एक तिहाई बढ़ा लिया है। उप सहारा अफ्रीका में लगभग 43% स्कूल से बाहर के बच्चे रहते हैं और अन्य 27% दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में रहते हैं और लगभग आधे 15 देशों में रहते हैं (चित्र 3)। अनेक देशों ने स्कूल से बाहर बच्चों की कमी में नाटकीय कमी दर्ज कराई है। वर्ष 1999 से 2008 तक, इथोपिया ने स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों में लगभग 4 मिलियन की कमी की है और वह अब वर्ष 2015 तक यूपीई अर्थात सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा

© ट्रिमोथीएलेन / एक्सीओम / एचओए / क्यू यू आई

अधर में जीवनः
नायसिंगपाड़ा शरर्णीशिविर
में बच्चे, भारत

प्राप्ति के वास्तविक संदर्श में हैं। अन्य देश, जिन्होंने एक निम्न आधार रेखा से शुरूआत की थी और एक लंबी यात्रा तय की, तथापि इनमें से अनेक 2015 तक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने से अभी भी कुछ पीछे हैं। उदाहरण के लिए, नाइजर ने एक दशक से कम अवधि में ही अपने पंजीयन की संख्या दो गुनी कर ली है।

यद्यपि उपलब्धियां प्रोत्साहक हैं, तथापि वर्ष 2015 तक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि हेतु विश्व सही पथ पर नहीं है। इस रिपोर्ट की विश्लेषण प्रवृत्तियाँ 128 देशों की पंजीयन (भर्ती) की प्रगति को अवलोकित करती है जहां स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 60% आती है। इसमें संदेश यह निकलता है कि पिछले दशक के उत्तरार्ध में स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या लगभग

वर्ष 2008 तक 67 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर थे

चित्र 3: विश्व के आधे स्कूल से बाहर के बच्चे केवल पन्द्रह देशों में रहते हैं।

चुने हुए देशों में, वर्ष 2008 में, प्राथमिक स्कूल आयु के स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या

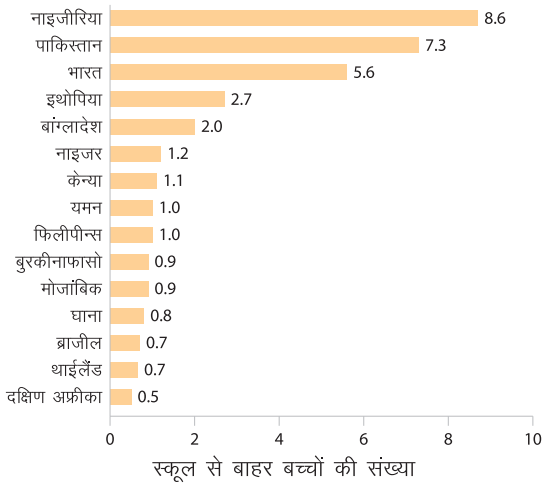

स्रोतः देखें चित्र 1.11. 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

आधी गिरावट आई, जोकि दशक के पूर्वार्ध में हासिल की गई थी। एक वैश्विक पैमाने के समायोजन पर, यदि यह प्रवृत्ति कायम रही तो वर्ष 2008 से कहीं अधिक वर्ष 2015 में 72 मिलियन से भी अधिक बच्चे स्कूल से बाहर होंगे।

शिक्षा में प्रगति को बढ़ाने में एक सबसे बड़ी बाधा विषमता या असमानता अभी भी शेष है (चित्र 4)। पाकिस्तान में, वर्ष 2007 में गरीबतम घरों के 7 से 16 वर्ष की आयु के लगभग आधे बच्चे स्कूल से बाहर थे, जबकि इसकी तुलना में समृद्ध घरों के 5% बच्चे स्कूल से बाहर थे। फिलीपींस एवं टर्की जैसे अनेक देश, जो सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति के करीब है, अंतिम चरण उठाने में असमर्थ है। व्यापक रूप से, गरीबतम एवं सीमांत (अति पिछड़ों) तक अपनी पहुंच बना पाने में असफल रहना एक कारण है। जेंडर (लिंग) भेद अभी भी गहनता से आबद्ध है (नीचे देखें)। हाल ही के वर्षों में सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट ने समानता आधारित लक्ष्य अपनाने के तर्क दिए हैं जिससे सरकारें न केवल राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिबद्ध हैं, बल्कि धन, क्षेत्र, मानवजातीय, लैंगिक आदि पर आधारित भेदभाव समाप्ति के लक्ष्य प्राप्त हों और प्रतिकूलता हेतु अन्य प्रतीक भी समाप्त हों।

उप सहारा अफ्रीका में, प्रत्येक वर्ष लगभग 10 मिलियन बच्चे प्राथमिक स्कूल छोड़ देते हैं

सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि हेतु स्कूल में प्रवेश पाना केवल एक शर्त है। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में भर्ती तो हो जाते हैं, परन्तु अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। उप सहारा अफ्रीका में, प्रत्येक वर्ष लगभग 10 मिलियन बच्चे प्राथमिक स्कूल छोड़ देते हैं। यह भारी मात्रा में कौशल एवं शिक्षा प्रणाली में असक्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। गरीबी एवं खराब शिक्षा की गुणवत्ता के साथ, बच्चे ग्रेड प्रोन्नति के अपेक्षित स्तर पर अधिगम प्राप्त करने में असफल रहते हैं और दोनों ही स्कूल छोड़ने के स्तर में भारी भागीदारी है।

चित्र 4: देश के अंतर्गत वृहत भिन्न–भिन्न स्कूल जाने के अवसर–पाकिस्तान का उदाहरण

2007, पाकिस्तान में स्कूल में 7–16 वर्ष के बिना नामांकन वाले बच्चों का प्रतिशत

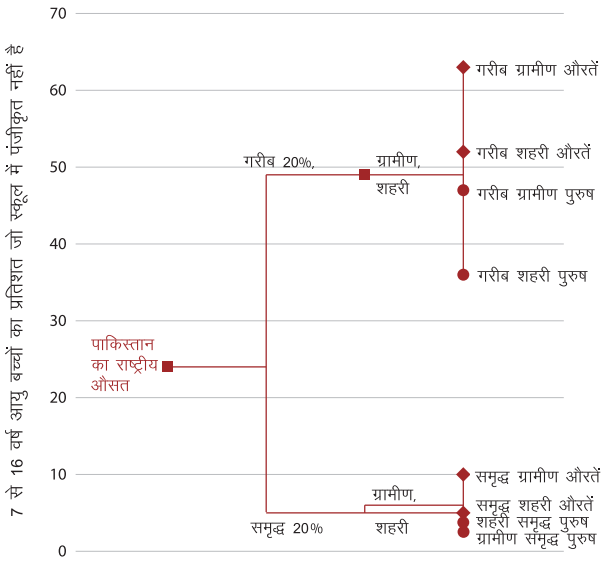

स्रोत: देखें चित्र 1.11. 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

बच्चों को स्कूल से बनाए रखने की बेहतरी हेतु देशों की विशिष्ट आवश्यकता पर आधारित रणनीतियां गठित करने की आवश्यकता है। इथोपिया, मलावी तथा फिलीपींस जैसे कुछ देशों में ग्रेड 1 में बच्चों को स्कूल छोड़ने की उच्च समस्या है जबकि यूगांडा में ग्रेड 1 एवं ग्रेड 6, दोनों मे समस्या उभरती है। स्कूलों में प्रवेश (पंजीयन) की तीव्र वृद्धि, जोकि प्रायः उपयोग शुल्क के हटाने से अनुपालित है, जो कक्षा की तेजी से बढ़ती भीड़ एवं खराब गुणवत्ता की शिक्षा का रूप ले सकती है। मलावी तथा यूगांडा शुरूआती कक्षाओं (ग्रेड) से उच्च कक्षाओं की ओर पंजीयन की प्रगति परिवर्तित कर पाने में संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त गणतंत्र तंजानिया ने क्रमबद्ध सुधारों के माध्यम से बेहतर नतीजे हासिल किए हैं, जिसने प्राथमिक कक्षाओं के अनुभवी एवं बेहतर योग्य शिक्षकों में निवेश एवं आबंटन को बढ़ाया है। बच्चे जिस आयु में स्कूल के प्रारंभिक ग्रेड में प्रवेश पाते हैं, वह भी काफी मायने रखती है। देर से अधिक आयु के बच्चों की भर्ती सुदृढ़ रूप से बीच में स्कूल छोड़ने (ड्रापआउट) से संबद्ध है। कोलंबिया में, ग्रामीण स्कूली कार्यक्रम ने जो एक अन्य उपागम है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं औचित्य में सुधार के द्वारा स्कूल छोड़ने की दर को घटाया है।

इस रिपोर्ट ने अनेकों सफलतापूर्ण उपागमों को पहचाना है जिन्होंने सुरक्षा तंत्र एवं स्कूल की उपस्थिति के साथ नकदी हस्तांतरण को संबद्ध कर स्कूल बीच में छोड़ने की दर को कम किया है जोकि नाजुक/कमजोर एवं गरीब परिवारों को सूखा, बेरोजगारी, बीमारी जैसे आघातों में डटकर खड़े रहने के काबिल बनाता है। एक उदाहरण इथोपिया का प्रोडक्टिव सेफ्टी नेट कार्यक्रम है जो गरीब परिवारों को नकदी या खाद्यान्न हस्तांतरित कर अनेक अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल में अधिक दिनों तक रोकने में सक्षम बनाता है।

युवा एवं वयस्क अधिगम (शिक्षण): एक तीव्र बदलती दुनिया के लिए कौशल

डाकार में युवा लोगों की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए वचनबद्धता की गई थी कि एक निम्न स्तरीय विवरणों के साथ एक उच्च स्तर की महत्वाकांक्षा को संयुक्तीकृत किया जाए। प्रमात्रात्मक लक्ष्यों की अनुपस्थिति के कारण निगरानी प्रगति कठिन है।

जनसंख्या के भारी हिस्से के साथ, अधिकतर समृद्ध देश सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के करीब है। उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप में लगभग 70% तृतीयक स्तर तक प्रगति कर रहे हैं। जबकि परिदृश्य के दूसरे छोर पर उप सहारा अफ्रीका में माध्यमिक स्तर पर सकल पंजीयन का अनुपात केवल 34% तथा तृतीयक स्तर की प्रगति केवल 6% है। हालांकि, इस क्षेत्र ने 1999 से बहुत ही निम्न बिन्दु से इस दिशा की ओर शुरूआत की थी। इथोपिया एवं यूगांडा में पंजीयन दो गुने से अधिक तथा मोजांबिक में चार गुना है। पूरे विकासशील देशों में प्राथमिक स्कूल में पंजीयन के अनुपात में वृद्धि हुई है और माध्यमिक स्तर की मांग बढ़ रही है। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के पंजीयन में भी वृद्धि हुई, यद्यपि आंकड़ों की कृत्रिमता पूरे क्षेत्र में तुलनात्मकता दिखा पाने में असमर्थ है। स्कूल छोड़ने वाले किशोरों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन वर्ष 2008 में वे अभी भी दुनिया भर में लगभग 74 मिलियन है।

देशों में असमानता माध्यमिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय विभाजन का दर्पण है। कक्षाओं में उपस्थिति एवं शिक्षा पूर्णतः की दर सुदृढ़ तौर से समृद्धि, स्थैतिकी, मानवजातीयता, लैंगिक (जैंडर) तथा उन अन्य घटकों से संबंधित हैं, जो पिछड़ेपन को बढ़ावा देते हैं। कोलंबिया में 23 से 27 आयु श्रेणी के 28% लोग 20% समृद्ध परिवारों से संबद्ध हैं, उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की है, जबकि इसकी तुलना में गरीब परिवारों के केवल 0.2% बच्चे माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं। दूसरा अवसर कार्यक्रम के माध्यम से, जिन युवा लोगों ने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की थी, वे अपने जीवनयापन के लिए चयन/विकल्पों को विस्तारित करने के लिए आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लैटिन अमेरिका में, जोवनेस प्रोग्राम एक सफलतापूर्ण मॉडल है जो निम्न आय परिवारों को लक्षित है जिसमें तकनीकी एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण का संयोजन है। मूल्यांकनों से स्पष्ट हुआ है कि रोजगार एवं कमाई के अवसरों में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है।

यद्यपि अधिकतर विकसित देशों में, उच्च स्तर पर माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर में पंजीयन हुए है तथापि वे भी असमानता एवं न्युनीकरण (सीमांतीकरण) से संबद्ध समस्याओं को झेल रहे हैं। ओईसीडी देशों में लगभग हर पांच में से एक उच्च माध्यमिक शिक्षा में पहुंच पाने में असफल रहते हैं। शिक्षा अधूरी छोड़ने के अंतर्गत गरीबी, अभिभावकों की निम्न स्तरीय शिक्षा एवं आव्रजन स्थिति आदि जोखिम घटक हैं।

बढ़ती हुई युवा बेरोजगारी, जिसे वैश्विक वित्तीय संकट ने और भी अधिक तीव्रता से बढ़ाया है, ने अनेकों ओईसीडी देशों को उत्प्रेरित किया है कि कौशल विकास हेतु व्यापक प्राथमिकता को जोड़ दें। यूनाइटेड किंगडम 2008 शिक्षा एवं कौशल अधिनियम ने 18 वर्ष से कम आयु के सभी लोगों के लिए शिक्षा एवं कौशल को अनिवार्य बना दिया है, जिसके साथ पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक शिक्षा के विकल्प अप्रेंटिसशिप एवं कंपनी आधारित कौशल आदि के विकल्प भी है। द्वितीय–अवसर (सेकेंड–चांस) या मौके का उद्देश्य युवा लोगों को निम्न कौशल के साथ शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि को भी सुदृढ़ बनाना है। यद्यपि इस क्षेत्र के कार्यक्रमों का एक संयुक्त रिकार्ड है। कुछ एक ने बहुत ही प्रभावशाली नतीजे प्राप्त किए है। यूनाइटेड स्टेट्स के सामुदायिक कालेज तथा यूरोपियन संघ देशों में सेकेंड–चांस प्रोग्राम ने असुविधाग्रस्त लोगों (पिछड़ों) तक पहुंचने का एक सुदृष्ढ़ ट्रैक रिकार्ड कायम किया है।

वयस्क साक्षरता: राजनीतिक उपेक्षा ने प्रगति को पीछे धकेला

साक्षरता बेहतर जीवनयापन, बेहतर स्वास्थ्य एवं व्यापक मौकों के द्वार खोलती है। कार्यवाही हेतु डाकार रूपरेखा (डाकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन) के अंतर्गत वयस्क साक्षरता के लिए एक विशिष्ट लक्षित कार्यक्रम भी शामिल है जिसके तहत 2015 तक वयस्क साक्षरता में 50% सुधार लाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2008 में, ठीक 796 मिलियन वयस्क मूलभूत साक्षरता कौशल से रहित थे जोकि विश्व भर के वयस्क जनसंख्या का लगभग 17% हिस्सा हैं। इनमें से लगभग दो तिहाई हिस्सा औरतों का है। इनकी भारी बहुतायत दक्षिण एवं पश्चिम एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में है, यद्यपि अरब देशों ने उच्च स्तर की वयस्क साक्षरता को दर्ज किया है।

केवल 10 देशों में विश्व की 72% निरक्षर वयस्कों की संख्या रहती है (चित्र 5) इन देशों में निष्पादकता समिश्रित है। वर्ष 2000 से 2007 तक ब्राजील 2.8 मिलियन निरक्षर वयस्कों की जनसंख्या को घटाने में सक्षम रहा और चीन ने भी सार्वजनिक वयस्क साक्षरता की दिशा में अच्छी प्रगति की है। भारत में साक्षरता दर बढ़ रही है। लेकिन इतनी तेज गति से नहीं कि पिछले दशक के पूर्वार्ध की 11 मिलियन निरक्षर वयस्कों की संख्या को रोक सके। नाइजीरिया एवं पाकिस्तान दोनों ही ने धीमी प्रगति दर्ज की है।

प्रवृत्ति विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 2000 में डाकार में की गई प्रतिबद्धता और उसके बाद प्रगति की रफ्तार के बीच विचारणीय अंतराल है। कुछ देश विशाल निरक्षर जनसंख्या के बावजूद, विएतनाम एवं चीन सहित, प्रतिबद्धता को पूरा करने के सही पथ पर हैं। लेकिन प्रगति की वर्तमान दर से, अन्य प्रमुख देश, जिनके पास महत्वपूर्ण रूप से विश्व की भारी निरक्षर जनसंख्या है, इसे दूर कर पाने में असफल रहेंगे। बांग्लादेश और भारत वर्ष 2015 तक लक्ष्य का आधे से ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जबकि अंगोला, चाड तथा जनतांत्रिक गणतंत्र कांगो तो इससे भी कम लक्ष्य पाने में असफल रहेंगे।

साक्षरता में धीमी प्रगति के लिए व्यापक रूप से राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी को एक बड़े कारण के रूप में उद्धृत किया गया है जो कि अभी तक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पिछले दशक की तुलना में थोड़े–बहुत सार्थक बदलाव आए हैं। साक्षरता सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की कार्यसूची में कहीं दर्शित नहीं होती है एवं न ही यूनाइटेड नेशंस लिटरेसी डिकेड (2005–2012) में महत्वपूर्ण रूप से इस समस्या के प्रति जागरूकता दिखाई गई और न ही इसमें कार्यवाही के ऊपर कलई चढ़ाई गई है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विचारों का आदान–प्रदान किया गया तथा संवादों का व्यापक आदान–प्रदान हुए, लेकिन कार्यवाही के लिए प्रतिष्ठित मंच स्थापित करने में असफल रहे। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णायक चैंपियन नेतृत्व भी मौजूद नहीं है।

जब राजनीतिक नेता साक्षरता से निपटने की आवश्यकता अभिस्वीकृत करते हैं तो सहज प्रगति संभव हैं। 1990 दशक के उत्तरार्ध से लैटिन अमेरिका और कैरीबियन देशों ने वयस्क

वर्ष 2008 में, ठीक 796 मिलियन वयस्क मूलभूत साक्षरता कौशल से रहित थे जोकि विश्व भर के वयस्क जनसंख्या का लगभग 17% हिस्सा हैं

चित्र 5: अधिकांश निरक्षर वयस्क दस देशों में रहते हैं।
2005–2008, चुने हुए देशों में, निरक्षर वयस्कों की संख्या

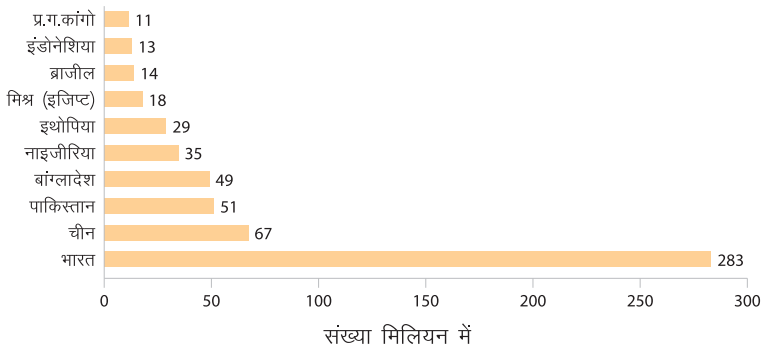

स्रोत: देखें चित्र 1.29 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

साक्षरता पर बल देना प्रारंभ कर दिया है। साक्षरता के लिए द आइबेरो–अमेरिकन प्लान एंड युवाओं एवं वयस्कों के लिए मूलभूत शिक्षा (पी आइ ए) ने वर्ष 2015 तक वयस्क निरक्षरता के उन्मूलन हेतु एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित किया है। प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ बोल्विया, क्युबा तथा निकारागुआ जैसे राष्ट्रों सहित कई देशों ने अपने यहां नवाचारी कार्यक्रम तैयार किए हैं। पी आई ए का उद्देश्य है कि 34 मिलियन निरक्षर वयस्कों को तीन वर्ष की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। इसके साथ ही, 110 मिलियन कार्यशील निरक्षरों को भी समर्थन हेतु सक्षम है जो अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाए थे।

साक्षरता में एक भेदन हेतु राष्ट्रीय सरकारों को जरूरत होगी कि नियोजन, वित्त सहायता में एवं हस्तगत कराने के लिए और अधिक जिम्मेदारी उठाएं, जिसके लिए व्यापक दायरे के माध्यम से काम करना होगा। जब ऐसा होता है तो लाभ त्वरित हो सकता है। मिश्र (ईजिप्ट) द्वारा प्राप्त प्रगति, मध्य 1990 दशक के दौरान जनरल अथॉरिटी फार लिटरेसी एंड एडल्ट एजूकेशन के गठन के बाद यह रूपरेखा तैयार की गयी कि कैसे संयुक्त रणनीतियों के माध्यम से उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, जिसके तहत साक्षरता अनुदेशकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण, प्रभावी लक्ष्य भेदन तथा जेंडर समानता की प्रतिबद्धता समन्वित है।

लिंग साम्यता एवं समानता: पार पाने हेतु अलाम की धारा

शिक्षा में लिंग साम्यता एक मानव अधिकार है, समान सुअवसरों की नींव एवं आर्थिक वृद्धि, रोजगार जनन एवं उत्पादकता का एक स्रोत है। जो देश उच्च लिंग भेदभाव के सहन कर रहे हैं वे लड़कियों एवं औरतों की मानवीय क्षमताओं के न्यून आकलन की भारी कीमत चुका रहे हैं और अपनी रचनात्मकता को मंद एवं अपने अरमानों (क्षितिज) को संकरा बना रहे हैं। हालांकि, लिंग साम्यता की दिशा में कुछ प्रगति हो चुकी है तथापि बहुत सारे गरीब देश नीतियों एवं शिक्षा की प्राथमिकताओं में आमूल बदलावों के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे।

यदि विश्व ने 2008 तक लिंग साम्यता प्राप्त कर ली होती तो 3.6 मिलियन अतिरिक्त लड़कियां स्कूल में होतीं

प्राथमिक स्कूल स्तर पर लिंग साम्यता की प्रगति लगातार गति पा रही है। वे क्षेत्र, जिन्होंने दशक की शुरूआत भारी लैंगिक असमानता के साथ प्रारंभ किया था– अरब राष्ट्र, दक्षिण एवं पश्चिम एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका आदि सभी ने प्रगति की है। लेकिन अभी भी बहुत लंबी दूरी तय करनी है उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। बावन देशों के आंकड़े हैं जिनके प्राथमिक स्कूल में लड़के एवं लड़कियों के अनुपात के लिंग साम्यता सूचकांक में मापा गया है जो 0.95 या कम है तथा 26 देशों में यह 0.90 या कम है। अफगानिस्तान ने प्रत्येक 100 लड़कों में 66 लड़कियां पंजीकृत हैं, वहीं सोमालियां में प्रति 100 लड़कों में 55 लड़कियां पंजीकृत है। यदि विश्व ने 2008 तक लिंग साम्यता प्राप्त कर ली होती तो 3.6 मिलियन अतिरिक्त लड़कियां स्कूल में होतीं।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा में लिंग साम्यता उच्च रूप से भिन्नता पूर्ण है। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में संयुक्त रूप से लड़कियों के पंजीकरण में भारी वृद्धि दर्ज की है जो लिंग साम्यता की दिशा में एक सुस्पष्टीकृत प्रगति है, जबकि उप सहारा अफ्रीका में माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों का पंजीयन स्पष्ट रूप से वृद्धि युक्त है, हालांकि एक निम्न आधार है क्योंकि साम्यता में सुधार नहीं हुआ है। वर्ष 2008 में, उप सहारा अफ्रीका के अनुकूल आंकड़ों सहित 24 देश तथा दक्षिण एशिया के तीन देशों में माध्यमिक स्कूलों में लिंग साम्यता सूचकांक (जी पी आई) पंजीयन 0.90 या कम था और दस का सूचकांक 0.70 या कम था। चाड में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पंजीयन दो गुना है और पाकिस्तान में हर चार लड़कों में तीन लड़कियां स्कूल में हैं। अरब राष्ट्रों में माध्यमिक स्कूलों में लिंग साम्यता की दिशा में प्रगति हुई है तथापि प्राथमिक स्तर की प्रगति से पीछे है। अनेक देशों में, माध्यमिक शिक्षा में लिंग साम्यता को प्राप्त करने के परिदृश्य अभी भी सीमित हैं यद्यपि व्यावहारिक नीतियों से समर्थित सुदृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता एक अंतर पैदा कर सकती है।

शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लैंगिक असंतुलन की खोज, उसकी उत्पति के बिन्दु नीतियों के सुधार में सहायक हो सकते हैं। बहुत सारे देशों में, भेदभाव की शुरूआत प्राथमिक शिक्षा की पहली कक्षा से हो जाती है। तीन चौथाई देश, जिन्होंने प्राथमिक स्तर पर लिंग साम्यता नहीं हासिल की है, वे प्राथमिक चक्र के प्रारंभ में लड़कियों से अधिक लड़कों के पंजीकृत करते हैं। माली में ग्रेड 1 में लड़कों के लिए 102% तथा लड़कियों के लिए 89% स्कूल भरती है। जब तक इस तरह का असंतुलन प्राथमिक स्तर पर (लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर को घटाकर) नहीं दूर किया जाएगा तब तक प्राथमिक प्रणाली में लैंगिक भेदभाव स्थाई परिणिति है, जोकि माध्यमिक शिक्षा में आपूर्ति का रूप लेता है।

जब बच्चे एक बार स्कूल में होते हैं, तो प्रोन्नयन प्रतिमान भिन्न होता है। बुरकीना फासो में, लगभग 70% लड़के एवं लड़कियां स्कूल के आखिरी ग्रेड (कक्षा) पहुंचने की थोड़ी ज्यादा संभावना होती है। इसलिए इन देशों, नीतियों को प्राथमिक भर्ती के दौरान बाधाओं को दूर करने में ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। गुइनिया में, इसके विपरीत स्कूल में लड़कियों की उत्तरजीविता की दर लड़कों की अपेक्षा कम है। जहां पर स्कूल बीच में छोड़ने की दर में लिंग–भेद है, वहां सरकारों को जरूरत है कि प्रोत्साहन पैदा करें जैसे कि नकदी हस्तांतरण या स्कूल में आहारपूर्ति कार्यक्रम, अभिभावकों के लिए प्रोत्साहन, ताकि बच्चों को स्कूल में रखें।

अधिकतर मामलों में, माध्यमिक शिक्षा में लिंग भेदभाव वापस प्राथमिक स्कूल में ढूंढने योग्य है। अधिकतर देशों में, जहां लड़कियां अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करती हैं उनके माध्यमिक शिक्षा में अंतरण के अवसर लड़कों के समान ही होते हैं। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा बीच में छूटने की संभावना अधिक होती है। बांग्लादेश में, प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के अंतरण में लड़कियों के पक्ष में बहुत कम भेदभाव होता है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा पूरा करने की दर लड़कियों की 15% की तुलना में लड़कों का प्रतिशत दर 23% होता है।

प्रतिकूल परिस्थितियां तथा लिंग भेद को महत्व देने वाले घटक समृद्धि, स्थैतिकी, भाषा से जुड़े होते हैं। यद्यपि समृद्ध घरों के लड़कों एवं लड़कियों के बीच स्कूल में उपस्थिति के बीच प्रायः छोटा अंतर होता है जबकि गरीब परिवारों, ग्रामीण या मानव जातीय अल्प संख्यकों के

लड़कों एवं लड़कियां विशिष्ट रूप से पीछे छूट जाते हैं। पाकिस्तान में, 17 से 22 आयु वर्ष की औरतें औसतन स्कूल में पांच साल बिताती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब घरों की औरतों के लिए यह संख्या केवल एक साल तक घटकर आ जाती है जबकि शहर में समृद्ध घरों की औरतें औसतन शिक्षा में 9 वर्ष बिताती है।

औरतें लगातार वेतन/मेहनताने एवं रोजगार अवसरों में उच्च स्तरीय प्रतिकूलता को झेलती हैं। इस वापस प्राप्ति की मंदता को वे शिक्षा से जनित कर सकती हैं। ठीक इसी समय पर, शिक्षा बाजार की प्रतिकूलताओं को तोड़ने में एक भूमिका निभा सकती है। लड़कियों की शिक्षा हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों को प्रस्तावित करने वाली व्यापक नीतियों में, लड़की शिक्षा मैत्री स्कूलों, माहौल का विकास, तकनीकियों एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों हेतु पहुंच में सुधार तथा अनौपचारिक शिक्षा से उन लिंग प्रतिकूलताओं से उबरा जा सकता है जो औरतों को कौशल विकसित करने से सीमित कर देती है। बांग्लादेश में, बी आर ए सी (ब्रेकस) रोजगार एवं जीवन यापन किशोर केन्द्र का उद्देश्य युवा औरतों में कौशल विकास तथा आत्मविश्वास पैदा करना है।

बाक्स 2: लड़कियों एवं औरतों का मददगार बी आर ए सी

वर्ष 2009 में लगभग 21,000 ब्रैक्स रोजगार एवं जीवनयापन किशोर केन्द्र लगभग 430,000 युवा औरतों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो समाजीकरण (मेल–जोल) के लिए एक जगह पर एकत्र हो सकती हैं, अपने साक्षरता कौशल को बनाए रखती हैं, तथा परिवार के अंतर्गत लड़की की भूमिका एवं स्वास्थ्य, बाल विवाह पर चर्चा कर सकती हैं। इसके साथ ही केन्द्र आय जनन प्रशिक्षण देता है तथा एक बचत एवं एक लघु ऋण कार्यक्रम उन सदस्यों के लिए चलाता है जो अपना छोटा व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि केन्द्र सफलतापूर्वक सामाजिक गतिशीलता की जागरूकता कर रहा है तथा आय उत्पादक गतिविधियों में विनियोजित कर रहा है। इसकी सफलता को अनुपालित करते हुए इस मॉडल को अफगानिस्तान, सूडान, यूगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया जैसे देशों में अधिगृहीत किया गया है।

स्रोत: देखें बॉक्स 1.13, *वर्ष 2011 सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

शिक्षा की गुणवत्ता: असमानता की प्रगति को बाधित करती है

एक शिक्षा प्रणाली की परीक्षा यह है कि क्या यह युवा लोगों को उन कौशलों से युक्त बनाकर संसाधित करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर रही है जो उनके एक संरक्षित जीवन यापन को विकसित करने के लिए आवश्यक एवं सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में भागीदारी के लायक बनाती है। बहुत सारे देश इस परीक्षा में असफल रहे हैं और बहुत सारे छात्र स्कूल छोड़ने के समय सर्वाधिक मूलभूत एवं गणना के कौशल प्राप्ति से रहित होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अधिगम मूल्यांकन ने अधिगम उपलब्धि में सुस्पष्ट वैश्विक एवं राष्ट्रीय भेदभावों/असमानताओं को प्रकट किया है। वर्ष 2006 की अंतर्राष्ट्रीय पाठन साक्षरता अध्ययन में प्रगति (पी आई आर एल एस) 40 देशों में चार संकेतकों के खिलाफ ग्रेड–4 के छात्रों के पाठन कौशल को मूल्यांकित किया था। समृद्ध देशों, जैसे कि फ्रांस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में छात्रों ने संकेतकों के समतुल्य या उससे बढ़िया निष्पादन किया। जबकि इसके विपरीत मोरक्को एवं दक्षिण अफ्रीका जो कि दोनों मध्य आय वर्ग देश है, में 70% से अधिक छात्रों ने न्यूनतम संकेतकों पर नीचे ही निष्पादन किया।

बहुत सारे देशों में अपवाद स्वरूप अधिगम उपलब्धि का स्तर बहुत ही निम्न है (चित्र 6)। भारत में, 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण ने पाया कि 38% ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा चार के छात्र कक्षा 2 के लिए निर्मित पाठ्य पुस्तक ही पढ़ सकते थे। यहां तक कि स्कूल में आठ वर्ष बिताने के बावजूद 18% छात्र कक्षा दो की पुस्तक पढ़ने में असक्षम पाए गए। वर्ष 2007 में, शिक्षा की गुणवत्ता निगरानी हेतु दक्षिणी एवं पूर्वी अफ्रीका संकाय (एस ए सी एम ई क्यू) के मूल्यांकन ने निम्न आय देशों में अधिगम उपलब्धि की नितांत कमी पर प्रकाश डाला। मलावी और जांबिया में कक्षा 6 के एक तिहाई से अधिक छात्र किसी भी प्रकार की (उच्चारण) प्रवाह से पढ़ने में असमर्थ थे।

मलावी और जांबिया में कक्षा 6 के एक तिहाई से अधिक छात्र किसी भी प्रकार के प्रवाह (उच्चारण) से पढ़ने में असमर्थ थे

क्या अनेक देशों में तीव्र वृद्धि के पंजीयन (प्रवेश) ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता किया है? यह प्रश्न चल रही बहस का केन्द्र बिन्दु है। यहां पर यह भी सच है कि बहुत सारे नए प्रवेश स्कूलों में उन परिवारों के बच्चों के होते हैं जिन्हें बहुत ही उच्च स्तर की गरीबी, खराब पोषण तथा निम्न स्तर की अभिभावक शिक्षा के रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। ये सारी विशिष्टताएं निम्न (अधिगम) उपलब्धि से जुड़ी है। यह माना जा सकता है कि पंजीयन (प्रवेश) एवं अधिगम स्तर के बीच अनुचित हित लाभ या लेन–देन है। वास्तव में, साक्ष्य अनिश्चायक हैं। सैकमैक (एस ए सी एम ए सी) मूल्यांकन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अनेक देशों में ऐसा कोई अनुचित लेन–देन नहीं हुआ है। केन्या एवं जांबिया में, वर्ष 2000 एवं 2007 में भारी संख्या में पंजीयन हुए, लेकिन परीक्षण अंकों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। संयुक्त गणराज्य तंजानिया ने अधिगम के औसत स्तर पर एक सुधार दर्शाया है जबकि इसी दौरान प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का पंजीयन लगभग दो गुना हो गया।

अधिगम उपलब्धि माता पिता की समृद्धि एवं शिक्षा, भाषा, मानव जातीय एवं भौगोलिक स्थितियों जैसे घटकों से जुड़े हैं। बांग्लादेश में, उदाहरण के लिए, 80% छात्र कक्षा 5वीं की प्राथमिक शिक्षा विदाई परीक्षा

चित्र 6: उपसहारा अफ्रीका में पाठन कौशल व्यापक रूप से भिन्नतापूर्ण

पाठन के लिए सैकमैक कौशल गमनीय ग्रेड 6 के छात्रों का प्रतिशत

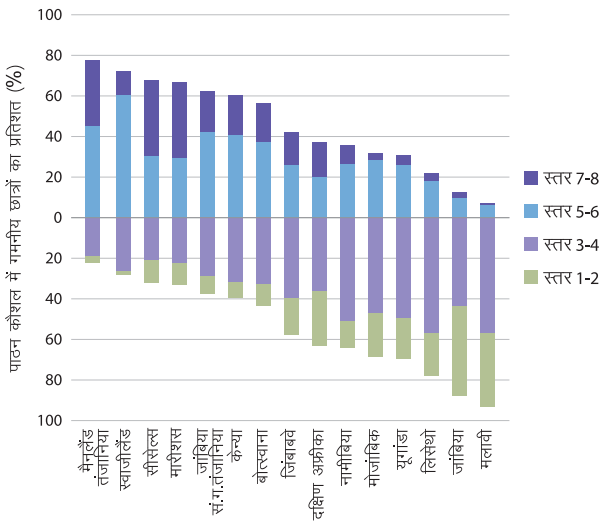

स्रोत: देखें चित्र 1.37 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

उत्तीर्ण की अगले ग्रेड पर जाते हैं। लेकिन वास्तव में बारीसाल उपजिले के सभी छात्र उत्तीर्ण हो गए, जबकि सिलहट उपजिला में आधे से कुछ अधिक छात्र ही उत्तीर्ण हुए। इसलिए, बांग्लादेश में एक बच्चा किस स्कूल में जाता है उसके राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अवसर स्पष्टतया महत्व रखते हैं। केन्या में, कक्षा 3 के आधे गरीबतम बच्चे मानक कक्षा 2 की किसवाहिली पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं अपेक्षाकृत दो तिहाई समृद्ध बच्चों के।

गरीबतम देशों की सरकारों को उनकी अपनी शिक्षा प्रणाली में अधिगम के औसत स्तर को ऊपर उठाने की अपरिमित चुनौती झेलनी पड़ रही है। वे नीतियां जो प्रणालीगत सुधार प्राप्ति करने के लिए छात्रों के बीच असमानता को घटाए बिना केन्द्रित है, वे संभवतः सफल नहीं होंगी।

स्कूलों की भरती में सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियों की एकाग्रता या सकेन्द्रकता स्कूलों की निष्पादकता के निम्न स्तर से सुदृढ़ता से संबद्ध हैं लेकिन स्कूल भी असमानता को पैदा करते हैं। अधिकतर देशों में, भिन्न समाज–आर्थिक वर्ग को स्कूलों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं महत्वपूर्ण रूप भिन्न होती है। इन भेदभावों को कम करने हेतु अधिगम के औसत स्तर को सुधारने एवं अधिगम असमानताओं को घटाने की दिशा में पहला चरण है। स्कूल की गुणवत्ता के बीच व्यापक भिन्नताएं तथा देश के अंतर्गत ही विभेद सार्वजनिक उपयोज्य पाठों को तैयार करना कठिन हो जाता है। हालांकि, कुछ घटकों को पहचानना संभव है जो एक देश के व्यापक परिधि में महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव को दर्शाते हैं।

यदि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना है तो वर्ष 2015 तक 1.9 मिलियन शिक्षकों को भर्ती करना होगा

- *शिक्षकों की संख्या:* सुयोग्य लोगों को शिक्षण व्यवसाय में आकर्षित करना, उन्हें रोककर रखना तथा आवश्यक कौशल एवं समर्थन को उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक वितरण प्रणाली शिक्षकों का वितरण कितनी समानता से कराता है और अधिक समान अधिगम परिणाम प्राप्त करने की एक कुंजी हैं। एक अन्य अत्यावश्यक संबद्धता भर्ती की है। यदि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना है तो वर्ष 2015 तक 1.9 मिलियन शिक्षकों को भर्ती करना होगा, जिनमें आधे से ज्यादा उप सहारा अफ्रीका में।

- *वास्तविक शिक्षण अवधि का महत्व:* शिक्षकों की अनुपस्थिति तथा सत्र के समय कार्य के अतिरिक्त बिताया समय महत्वपूर्ण रूप से अधिगम अवधि को कम करने के साथ–साथ अधिगम विषमताओं को भी व्यापक बनाता है। भारत के दो राज्यों में एक सर्वेक्षण ने पाया कि नियमित ग्रामीण शिक्षक औसतन हफ्ते में एक दिन अनुपस्थित रहते थे। शिक्षकों के रोजगार परिस्थितियों को संबोधित करने के साथ, स्कूल अभिशासन को मजबूत बनाने एवं उत्तरदेयता अधिगम उपलब्धियों को बढ़ा सकती हैं तथा असमानता को घटा सकती है।

- *प्रारंभिक कक्षाएं निर्णायक होती हैं:* जैसे–जैसे बच्चे शिक्षा प्रणाली के साथ प्रगति करते हैं, वैसे–वैसे कक्षा का आकार सिकुड़ता जाता है। बांग्लादेश में, सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा का आकार औसतन 30 से अधिक छात्र होते हैं। शिक्षण संसाधनों का सभी कक्षाओं में अधिक समान वितरण तथा एक वष्हत ध्यान केन्द्रण यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र साक्षरता एवं गणना जैसे निर्णायक आधारभूत कौशल प्राप्त करते हैं।

- *कक्षा का वातावरण महत्वपूर्ण है:* खराब ढंग से संसाधित कक्षा स्थल एवं पाठ्यपुस्तकों एवं लेखन सामग्री के बिना एक प्रभावी अधिगम प्रेरक नहीं होता है। मलावी में औसत प्राथमिक कक्षा का आकार 36 से लेकर 120 छात्र तक प्रति शिक्षक के दायरे में हो सकता है। केन्या में, अपनी गणित की पुस्तक के साथ बच्चों का समानुपात उत्तरपूर्वी राज्य में 8% से लेकर नैरोबी में 44% के दायरे में होता है।

प्रतिकूलताओं से निपटने की कार्यवाही जो अति पिछड़े (सीमांत) बच्चों को कक्षा तक ले आती है, उनके लिए स्कूलों को जरूरत है कि अतिरिक्त समर्थन उपलब्ध कराएं। जिसमें अतिरिक्त शिक्षण समय एवं संपूरक संसाधन शामिल हैं। अधिगम अंतराल को पाटने में सरकारी संसाधनों का आंबटन महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। भारत में, केन्द्र सरकार ने प्रति छात्र आबंटन को तत्वतः खराब शिक्षा संकेतक वाले जनपदों के हिसाब से बढ़ा दिया है। इस अतिरिक्त संसाधन ने अतिरिक्त शिक्षकों एवं आधारभूत संरचना में अंतर को भरने के लिए निधि प्रदान करने में सहायता की है। उपचारात्मक शिक्षा कार्यक्रम भी एक अंतर पैदा कर सकते हैं (बाक्स 3)। चिली में द प्रोग्राम डे लैस 900 इस्क्यूल्स द्वारा खराब निष्पादकता वाले स्कूलों को अधिगम बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शिक्षकों के कौशल सुधार हेतु साप्ताहिक कार्यशाला आयोजन, बच्चों के लिए स्कूल से बाहर कार्यशाला, पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सामग्री आदि भी शामिल है। इस कार्यक्रम ने कक्षा 4 के अधिगम स्तर को बेहतर बनाया है तथा अधिगम अंतराल को घटाया है। राष्ट्रीय अधिगम मूल्यांकन को भी निभाने के लिए एक भूमिका है। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक कक्षाओं का मूल्यांकन उन बच्चों को पहचान सकता है जो पढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं तथा उन स्कूलों एवं क्षेत्रों को भी पहचाना जा सकता है जिन्हें समर्थन की जरूरत है। अधिगम मूल्यांकन के परिणामों को अभिभावकों की पहुंच में लाने से, वे समुदायों को शिक्षा दाताओं को जिम्मेदार बनाने में मदद कर सकते हैं और शिक्षा दाताओं को निहित शिक्षा समस्याओं को समझने के लायक बना सकता है।

बाक्स 3: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रथम का बालसखी कार्यक्रम

प्रथम एक विशाल भारतीय गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य गरीब एवं नाजुक तबके के लोगों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसकी मौलिक उपचारात्मक शिक्षा कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के कक्षा 3 एवं 4 के छात्रों को लक्ष्य करता है जो फेल होकर पिछड़ जाते हैं। यह छात्रों को स्थानीय भर्ती शिक्षकों के द्वारा गणनात्मक एवं साक्षरता कौशल को सिखाता है जो दो हफ्तों का प्रशिक्षण एवं तदोपरांत सेवाकालीन समर्थन प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम के मूल्यांकन यह प्रकट करते हैं कि छात्रों की साक्षरता एवं गणना परीक्षा के अंकों में सुधार दर्शाते हैं तथा अधिगम अंतर को कम करते हैं। इसकी सफलता को संशोधित संस्करण के रूप भारत के उन्नीस राज्यों में रीड इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया गया है, जो 2008/2009 में अनुमानतः 33 मिलियन बच्चों तक पहुंच रहा है।

स्रोत: देखें बॉक्स 1.14, वर्ष 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

सबके लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायताः एक भेदन की तलाश

बढ़ी हुई वित्तीय सहायता शिक्षा में सफलता की गारंटी नहीं हैं, लेकिन चिरकालिक कम वित्तीय सहायता असफलता के पथ की गारंटी अवश्य है। कार्यवाही हेतु डाकार रूपरेखा ने वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ लक्ष्यों को समर्थित करने की महत्ता के पहचाना है। गमनीयता के रिकार्ड वैविध्यपूर्ण है। विश्व के अनेक गरीबतम देशों ने शिक्षा पर व्यय को बढ़ा दिया है, यद्यपि कुछ सरकारें अभी भी अपने राष्ट्रीय बजट में शिक्षा को बहुत कम प्राथमिकता देती हैं। तथापि सहायता स्तर में वृद्धि हुई है हालांकि दानदाता सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने हेतु अपनी शपथ को सम्मान देने में असफल रहे कि सबके लिए शिक्षा जो कोई भी देश गंभीरता से प्रतिबद्ध नहीं है और वे संसाधनों की कमी के कारण इस लक्ष्य के लिए अपनी उपलब्धियों को व्यर्थ न गवां दें। वर्ष 2015 से आगे को ध्यान में रखते हुए, यहां पर एक खतरा है कि वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के बाद, वह संकट और भी बढ़ गया जोकि पहले ही सबके लिए शिक्षा की आवश्यकताओं एवं वास्तविक वित्तीय प्रतिबद्धता के बीच अंतराल के रूप में था।

घरेलू वित्तीय सहायता बढ़ रही है, लेकिन इसमें पूरे देश एवं क्षेत्रों के अंतर्गत स्पष्ट विभेद हैं

यहां तक कि गरीबतम देश, घरेलू राजस्व एवं सरकारों द्वारा सार्वजनिक व्यय–न कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता–शिक्षा में निवेश की आधारशिला बनाती है। विश्व के अनेक गरीबतम देशों ने शिक्षा में अपना निवेश किया है। कम आय वाले देशों ने एक समूह के रूप में 1999 से अब तक 2.9% से 3.8% तक शिक्षा में व्यय बढ़ाया है। उप सहारा अफ्रीका के अनेक देशों ने अपनी राष्ट्रीय आय के एक बड़े हिस्से को विशेष रूप से शिक्षा के लिए वृद्धि की है जोकि 1999 से बुरूंडी में दो गुना तक है। एवं संयुक्त गणराज्य तंजानिया में तीन गुना है।

एक कम सकारात्मक नोट पर, कुछ अंचलों एवं देशों ने लगातार शिक्षा वित्त सहायता की उपेक्षा की है। विश्व अंचलों में मध्य एशिया, दक्षिण एवं पश्चिम एशिया ने शिक्षा में कम से कम निवेश किया गया है। सामान्य तौर पर सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा के लिए आबंटन में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन यह प्रतिमान अनियमित है। यद्यपि पाकिस्तान की प्राप्ति व्यक्ति आय ठीक वीएतनाम के समान है तथापि सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा के लिए आबंटन उससे ठीक आधा है। ठीक इसी प्रकार से सीरियन अरब रिपब्लिक के स्तर से फिलीपींस का आधे से भी कम आबंटन है।

कुल मिलाकर वित्तीय सहायता प्रवृत्तियां आर्थिक वृद्धि तथा आरक्षित (रिजर्व) संग्रह के स्तर एवं राष्ट्रीय बजट में (शिक्षा हेतु) आबंटित हिस्से से निदेशित होती है। अधिकतर विकासशील देशों में 1999 से 2008 तक सुदृढ़तर आर्थिक वृद्धि ने शिक्षा में निवेश को बढ़ाया है। आर्थिक वृद्धि को किस दर से शिक्षा व्यय में वृद्धि के रूप में परिवर्तित किया जाए, यह व्यापक सार्वजनिक व्यय निर्णयों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए घाना, मोजांबिक तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया ने शिक्षा पर व्यय में वृद्धि समृद्ध राजस्व संग्रह के द्वारा आर्थिक वृद्धि से कहीं अधिक गति से की, तथा राष्ट्रीय बजट में शिक्षा के अंश के आबंटन में वृद्धि की है। ठीक इसी प्रकार से अन्य कई देशों ने वृद्धि अधिमूल्य (बढ़ौती) के

पोर्ट औ प्रिंस में खुले आसमान में कक्षा, हैती शिक्षा प्रणाली संघर्षों के कारण पहले ही कमजोर पड़ चुकी है। जनवरी 2010 में भूकम्प द्वारा विनष्ट हो गई।

अंश शिक्षा के लिए बजट में आबंटन किया। फिलीपींस में; वर्ष 1999 से 2008 तक शिक्षा पर वास्तविक व्यय में वृद्धि 0.2% वार्षिक की दर से किया है जबकि अर्थव्यवस्था में 5% की वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप फिलीपींस के द्वारा राष्ट्रीय आय का निम्न भाग शिक्षा में निवेशित किए जाने से समय गुजरने के साथ वह नीचे आ गया। राष्ट्रीय संसाधन संग्रहण प्रयास सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य हेतु एक निर्णायक वहनीयता रखते हैं। संयुक्त गणराज्य तंजानिया में, बढ़ी हुई वित्तीय सहायता ने 1999 से अब तक 3 मिलियन स्कूल से बाहर बच्चों की जनसंख्या को घटाया है, जबकि बांग्लादेश में शिक्षा में पिछले दशक में एक बढ़िया निपटान प्राप्त किया है। इसकी प्रगति को निम्न स्तरीय राजस्व संग्रह तथा राष्ट्रीय बजट में शिक्षा के लिए न्युन हिस्से ने पीछे खींचा है।

गरीबतम देशों के लिए, यहां पर दोनों चरणों में ध्यान देने योग्य गुजाइंश है जो अपना संसाधन धन संग्रहण प्रयास को बढ़ाएं तथा प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर डालें। 2011 के लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट अनुमानित करती है कि वे घरेलू वित्त सहायता से प्राथमिक शिक्षा पर एक अन्य 7 बिलियन यूएस डालर खड़ा कर सकते हैं जो सकल राष्ट्रीय आय से कुल मिलाकर लगभग 0.7 अंश खींचना है।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता : अपनी बचनवद्धता से पीछे हटना

वर्ष 2002 से, कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षा, सहायता दो गुना हो गई है जो कुछ महत्वपूर्ण लाभों को हस्तगत करने में मददगार रही है। बांग्लादेश, कोलंबिया, इथोपिया, मोजांबिक, रवांडा, सेनेगल तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया सहित गरीब देशों में सहायता ने प्रगति को गति देने वाले कार्यक्रमों की नीतियों को समर्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि विकास सहायता की महत्ता या मूल्य पर सहायता निराशावादी प्रश्न खड़ा करते हैं तथापि परिणाम जमीन पर कुछ अधिक सकारात्मक कहानी बयान करते हैं। हालांकि, दानदाता अपनी उन वचनबद्धताओं से काफी पीछे रहे हैं जो वादे उन्होंने डाकार और बाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर किए थे।

कम आय वाले देशों ने एक समूह के रूप में 1999 से अब तक 2.9% से 3.8% तक शिक्षा में व्यय बढ़ाया है

शिक्षा हेतु सहायता कुल मिलाकर सहायता स्तर तथा व्यापक सहायता वातावरण से अपरिहार्य रूप से प्रभावित है। वर्ष 2005 में आठ के समूह और यूरोपियन यूनियन द्वारा वर्ष 2010 के लिए 50 बिलियन यू एस डालर की प्रतिज्ञा की गई थी जिसका आधा भाग स्पष्टतः उप सहारा अफ्रीका के लिए चिंहित था। अनुमानित प्रक्षेपित कमी 20 बिलियन यूएस डालर की गई जिसमें उप सहारा अफ्रीका के लिए 16 बिलियन यूएस डालर का लेखांकन था।

अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं विभिन्न मापदंडों के बारे में दानदाताओं के अस्थिर रिकार्ड हैं जोकि अपनाए गए जी–8 के अंतर्गत इटली, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र ने लगातार सकल राष्ट्रीय आय का बहुत कम स्तर शिक्षा सहायता में निवेशित किया। इटली ने 2009 में एक निम्न आधार से अपने व्यय में एक तिहाई की कटौती कर दी और यह प्रदर्शित किया और ईयू की अपनी प्रतिबद्धता से हट गया तथा सकल राष्ट्रीय आय स्तर का 0.51% न्यूनतम सहायता पहुंच गई। वित्तीय घाटे के दबाव ने सहायता की भावी दिशा के लिए अनिश्चय की स्थिति पैदा कर दी। हालांकि, अनेक दानदाता फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य सहित ने 2009 में अपनी सहायता व्यय में वृद्धि कर दी।

लगातार 5 साल तक धीरे–धीरे वृद्धि के उपरांत वर्ष 2008 में प्राथमिक शिक्षा सहायता 4.7 बिलियन यूएस डालर पर ठहर गई

सबके लिए शिक्षा कार्यसूची हेतु हाल ही में शिक्षा सहायता के आंकड़े एक चिंताजनक दिशा की ओर इंगित करते हैं। लगातार 5 साल तक धीरे–धीरे वृद्धि के उपरांत वर्ष 2008 में प्राथमिक शिक्षा सहायता उप सहारा अफ्रीका हेतु 4.7 बिलियन यूएस डालर पर ठहर गई (चित्र 7) जोकि सबके लिए शिक्षा हेतु सबसे बड़ा अंतराल वाला अंचल है तथा संवितरण 4% तक गिर गया जोकि प्राथमिक स्कूल आयु के प्रति बच्चे के हिसाब से 6% के बराबर है। एक वर्ष में सहायता की स्तर में कमी अपने आप में किसी प्रवृति का संकेत नहीं है; लेकिन यहां पर आत्म संतोष की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं हैं जैसा कि निम्न आय देशों के लिए सबके लिए शिक्षा लक्ष्य के अंतराल को पूरा करने के लिए 16 विलियन यूएस डालर आकलित किया गया है।

इस वित्तीय अंतराल के पैमाने को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकताओं के पुनर्विचार का एक स्पष्ट मामला है। यदि सभी दानदाता प्राथमिक शिक्षा हेतु अपनी सहायता का आधा व्यय करते हैं तो वे प्रतिवर्ष 1.7 मिलियन यू एस डालर संग्रहीत कर सकते हैं।

चित्र 7: 2008 में प्राथमिक शिक्षा में सहायता के संवितरण में वृद्धि रोकी गई

2002–2008, शिक्षा हेतु सहायता संवितरण

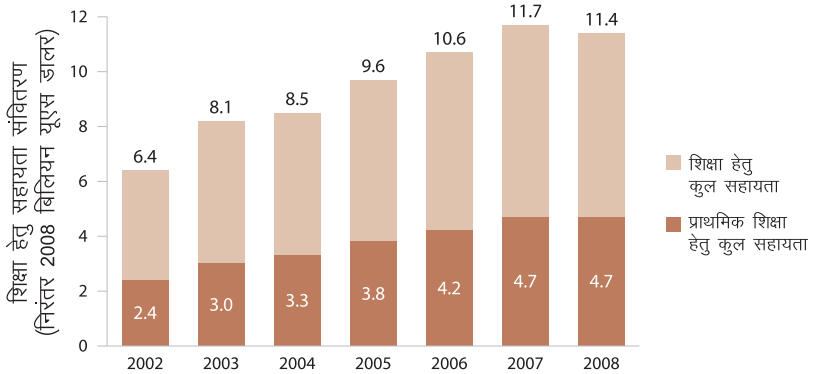

स्रोतः देखें चित्र 2.8, 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

हालांकि, यहां पर बहुत थोड़े साक्ष्य यह सुझाते हैं कि प्रमुख दानदाता प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च स्तरीय शिक्षा प्रावधान के बीच एक संतुलन पर पुनः विचार कर रहे हैं। जी–8 के अनेक प्रमुख दानदाता–फ्रांस, जर्मनी एवं जापान सहित अपनी शिक्षा सहायता का 70% से अधिक भाग प्राथमिक शिक्षोपरांत की शिक्षा हेतु आबंटित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एक व्यापक सहायता का समानुपात जो सहायता को थोपी गई सहायता के रूप में दिया जाता है। वास्तविकता में दानदाता देशों में ही शिक्षा संस्थानों हेतु संसाधन अंतरित हो जाते हैं। जर्मनी एवं फ्रांस में, शिक्षा हेतु सहायता का आधार भाग थोपी (आरोपित) लागत के रूप में होती है। परिणामस्वरूप कुछ विदेशी छात्र फ्रांस व जर्मनी में उच्च शिक्षा प्रणाली से लाभान्वित होते हैं। यह स्पष्ट रूप से गरीब देशों में शिक्षा प्रणाली के गहन वित्त अंतराल को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रमात्रा के परे देखते हुए, सहायता के प्रभावीपन की एक निरंतर संबद्धता रहती है। वर्ष 2007 में कुल सहायता का आधे से भी कम हिस्सा राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रणालित किया गया और पांच में से ठीक एक दानदाता द्वारा मिशन को समन्वित किया गया और उस वर्ष के लिए दी जाने वाली विकास सहायता का वास्तव में केवल 46% भाग ही संवितरित किया गया। यह नतीजे उस लक्ष्य स्तर से नीचे रहे जो सहायता प्रभावीपन पर दानदाताओं द्वारा पेरिस घोषणा के दौरान की गई थी। यहां पर शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए सहायता प्रतिबद्धता एवं संवितरण के बीच का अंतराल कक्षा भवन के निर्माण एवं शिक्षकों की भर्ती के क्षेत्र में नियोजन को हानि पहुंचाते हैं।

वित्तीय संकट – में पीड़ा युक्त समायोजन

सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के संकटों पर वैश्विक वित्तीय संकट का संघात लगातार दानदाताओं व अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा व्यापकता से उपेक्षित किया जा रहा है। बढ़ी हुई गरीबी एवं नाजुकता के सम्मुख और बढ़ते हुए वित्तीय घाटे के कारण राष्ट्रीय वित्तीय प्रयासों की बाधाओं के साथ जो कुछ उपलब्ध हो पाता है और उन्हें गतिशील प्रगति की नींव को यथा–स्थान पर रखने हेतु सहायता निर्णायक होती है।

2010 सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से अनुरोध करती है कि सबके लिए शिक्षा वित्तीय सहायता हेतु बजट समायोजित संबद्ध संकटों के निहितार्थों का मूल्यांकन करें। इसके साथ ही इस सूचना पर अद्यतन प्रकाश डालती है कि डाकार में निर्धारित लक्ष्य पर इन समायोजन के कारण वास्तव में कितनी खराब स्थिति है। यह तस्वीर बदली नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइ एम एफ) ने संकेत दिया है कि अधिकतर विकासशील देशों ने प्राथमिक मूल बजट सेवाओं के समर्थन में कमी नहीं की है। यह प्रोत्साहन युक्त हो सकता है कि यह इस बात को संबोधित नहीं करता है कि विनियोजित व्यय सुसंगत है या पूर्व संकट योजना है या सबके लिए शिक्षा वित्तीय सहायता की आवश्यकता के साथ है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट करने की प्रणाली बजट समायोजन के औचित्यपूर्ण मूल्यांकन को हानि पहुंचाता है।

हालांकि, समृद्ध देशों की बैंकिंग प्रणाली एवं विनियमन असफलता के कारण वित्तीय संकट पैदा हुआ, लेकिन इसके दुष्परिणामस्वरूप गरीब देशों के करोड़ों लोग इससे समन्वित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुस्त आर्थिक वृद्धि, उच्च खाद्यान्न मूल्यों के साथ एक दूसरे को काट रहे हैं, फलतः अतिरिक्त 64 मिलियन लोगों को घोर गरीबी में छोड़ दिया तथा वर्ष 2009 में 41 मिलियन अन्य कुपोषित जुड़ गए जो तुलनात्मक रूप से संकट के पूर्व की संख्या के अतिरिक्त है। अपरिहार्य रूप से शिक्षा के संदर्श परिणाम भुगतेंगे। यहां पर पहले ही इस बात के प्रमाण हैं कि परिवार के बजट में पड़ते भार के कारण बच्चों को स्कूल से हटा लेना एक अग्रणी कारण है। और इसके साथ ही बढ़ा हुआ कुपोषण भी बच्चों की स्कूल की उपस्थिति तथा अधिगम परिणामों को प्रभावित करेगा।

सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों की प्रगति की दिशा में वित्तीय घाटा का दबाव एक अन्य संकट है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की असफलता सबके लिए शिक्षा लक्ष्य हेतु वित्तीय घाटे के समायोजन के निहितार्थ मूल्यांकन अभी भी शेष चिंता का विषय है। इस समस्या का एक हिस्सा क्रमबद्ध बजट निगरानी का अभाव है। पूर्व रिपोर्ट हेतु आयोजित अनुसंधान की नींव पर 2011 सबके लिए शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ने यह प्रयास किया है कि अंशतः सूचना अंतराल को भरे। एक सर्वेक्षण के निष्कर्षानुसार जोकि 18 निम्न आय देशों को तथा 10 मध्य आय देशों को आवृत्त करता है, यह रिपोर्ट वर्ष 2009 के लिए वास्तविक व्यय तथा परिणामों के साथ 2010 के नियोजित व्यय का अवलोकन कर रही है।

- चाड, घाना, नाईजर तथा सेनेगल सहित सात निम्न आय देशों ने वर्ष 2009 में शिक्षा में कटौती की है। शिक्षा में कटौती वाले देशों से लगभग 3.7 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर थे।
- उपरोक्त सात में पांच निम्न आय देशों द्वारा वर्ष 2010 के लिए नियोजित व्यय उन्हें वर्ष 2008 के स्तर के शिक्षा के बजट से नीचे छोड़ देगा।
- हालांकि 7 निम्न मध्य आय देशों ने वर्ष 2009 में व्यय हेतु व्यय यथावत रखा या बढ़ाया है तथापि वर्ष 2010 के शिक्षा बजट में 6 नियोजित कटौतियां की गई हैं।
- वर्ष 2015 से आगे देखते हुए निम्न आय देशों के नियोजित वित्तीय घाटे यह मय पैदा करते है कि सबके लिए शिक्षा वित्तीय सहायता अंतराल और अधिक बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रक्षेपित संकेत दिया है वर्ष 2015 तक निम्न आय देशों की 6% औसत वार्षिक की दर से सार्वजनिक व्यय बढ रहा है, तथापि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति हेतु औसतन सार्वजनिक व्यय, लगभग 12% की दर से वृद्धि अपेक्षित है।

वित्तीय सहायता पर पांच संस्तुतियां

अगले पांच वर्षों हेतु राष्ट्रीय सरकारों तथा दानदाताओं के लिए वित्तीय सहायता वातावरण और भी कठिन होने की संभावना है जो कि यह पूर्व दशक में भी हो चुका है। वर्ष 2000 में स्थापित किए गए लक्ष्य हेतु एक बडे धक्के के लिए दृढ़ संकल्पित कार्रवाई की जरूरत होगी। यह रिपोर्ट पांच व्यापक उपागमों को अनुशंसित करती है।

- *वित्तीय संकट के आलोक में पुनर्मूल्यांकित वित्तीय सहायता की जरूरत है:* सबके लिए शिक्षा लक्ष्य हेतु नियोजन विस्तृत राष्ट्रीय अनुमानों पर आधारित होने चाहिए। सरकारों एवं यूएन एजेंसी के साथ काम करते हुए विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वर्तमान व्यय नियोजनों तथा सबके लिए शिक्षा हेतु अपेक्षित वित्तीय सहायता एवं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के साथ की आर्थिक कर्मियों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें इन वित्तीय आवश्यकताओं तथा वित्तीय (घाटा) समायोजन कार्यक्रमों के बीच पंक्तिबंधता को आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकित करना चाहिए।

शिक्षा में कटौती वाले देशों से लगभग 3.7 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर थे

चित्र 8: शिक्षा व्यय पर वित्तीय संकट का प्रभाव

2008–2010, चुने हुए निम्न एवं निम्न मध्य आय देशों में शिक्षा व्यय पर सूंचकांक

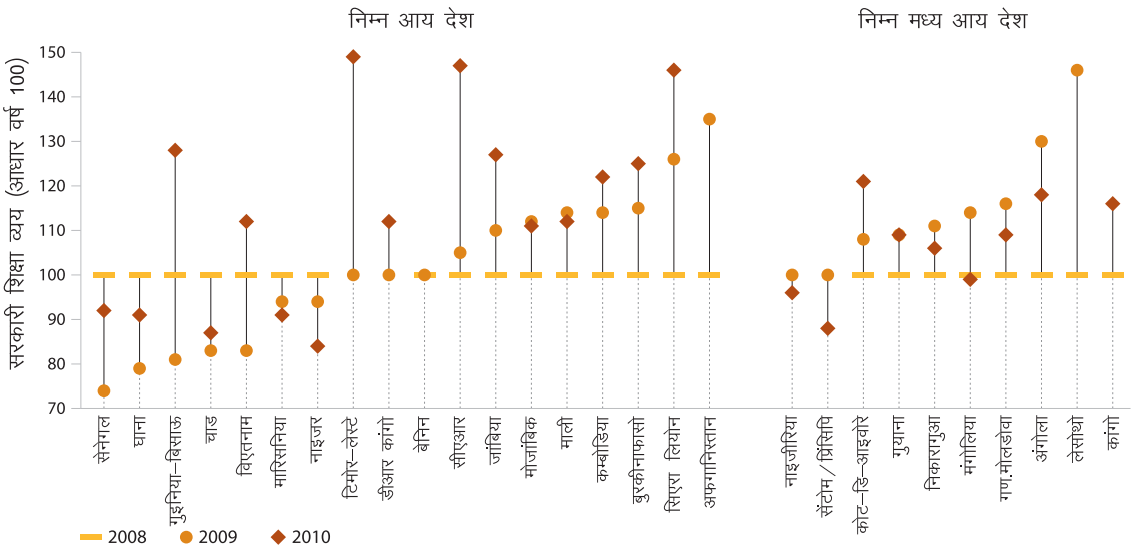

स्रोतः देखें चित्र 2.12. 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

दानदाता सरकारों को चाहिए कि वे वर्ष 2011 से 2015 प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 विलियन यूएस डालर राजस्व प्रणालन में करें

- *वर्ष 2005 की प्रतिबद्धता पर हस्तांतरण या सिपुदर्गी।* दानदाता सरकारों को वर्ष 2005 में की गई प्रतिबद्धता को निभाने के लिए तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए तथा वर्ष 2015 की अवधि के लिए नई वचन बद्धता करनी चाहिए। सभी दानदाताओं को सचल संकेतात्मक समयसारिणी स्थापित करनी चाहिए कि वे इन कमियों को कैसे पूरा करेंगे, जिसमें उप सहारा अफ्रीका के लिए पहले ही 16 विलियन यूएस डालर की कमी शामिल है।

- *प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता बनाएं।* दानदाता प्रायः विकास शील देशों की सरकारों के साथ जुड़ी सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकताओं के साथ उनकी सबके लिए शिक्षा के साथ जुड़ी प्रतिबद्धता की महत्ता को कम करके आंकते हैं। उन्हें एक समान सिद्धांत अवलोकित करने की आवश्यकता है। यदि सभी दानदाता अपनी सहायता का आधा हिस्सा भी शिक्षा पर खर्च करें (जोकि वर्तमान में औसतन 41% है) तो प्रतिवर्ष औसतन 1.7 विलियन यूएस डालर संग्रहण हो सकता है।

- *एक नया वैश्विक वित्तीय सहायता प्रयास का प्रारंभ* दि इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजूकेशन (आई एफ एफ ई)। सबके लिए शिक्षा साझेदारी को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है ताकि 2005 की प्रतिबद्धता पूरी हो और दानदाता प्राथमिक शिक्षा हेतु व्यापक प्राथमिकता जोड़े। यह प्रयास अभी भी बहुत कम और बहुत देर से सिपुर्द कर पा रहे है। आईएफएफ (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा) के तहत प्रतिरक्षीकरण में अग्रणी भारित व्ययों का उपयोग कर तथा लंबे समय तक ब्याज भुगतान कर ससांधनों का संग्रहण किया। शिक्षा के लिए इस मॉडल को विस्तारित करने का मामला सरल है और अपरिहार्य भी; क्योंकि बच्चे टीकाकरण के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से बच्चे शिक्षा के लिए भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। दानदाता सरकारों को चाहिए कि वे वर्ष 2011 से 2015 तक आईएफएफई ब्रांड निगर्मन के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3 विलियन यूएस डालर से 4 विलियन यूएस डालर संशोधित तीव्र पथ प्रयास के माध्यम से राजस्व प्रणालन के हिस्से के रूप में करें।

- *नवाचारी वित्त संग्रहण* सबके लिए शिक्षा हिमायत करती है कि वित्तीय सस्थानों पर अधिभार हेतु मामला बनाने के लिए व्यापक संघटनों के साथ काम करना चाहिए जिसमें 'राबिन हुड टैक्स' अभियान जैसे प्रस्ताव भी सम्मिलित हों और वे सुनिश्चित करते हों कि एक व्यापक सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की वित्तीय सहायता रणनीति सहित एक हिस्से के रूप में राजस्व आबंटन में शिक्षा भी शामिल हो। वित्तीय सहायता अंतराल के पैमाने के अनुसार, यहां पर अन्य ऐसे नवाचारी वित्तीय सहायता प्रस्तावों की आवश्यकता है जो शिक्षा पर केन्द्रित हों। 2011 सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट ने पूरे यूरोपीय यूनियन देशों में मोबाइल फोन पर अधिभार का 0.5% प्रभार मोबाइल ग्राहकों से लेने का मामला बनाया है। इस प्रकार की मोबाइल फोनों के ग्राहकों पर लगाया गया अधिभार अनुमानतः वर्ष में 894 मिलियन यूएस डालर सग्रंहण कर सकता है। □

काबुल में टूटेफूटे भवन में खेलते बच्चे, जोकि अब 105 शरणार्थी परिवारों के लिए बसेरा है।

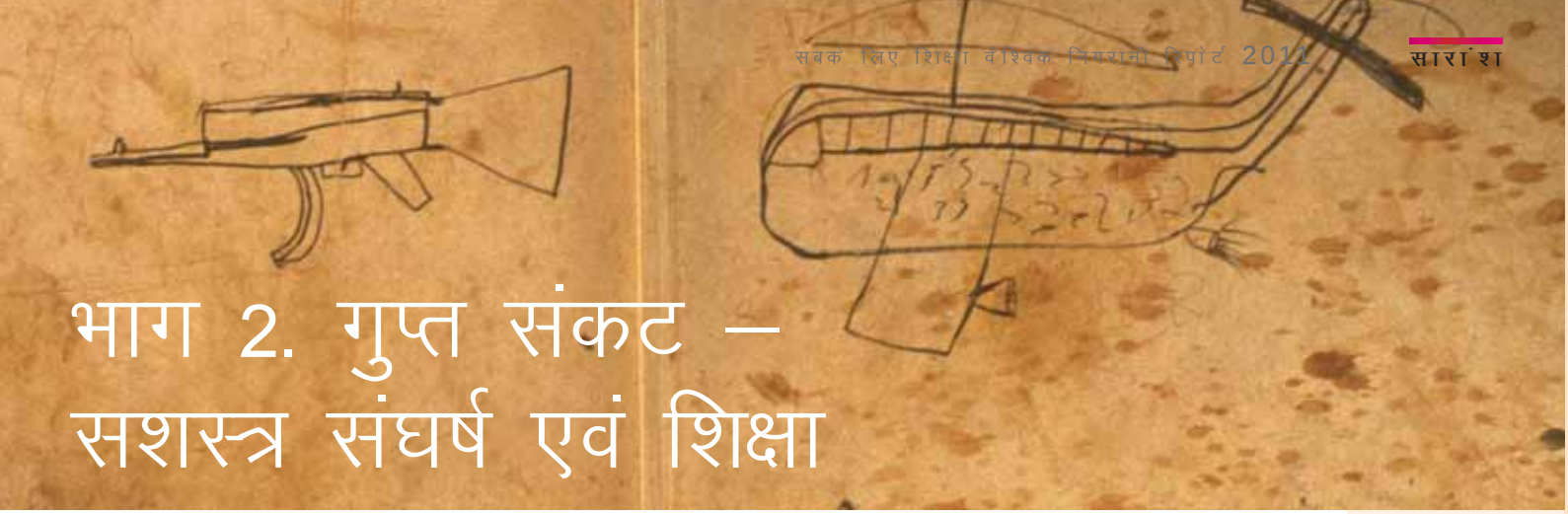

भाग 2. गुप्त संकट – सशस्त्र संघर्ष एवं शिक्षा

संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 'युद्धों की विभीषिका' के अंत में किया गया। नई प्रणाली के निर्माताओं के सामने उद्देश्य यह था कि ''मानव अधिकारों हेतु भर्त्सना एवं असम्मान'' के रूप में तथा बर्बर कृत्यों जिसे मानवीयता के सद्विवेक अत्याचार के रूप में वर्णित करते हैं, को रोकना तथा मानव अधिकार की सार्वजनिक घोषणा को वापस लाना था। आज पैंसठ वर्ष बाद भी युद्ध की विभीषिका जारी है। इसका सर्वाधिक वास्तविक विकार गरीबतम देशों में पाया गया है और यह विशाल पैमाने पर शिक्षा के लिए विध्वंसक स्वरूप है।

शिक्षा पर सशस्त्र संघर्ष के संघात(कुप्रभाव) को व्यापक रूप से उपेक्षित किया गया है। यह एक गुप्त संकट है जो गरीबी को लादता है, आर्थिक प्रगति को नकारता है तथा राष्ट्रों प्रगति को पीछे धकेलता है। संकट का मार्मिक सत्य अत्यधिक व्यापक एवं क्रमबद्ध मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है जो पूर्ण रूपेण एक बर्बरतापूर्ण कृत्य कहलाने के योग्य है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में अतिशीघ्र ध्यानकर्षण हेतु कोई समीक्षा का अर्थ नहीं है। अभी तक, मानवता की अंतरात्मा के उद्वेलन एवं चमकीली प्रभावी प्रतिक्रिया से बहुत दूर हैं। संघर्ष का शिक्षा पर पड़ा विध्वसंक प्रभाव व्यापक रूप से आसूचित ही रह जाता है। अंतराष्ट्रीय समुदाय इसके भुक्तभोगियों की ओर से अपनी पीठ मोड़ लेता है।

2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* ने शिक्षा में गुप्त संकट की ओर प्रकाश प्रक्षेपित किया है। इसने संकट के पैमाने को अभिलेखित किया, इसके कारणों की खोजा तथा बदलाव के लिए कार्यसूची को स्थापित किया। इसका प्रमुख संदेश यह है कि कार्य व्यापार यथानुसार सबके लिए शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति के किसी भी परिप्रेक्ष्य के नकारते हुए उपागमित करता है फिर चाहे वह सबके लिए शिक्षा हो या फिर सहस्राब्दी विकास के लक्ष्य।

सशस्त्र संघर्ष एवं शिक्षा के बीच की सारी कडियां एक ही दिशा में नही संचालित होती हैं। यद्यपि शिक्षा प्रणाली में यह संभावना निहित है कि वह शांति के लिए एक शक्ति पूर्ण बल के रूप में कार्य कर सकती है। इसके साथ ही इसमें समाधान एवं संघर्ष विराम की क्षमता है, लेकिन ये सभी प्रायः हिंसा हेतु ईंधन का काम करते हैं। यह कुछ ऐसा था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने समझा था। उन्होंने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध, उसके तत्कालिक कारण चाहे कुछ भी रहे हों, कुल मिलाकर परस्पर समझ की असफलता के कारण संभावित हुआ। यूनेस्को ने इसके उत्पत्ति के कारणों को खोजा और उन असफलताओं को संबोधित करने का एक प्रयास किया। इसके 1945 के संविधान ने माना कि पूरे इतिहास के दौर में, एक दूसरे के मार्गों (जीवनयापन शैली) एवं जीवन की उपेक्षा ने लोगों को हिंसा हेतु प्रेरित किया और वह क्षीण होती शांति केवल शिक्षा के ऊपर ही निर्मित की जा सकती है। चूंकि युद्ध मानव के मस्तिष्क में शुरू होते हैं अतः यह मानव का मस्तिष्क ही है जहां शांति की सुरक्षा निर्मित की जानी चाहिए। लेकिन अभी भी प्रायः शिक्षा प्रणाली को परस्पर सम्मान, धैर्य या सहनशीलता तथा निर्णायक सोच को बढ़ावा देने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि दूसरों के

विशेष भागीदारीः बस अब बहुत हुआ

लगभग सत्तर साल गुजर चुके हैं जब एक पीढ़ी के राजनीतिक नेता एक भीषण संघर्ष के परिणामस्वरूप मिले और दो सरल शब्दों की शपथ ली कि 'अब दोबारा नहीं'। इस दुश्मनी, युद्धों एवं मानव अधिकारों के उल्लंघनों में वापसी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया जोकि पहले ही न जाने कितनी जाने ले चुका था और असीम संभावनाओं (सक्षमताओं) को बेकार किया। लेकिन अभी भी मानव का जीवन एवं क्षमता नष्ट हो रही है और अब हमें इसे तुरंत रोकना है।

यूनेस्को रिपोर्ट काफी समय से अपेक्षित है। यह विश्व के कुछ सर्वाधिक नाजुक लोगों पर हुए बर्बर हिंसा की गंभीर क्रूरताओं का काला विवरण अभिलेखित करती है जिसमें स्कूली बच्चे शामिल है तथा यह सभी देशों के नेताओं के समक्ष, चाहे वे गरीब हो या अमीर के सामने चुनौती पेश करता है कि निश्चयात्मकता से कार्यवाही करें।

विश्व नेताओं से मेरी अपील है कि वे एक सरल से दृढ़ संकल्प कथन पर जोर दे 'बस अब बहुत हुआ' (इनफ इज इनफ) । एक अकेली नृजातीय मानव समुदाय का एक सदस्य होने के नाते हममें से किसी को भी मानव अधिकारों के उल्लंघन को बरदाश्त नहीं करना चाहिए, जिसमें बच्चों पर हमला और स्कूलों को विनष्ट करना–जोकि हमने अनेक सशस्त्र संघर्षों में देखा है–भी शामिल है। आइए सुरक्षा या दंडमुक्ति की संस्कृति के तहत एक रेखा खींचे कि जो ऐसे कार्यों को ही अनुमत करें और आइए अपने बच्चों को संरक्षित करें तथा उनके शिक्षा के अधिकारों को भी। मैं सभी राजनेताओं से अपील करता हूँ तथा उन देशों और सशस्त्र समूहों से भी अपील करता हूँ जो सशस्त्र संघर्ष में संलग्न हैं कि वे याद रखें कि अकेले अंतर्राष्ट्रीय मानवीयता के कानूनों से परे नहीं हैं।

इसके साथ ही मैं समृद्ध देशों के नेताओं से भी अपील करता हूँ कि जो सीमांत रेखा पर हैं, उन्हें अति प्रभावी समर्थन प्रदान करें। दुनिया भर में भ्रमण के दौरान मैंने प्रायः खुद को अद्वितीय प्रयासों, बलिदानों एवं दृढ़ इरादों के सम्मुख कृतज्ञ एवं विनम्र पाया जोकि अभिभावकों एवं बच्चों ने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की गई हैं। जब गाँवों पर हमला किया गया, लोगों को विस्थापित होना पड़ा, तब तत्काल कहीं से काम चलाऊ स्कूल प्रकट हुए। एक स्कूल नष्ट हुआ और अभिभावक एवं बच्चों ने मिलाकर हर संभव प्रयास करके शिक्षा के लिए द्वारा खोल लिए। क्या दानदाता भी ऐसा ही संकल्प और प्रतिबद्धता दर्शा सकते हैं।

प्रायः बहुत कम, संघर्ष प्रभावित देशों के लोग शिक्षा के लिए बहुत ही कम समर्थन प्राप्त कर पाते हैं और वे प्रायः गलत प्रकार से समर्थन पाते हैं। जैसा कि यह रिपोर्ट दर्शाती है विकास सहायताएं बहुत निम्न और बहुत विलंब के सिंड्रोम (संलक्षण) से ग्रस्त होती है। जिसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रयास निष्फल हो जाता है।

आर्च विशप डेसमंड टूटू
नोबल शांति पुरस्कार 1984 से प्रतिष्ठित

संघर्ष प्रभावित देशों के लगभग 28 मिलियन प्राथमिक स्कूल आयु वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं

प्रति असम्मान, अधैर्य व हिस्सा एवं पूर्वाग्रह प्रबलित किए जाते हैं जो समाजों को हिंसा की ओर धकेलते हैं।

प्रत्येक सशस्त्र संघर्ष भिन्न होता है और शिक्षा पर भिन्न दुष्परिणाम डालता है। फिर भी यहां पर कुछ पुनरावर्ती विषय है। इस रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन पर चार क्रमबद्ध असफलताएं पहचानी हैं जोकि इस 'सशस्त्र संघर्ष' का मर्म हैं।

- *संरक्षण की असफलता।* राष्ट्रीय सरकारें तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी नैतिक जिम्मेदारी एवं कानूनी उत्तरदायित्व की भूमिका नहीं निभाते जिससे कि सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों को फंसने से बचाया जा सके। यहां पर मानव अधिकारों के भीषण उल्लंघन के आस–पास दंडमुक्ति की संस्कृति होती है जोकि शिक्षा के प्रमुख बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती है। बच्चों, शिक्षकों एवं स्कूल पर हमला तथा व्यापक रूप से एवं क्रमबद्ध बलात्कार एवं अन्य यौन हिंसा के स्वरूपों का उभरना युद्ध का एक हथियार बन गए हैं, जो अनेक ऐसे उल्लंघनों के नग्नतम उदाहरण है।

- *प्रावधानों की असफलता।* सशस्त्र संघर्षों द्वारा प्रभावित अभिभावक एवं बच्चे प्रतिकूलताओं के सम्मुख शिक्षा में पहुंच बनाए रखने हेतु अद्वितीय संकल्प प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। उनके प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा बराबर समपूर्ति नहीं की जाती। मानवीय सहायता प्रणाली में शिक्षा एक सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है जो वित्तीय सहायता के अभाव से पूर्ण एवं प्रतिक्रिया रहित होता है।

- *प्रारंभिक क्षतिपूर्ति एवं पुनर्निर्माण में असफलता।* शांति प्रतिस्थापनाएं युद्ध के पश्चात सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को क्षतिपूर्ति एवं पुनर्निमाण की रणनीतियों को रखने के अवसरों का गवाक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन आमतौर पर ये समय पर कार्यवाही नहीं करते हैं। समस्या का एक हिस्सा यह है कि पश्च संघर्ष प्रभावित देश मानवीय सहायता एवं दीर्घकालिक विकास सहायताओं के बीच एक अस्पष्ट क्षेत्र में छोड़ दिए जाते हैं। जब यह बात संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों के बारे में आती है तो प्रायः अंतर्राष्ट्रीय सहायता संरचनाएं टूट जाती है।

- *शांति स्थापना में असफलता।* शांति स्थापना में शिक्षा एक केन्द्रीय भूमिका निभा सकती है, कदाचित किसी भी अन्य क्षेत्र से ज्यादा बेहतर शिक्षा उच्च दर्शनीय शांति लाभांश प्रदर्शित कर सकती है जिस पर शांति समझौतों की उत्तर जीविता निर्भर हो सकती है। इसके अतिरिक्त, जब शिक्षा प्रणाली को परस्पर समझ (भाईचारे), सहनशीलता एवं आदर के लिए प्रेरक प्रवृत्ति अपनाने की दिशा में समाविष्ट एवं सज्जित किया जाए तो वह हिंसात्मक संघर्ष हेतु कम भाव प्रवण (संवेदी) समाज को निर्मित कर सकती है।

© इस्माइल मोहम्मद / यू पी आई / गामा

बच्चे अपने साथियों के साथ टेंट वाली कक्षा में, वर्ष 2009 में इजरायल द्वारा गाजा पर हमले से उनके स्कूल के नष्ट होने के बाद

उपरोक्त प्रत्येक असफलता गहनता से सांस्थानिक व्यवहारों में अंतः स्थापित है। यद्यपि ये सभी व्यावहारिकता के लिए संशोधनीय है तथा इस रिपोर्ट में वहनीय समाधान पहचाने गए हैं। बदलाव के लिए प्रमुख संघटक है–सुदृढ़ नेतृत्व, सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय समन्वय तथा बहुस्तरीय प्रतिक्रिया का विकास–इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के लिए एक सर्वाधिक विशाल विकास चुनौती है।

सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों हेतु सशस्त्र संघर्ष एक बड़ी बाधा

जब सरकारों ने वर्ष 2000 में कार्यवाही के लिए डाकार रूपरेखा अपनाई थी तो उन्होंने सबके लिए शिक्षा प्राप्ति की दिशा में संघर्ष को सबसे बड़ी बाधा के रूप में पहचाना था। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि बाधा की ऊंचाई का प्राक्कलन कमतर किया गया था और इसे मिटाने की रणनीतियों हेतु कम सक्षम ध्यान दिया गया (*देखें–विशेष भागीदारी : सुरक्षा एवं विकास हेतु शिक्षा*)। संघर्ष प्रभावित विकासशील देश सबके लिए शिक्षा लक्ष्य हेतु लीग तालिका की पहुंच में भारी रूप से सबसे नीचे सकेन्द्रित है (चित्र–9)।

- अन्य विकासशील देशों की तुलना बाल मृत्यु दर दो गुना उच्च है जो उच्च स्तर के कुपोषण एवं संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को प्रतिबिंबित करते हैं।

- संघर्ष प्रभावित देशों के लगभग 28 मिलियन प्राथमिक स्कूल आयु वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं जहां विश्व की प्राथमिक स्कूल आयु की 18% जनसंख्या रहती है और पूरे विश्व की स्कूल से बाहर बच्चों की जनसंख्या का अकेले 42% हिस्सा यहीं रहता है। गरीबतम देशों के समूह के अंतर्गत वे पूरे विश्व की प्राथमिक स्कूल आयु के बच्चों की एक चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन लगभग इसकी आधी जनसंख्या स्कूल से बाहर है।

- संघर्ष प्रभावित देशों में; अन्य विकासशील देशों की तुलना में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में पंजीकरण लगभग एक तिहाई निम्न है और लड़कियों के लिए यह भिन्नता तो बहुत अधिक है।

- संघर्ष प्रभावित देशों में युवा साक्षरता दर 79% है जबकि इसकी तुलना में अन्य विकासशील देशों में यह दर 93% है।

विशेष भागीदारीः सुरक्षा एवं विकास हेतु शिक्षा

जब हम युद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सैनिकों का विचार आता है। लेकिन वे लोग ही केवल हिंसा या मृत्यु का सामना नहीं करते हैं। बल्कि कारूणिक स्थिति यह है कि युद्ध रेखा पर बच्चे और स्कूल ऐसी ही स्थिति से गुजरते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भंगुर या संघर्ष प्रभावित देशों में आधे बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं।

संघर्ष जितना छद्मपूर्ण है उतना ही भयंकर है। यह केवल न आज के जीवनयापन के साधन नष्ट कर रहा है, बल्कि यह भविष्य के जीवनयापन के साधन विनष्ट करता है; क्योंकि यह बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है। बच्चे युद्ध के बाद स्कूल आते हैं तो भी विध्वंसात्मक बचपन के संघातों का प्रभाव उनकी सीखने की क्षमता एवं दुनिया के साथ समन्वय करने में मुश्किल पैदा करता है। यह प्रभाव एक पीढ़ी को विकृत कर सकता है।

विध्वंस की ये लहरें विकास को एक घर्षित विराम दे कर जाती है और अवसर इसे आरक्षित में फेंक देते हैं। संघर्ष के साथ बच्चों का स्कूल से बाहर होना सबके लिए शिक्षा एवं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करना लगभग असंभव सा हो जाता है। जबकि धर्मान्धता (कठमुल्लापन) एवं हिंसा चौतरफा उभरती है। इसीलिए निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि इन बच्चों को शिक्षा अवश्य दी जाए। यह न केवल संघर्षों को रोकती है बल्कि अंत में राष्ट्र का निर्माण करती है। यह अवसंरचना बनाती है और अभिशासन सिखाती है और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मस्तिष्क परिपक्व करती है। नव प्राप्त शांति के परिणामस्वरूप संघर्षरतों, बच्चों एवं वयस्क आदि के लिए पुनः शिक्षा निर्णायक होती है चूंकि उनके पास एक बंदूक की लिबलिबी के अलावा न तो कोई कौशल होता है और न ही कोई संदर्श या विकल्प।

यह बात मध्यपूर्ण के लिए बिल्कुल सही है जहां, बहुत सारे बच्चों के लिए हिंसा ही उनके जीवन को पारिभाषित करती है। फिलीस्तीन में, लगभग 110,000 से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जोकि दस साल पहले 4,000 थे। अधिपत्य की छाया में बड़े होना, युद्ध से डरे हुए, स्कूल जाना फिलस्तीन के बच्चों के लिए एक मात्र सर्वाधिक कद्र वाली प्राथमिकता होती है। बंमों एवं अवरोधों के बावजूद, वे जानते हैं या उम्मीद करते हैं कि उनके सामान्य जीवन की यही एक आशा है।

इराक में, गरीबी और असुरक्षा लगभग आधा मिलियन बच्चों को स्कूल जाने से वंचित किए हुए हैं। उनके प्रतिदिन का पाठ भुखमरी एवं क्षति है, वे भय एवं घृणा की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आंचलिक एवं वैश्विक असुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता है तो हमें निश्चित रूप से गरीबी, सामाजिक अपवर्जन (वहिष्करण) तथा युद्धों के कारण आए अवसरों की कमी को संबोधित करना चाहिए इसका तात्पर्य है कि संघर्ष क्षेत्रों में शिक्षा को लाना, क्योंकि आंतकवाद को कम करती है तथा भंगुर राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाती है।

लेकिन, इससे भी ज्यादा, लाखों बच्चों के लिए आशा का संचार करती है, जो कि कभी भी शांति के बारे में नहीं जानते, उन देशों के लिए सुअवसर लाती है जोकि वृद्धि एवं समृद्धता से लगातार वंचित होते हैं।

संक्षेप में, शिक्षा हमारी लावण्यता को बचाने वाली हमारा सर्वोत्तम अवसर है और एक प्रकार से सारी मानवता के लिए सुरक्षा एवं विकास लाती है।

जोर्डन की महारानी रानिया अल अब्दुल्ला

यहां पर साक्ष्य है कि हिंसात्मक संघर्ष के द्वारा देश में धन एवं लिंग से संबंधित भेदभाव तेजी पकड़ते हैं। संघर्ष प्रभावित क्षेत्र प्रायः देश के अन्य भागों से पीछे रह जाते हैं। फिलीपीन्स में, स्वाशासित क्षेत्र मुस्लिम मिंडानावो में युवा लोगों की शिक्षा में भागीदारी दो वर्ष से कम है जो राष्ट्रीय औसत चार गुना कम है।

सशस्त्र संघर्ष से जुड़ी ज्यादातर मौतों युद्ध क्षेत्र से दूर उभरती हैं जो बीमारियों एवं कुपोषण का परिणाम होती हैं। ये दोनों जुड़वा मारक बहुतायत में 4.5 मिलियन जिंदगियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं जोकि युद्ध के दौरान प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगों में हुईं। जोकि विश्व के सबसे घातक संघर्ष का आतिथेय था। इसमें लगभग आधे शिकार बच्चे थे, जिनकी आयु पांच वर्ष से कम थी। बीमारियां एवं भुखमरी इन शीर्ष रेखाओं के साथ सन्निहित होती हैं जो शिक्षा के लिए दुर्बलीकरण के दुष्परिणामों को लाती है।

बच्चे, नागरिक एवं स्कूल अग्रिम पंक्ति पर

आजकल देश के ही अंतर्गत सशस्त्र संघर्ष प्रचुरता से लड़े जा रहे हैं न कि सीमा रेखा पर, और बहुत से लोग दीर्घकालिक हिंसा में सम्मिलित हैं। 2011 सबके लिए शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ने वर्ष 1999 से 2008 तक अड़तालीस सशस्त्र संघर्षों को पैंतीस देशों में पहचाना गया है। इनमें से तैंतालिस युद्धों ने निम्न आय देशों एवं निम्न मध्य आय देशों में स्थान लिया। जबकि हिंसा की सघनता, व्यापकता एवं भौगोलिक विस्तार भिन्न था एवं दीर्घकालिक सशस्त्र संघर्ष सामान्य था। निम्न आय देशों में यह संघर्ष औसतन बारह वर्ष लंबा था, जबकि शेष निम्न मध्य आय देशों में यह औसत बढ़ता हुए बाइस वर्ष का था।

21वीं शती के प्रारंभ में सेना बल का भेदभाव पूर्ण उपयोग तथा जान बूझकर नागरिकों को लक्ष्य बनाना हिंसापूर्ण संघर्ष का हालमार्क (पहचान चिंह) बन चुका है। अधिकतर संघर्षों में, यह लड़ाकों से ज्यादा नागरिकों के लिए खतरनाक बन चुका है। शिक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। आज सशस्त्र संघर्ष में बच्चे एवं स्कूल अगली पंक्ति पर होते हैं जिसमें कक्षाएं, शिक्षक तथा छात्र अंतिम लक्ष्य के रूप में देखें जाते हैं। जैसा कि एक यू.एन. रिपोर्ट बताती है कि इस के दुष्परिणाम के अंतर्गत बच्चों में स्कूल में भाग लेने के प्रति भय का बढ़ना, यहां तक कि शिक्षकों द्वारा कक्षाएं न पढ़ाना तथा अभिभावकों के अंदर बच्चों को स्कूल न भेजने की भय व्याप्ति बढ़ रही है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में सामान्यतया आतंकवादी समूह लगातार शिक्षा संस्थानों पर हमला करते हैं और विशेष रूप से कन्या स्कूलों को लक्षित करते हैं। सुरक्षा के डर के नतीजे में अफगानिस्तान के हेलमंढ राज्य में 70% से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। गाजा में, फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्र में इजयारली सेनाओं के हमलों के परिणामस्वरूप 2008 एवं 2009 में 350 बच्चे मरे और 1815 घायल हुए तथा 280 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए। इसी प्रकार से थाइलैंड के तीन दक्षिणी राज्यों में आतंकवादियों ने स्कूलों एवं शिक्षकों को लक्ष्य बनाया। चौबीस देशों से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल सैनिकों का उपयोग हो रहा है जिसमें सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, चाड, प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगों, म्यांमार तथा सूडान आदि शामिल हैं।

शिक्षा के लिए हिंसा के व्यापक प्रतिमान के दूरगामी दुष्परिणाम हैं। यू एन महासचिव की रिपोर्ट लगातार साक्ष्य उपलब्ध कराती हैं कि बहुत सारे देशों में बलात्कार एवं अन्य यौन हिंसाओं को

आज सशस्त्र संघर्ष में बच्चे एवं स्कूल अगली पंक्ति पर होते हैं जिसमें कक्षाएं, शिक्षक तथा छात्र अंतिम लक्ष्य के रूप में देखें जाते हैं

चित्र 9: शिक्षा में संघर्ष–प्रभावित देश पिछड़ रहे हैं

2008 में संघर्ष स्थिति: चुने हुए निम्न आय एवं निम्न मध्य आय देशों के लिए शिक्षा–सूचकांक

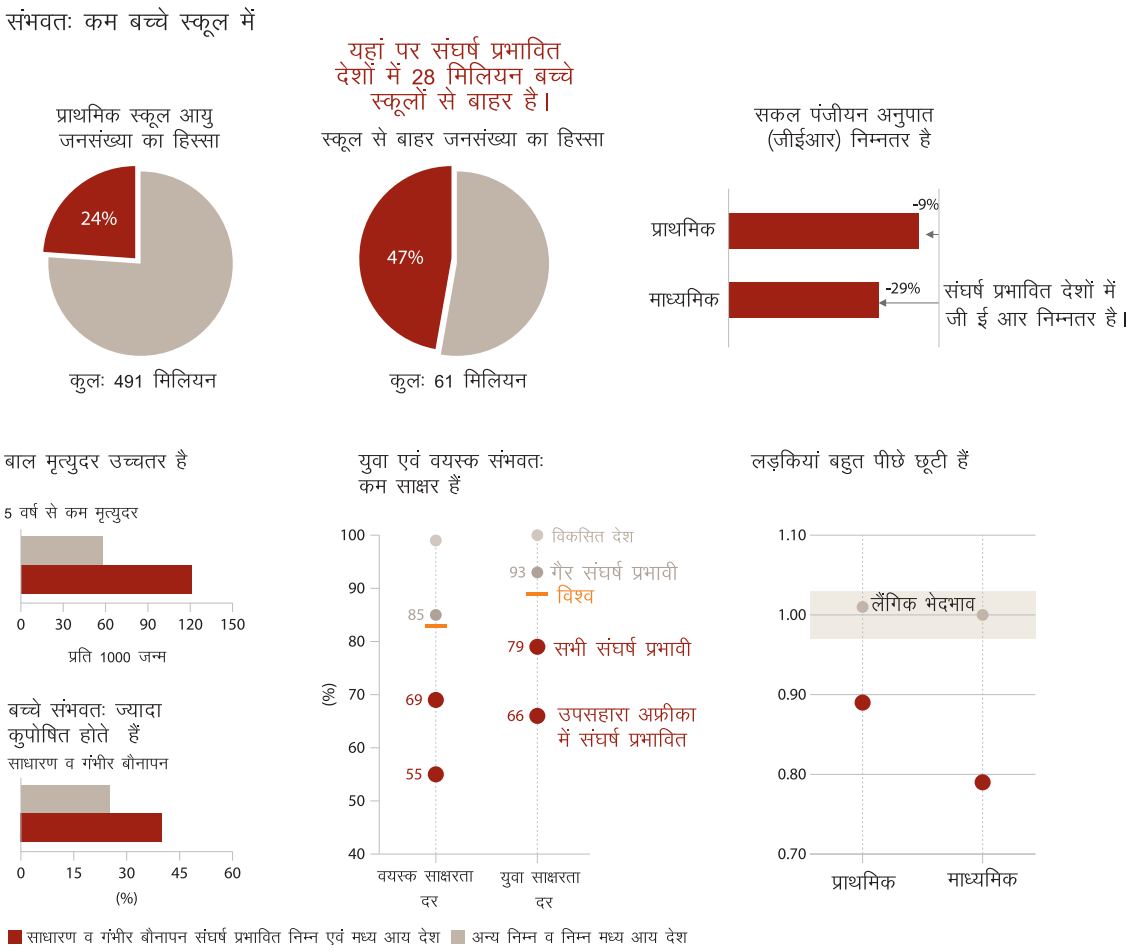

स्रोतः देखे चित्र 3.1. 2011 सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट

एक सोमाली लड़की मोगादिशू में एक युद्धशापित भवन से गुजरती हुई, जहां संघर्ष ने भारी संख्या में बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया।

व्यापक रूप से युद्ध नीति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें सेंट्रल अफ्रीकन गणतंत्र, चाड अफगानिस्तान, प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगों एवं सूडान आदि शामिल है। इनमें बहुत सारी भुक्तभोगी लड़कियां होती हैं। जो लोग प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं उनके लिए शारीरिक क्षति, मनोवैज्ञानिक प्रघात तथा लांछित या कलंकित होने जैसे दुर्बोध आदि संसाधनों एवं शिक्षा में अनंत प्रतिकूलताएं लाते हैं। युद्ध के एक साधन के रूप में बलात्कार के उपयोग के बहुत व्यापक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि असुरक्षा लड़कियों को स्कूल से बाहर रखती है तथा पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन में विघटन बच्चों को सुरक्षित अधिगम वातावरण में वंचित करता है।

स्कूली अवसरंचना हेतु यह केवल मानवीय मूल्य एवं भौतिक क्षति नहीं है, बल्कि शिक्षा को आहत करता है। इसके साथ ही सशस्त्र संघर्ष आर्थिक वृद्धि को क्षतिग्रस्त बनाता है, गरीबी को प्रबलित करता है तथा कक्षा में निवेश किए जाने वाले उत्पादक संसाधनों को मोड़कर अनुपात्दक सैनिक खर्चों में लगाता है। इस रिपोर्ट ने विश्व के ऐसे 21 गरीबतम देशों की पहचान की है जिनका प्राथमिक शिक्षा से अधिक सैन्य बजट है–कुछ

मामलों में बहुत ज्यादा है एवं शिक्षा के सबसे खराब संकेत है। चाड प्राथमिक शिक्षा के व्यय से चार गुना अधिक व्यय हथियारों पर करता है। और पाकिस्तान सात गुना ज्यादा सैन्य पर खर्च करता है। यदि कुछ देश शिक्षा की अपेक्षा सैन्य एवं हथियारों पर अधिक व्यय करते हैं यदि वे अपने उक्त खर्चों में 10% की कटौती कर लें तो 9.5 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। जोकि स्कूल से बाहर की उनकी 40% जनसंख्या के समतुल्य है (चित्र–10)।

सैन्य व्यय सहायता संसाधनों को भी मोड़ देते हैं। वर्ष 2009 में वैश्विक सैन्य व्यय 1.5 ट्रिलियन यूएस डालर पहुंच चुका था। यदि समृद्ध देश अपने सैन्य खर्च का केवल 6 दिन का व्यय प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए स्थानांतरित कर दें तो वे सबके लिए शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति में 16 बिलियन यूएस डालर का वाह्य वित्तीय सहायता अंतराल पूरा कर सकते हैं। और 2015 तक सारे बच्चे स्कूल में जा सकते हैं (चित्र–11)।

राष्ट्रीय सरकारों और सहायता दानदाताओं को तत्काल आधार पर हथियारों पर अनुत्पादक व्यय को स्कूल, किताबों, बच्चों जैसे उत्पादक व्यय में परिवर्तित करने के लिए संभाव्यता की समीक्षा करनी चाहिए। सभी देशों को सुरक्षा भय हेतु प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हालांकि शिक्षा में निवेश के अवसर खो देने के कारण गरीबी, बेरोजगारी, पलायन आदि प्रबलित होता है जोकि अनेक संघर्षों को अभिप्रेरित करता है।

विस्थापित जनसंख्या न के बराबर दृष्टिगत होती है

प्रायः थोक विस्थापन सशस्त्र समूहों के लिए एक सामरिक लक्ष्य होता है जो जनसंख्या को विलग करना चाहते हैं या विशिष्ट समूहों की जीवन यापन को क्षति पहुंचाते हैं। यूएन आंकड़े संसूचित करते हैं वर्ष 2009 के अंत तक विश्व भर में 43 मिलियन लोग विस्थापित हुए, यद्यपि वास्तविक संख्या निश्चित ही इससे अधिक होगी। हाल ही के अनुमान सुझाते हैं कि लगभग आधे शरणार्थी एवं आंतरिक विस्थापित लोग (आइ डी पीज) 18 वर्ष से कम आयु के हैं। हालांकि सीमाओं को पार करने वाले शरणार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा चुकी है, किन्तु अंतर–देशीय विस्थापन बढ़ चुका है।

विस्थापन यह विगोपित करता है कि लोगों को शिक्षा में सर्वोच्च प्रतिकूलता का जोखिम होता है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण के आंकड़ों ने शरणार्थी शिविरों में शिक्षा की स्थिति की विचलित करने वाली तस्वीर प्रस्तुत की है। प्राथमिक स्कूलों के लिए औसतन पंजीकरण केवल 69% है तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए पंजीयन ठीक 30% है। छात्रों/शिक्षक का अनुपात अति उच्च है। लगभग एक तिहाई शिविरों में 50:1 या अधिक सूचित किया है जबकि अनेक शिक्षक अप्रशिक्षित थे। कुछ शिविरों में, जिनमें सोमाली शरणार्थियों की शरणगाह उत्तरी केन्या भी शामिल है। अभिभावकों ने चिंता जाहिर की है कि माध्यमिक शिक्षा अवसरों की दुलर्भता ने युवाओं को सशस्त्र समूहों में भर्ती के जोखिम हेतु विगोपित किया है। विस्थापित जनसंख्या हेतु स्कूलों की उपस्थिति सेंट्रल अफ्रीकी गणतंत्र, चाड एवं प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो जैसे देशों में घोरतम निम्न है।

चित्र 10. युद्ध क्रीड़ा

युद्ध क्रीड़ा

इक्कीस विकासशील देश प्राथमिक शिक्षा से अधिक सेना में व्यय करते हैं।

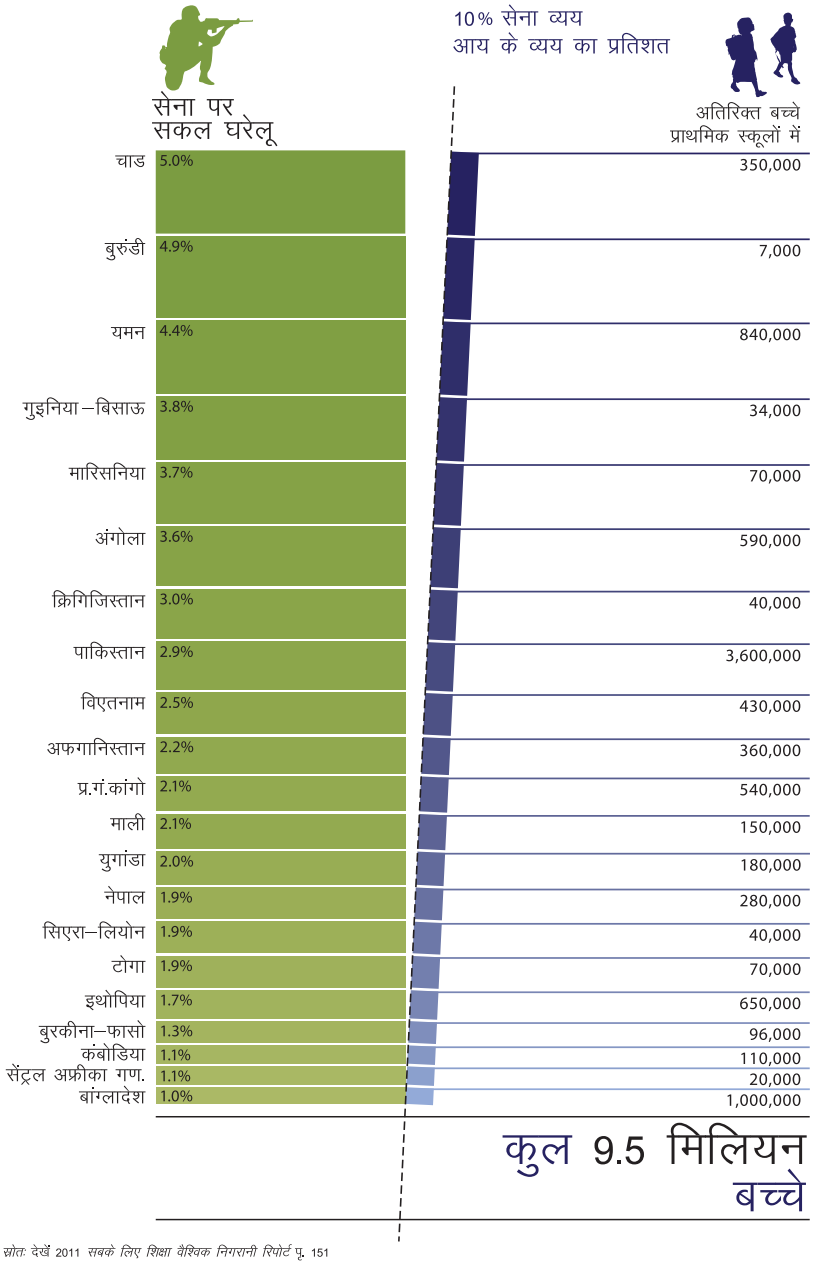

स्रोतः देखें 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* पृ. 151

शरणार्थियों को ऐसी व्यापक समस्याएं झेलनी पड़ती है जो शिक्षा को हानि पहुंचाती है। बहुत सारे देश शरणार्थियों को सार्वजनिक शिक्षा एवं मूलभूत सेवाओं में पहुंच की छूट नहीं प्रदान करते हैं। मलेशियाई कानून के तहत शरणार्थी अनाभिलेखित प्रवास के लिए प्रतिष्ठित नहीं हैं। थाइलैंड में, म्यानमार के दीर्घकालिक शरणार्थियों को सार्वजनिक शिक्षा में अधिकार नहीं हैं (बाक्स–4), सर्वाधिक सामान्य रूप से शरणार्थियों के लिए रोजगार के प्रतिबंध गरीबी को प्रबलित करते हैं, जोकि शिक्षा के लिए परिदृश्यों को अवमंदित

चित्र 11. सैन्य खंड

सैन्य खंड

सबके लिए शिक्षा बनाम सैन्य व्यय वित्तीय अंतराल

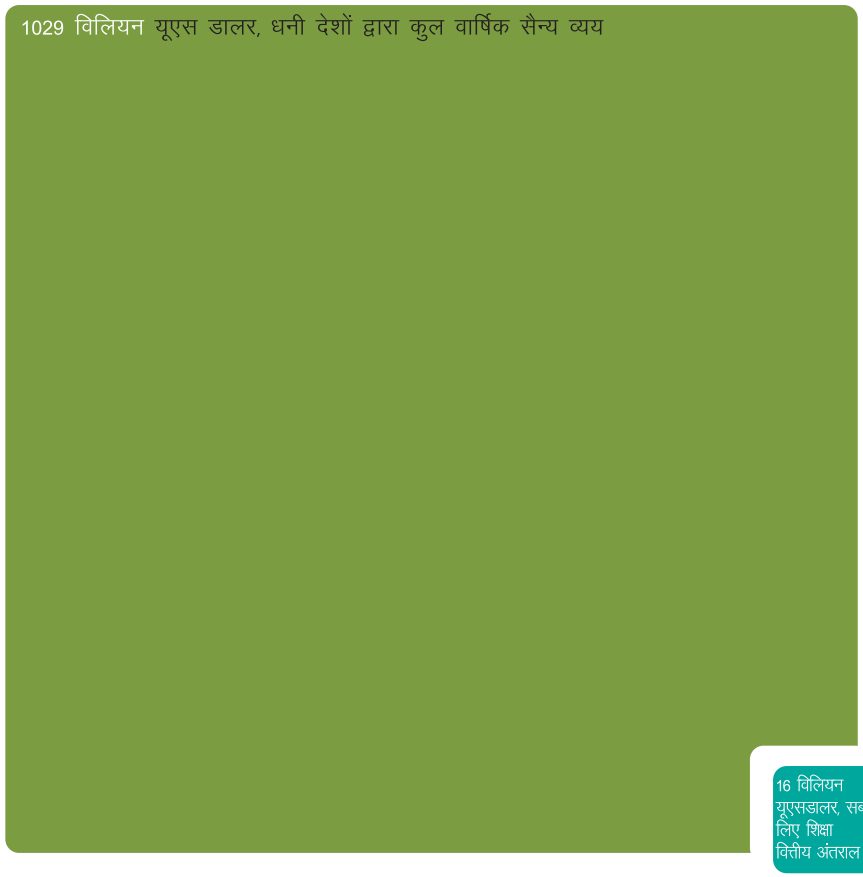

6 दिनों के सैन्य व्यय से सबके लिए शिक्षा वित्तीय अंतराल भर जाता है।

स्रोतः देखें 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* पृ. 150

बॉक्स 4: शरणस्थल, लेकिन शिक्षा में समस्या–थाइलैंड में कैरेन शरणार्थी

संघर्ष के कारण भारी संख्या में लोग पड़ोसी देशों में पलायन कर गए, जिनमें बांग्लादेश, चीन, थाइलैंड म्यॉनमार के जैसे देश शामिल हैं। इन शरणार्थियों की भारी जनसंख्या थाई सीमा में 9 शिवरों बसी हुई है। प्रचुरता से कैरेन एवं कैरेन्नी नृजाति समूह, 140,000 पंजीकृत निवासी उस देश में प्रवेश करने वाले विस्थापित नागरिकों के एक छोटे धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्षों के दौरान इन शिवरों ने एक सघन शिक्षा प्रणाली विकसित कर ली है। जिसमें पूर्व स्कूली, प्राथमिक एवं माध्यमिक, व्यावसायिक एवं वयस्क अधिगम सुविधाएं उपलब्ध है। सात कैरेन शिविरों का एक नेटवर्क 70 स्कूलों के माध्यम से 34,000 छात्रों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। शिविरों की शिक्षा को थाई प्राधिकारियों से अनुशंसा प्राप्त है जबकि सामुदायिक आधारित संगठनों के द्वारा एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (एनजीओज) द्वारा वित्तीय सहायता एवं दान संरक्षण प्राप्त है।

कैरेन शिविरों में शिक्षा एक अद्वितीय प्रतिबद्धता एवं सामुदायिक प्रयास को प्रतिबिंबित करती है। लेकिन यहां पर गंभीर समस्याएं भी हैं। माध्यमिक स्तर पर पंजीकरण विशेषरूप से निम्न, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वित्तीय सहायता को बिंबित करता है जहां कुछ स्कूल की खराब स्थिति एवं शिक्षकों को न्यून वेतन प्राप्त है। एक अनुमान ने 2008 में प्रति छात्र 44 यूएस डालर कुल व्यय प्रकट किया था जो कि थाई प्राथमिक शिक्षा से 3% कम स्तर पर है।

वहां के शिविरों में कुछेक शिक्षा समस्याएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं जो व्यापक अभिशासन की संबद्धता है। शरणार्थियों को आवागमन की सीमित छूट है तथा उन्हें शिविरों के बाहर नौकरी करने की अनुमति नहीं है। कोई स्थाई स्कूल भवन नहीं निर्मित कर सकते हैं (हालांकि हाल ही के संशोधन में अर्ध स्थाई संरचना बनाने को अनुमत किया है)। शिक्षिकों को शिविर के अंतर्गत ही भरती किया जाता है जो प्रायः आवश्यक कौशल से अभावग्रस्त होते हैं। हाल ही के सुधार ने कुछ संबद्धताओं को संबोधित करना प्रारंभ किया है। जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रमाणीकरण शामिल है। यूएनएचसीआर ने व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार का आह्वान किया है तथा शिविर की जनसंख्या को बाहरी संसाधनों पर निर्भरता के साधनों को घटाने के उपाय के रूप में रोजगार के साधन के रूप में बढ़ाया है।

स्रोतः देखें बाक्स 3.4. 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

कर देता है। और शरणार्थी स्थिति प्राप्त करने की कठिनाई बहुत सारे लोगों को गुप्तवास करने की ओर ले जाती है। शहरी झोपड़ पट्टियों में रहना, रोजगार अवसरों की कमी तथा स्थानीय स्कूलों में प्रवेश से इनकार के चलते, उनके बच्चों के पास शिक्षा प्राप्ति के बहुत कम अवसर बचते हैं। दूसरे संदर्भ में, संघर्षों में असमान व्यवहार के लिए एक परिपाटी छोड़ दी है। फिलिस्तीन के बच्चे पूर्वी जेरूसेलम में शिक्षा के लिए जाते हैं, उन्हें शिक्षा में वित्तीय सहायता झेलने के साथ–साथ सुरक्षा बलों से जानबूझकर सताए जाने की सूचनाएं है। कक्षाओं की कमी तथा शिक्षा की खराब गुणवत्ता ने तमाम फिलिस्तीन बच्चों को निजी शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए विवश किया है। जिससे गरीब परिवारों पर ध्यान देनेयोग्य वित्तीय भार लद गया है।

विपरीत चक्र – हिंसात्मक संघर्षों पर शिक्षा का प्रभाव

शिक्षा अकबयक संघर्ष का एक प्राथमिक कारण है। इसके बावजूद राजनीतिक उत्साहशीलता में निहित तत्व प्रायः देशों को हिंसा की ओर धकेल देते हैं। अंतर–राज्यीय सशस्त्र संघर्ष प्रायः शिकायतों एवं पहचान हेतु पूर्वाभाषित अन्यायों से, विश्वासों (धर्मों), नृजातीयता एवं अंचलता से संबंधित होते हैं। शिक्षा इन सभी क्षेत्रों में एक अंतर पैदा कर सकती है संतुलन को शांति या संघर्ष के पक्ष में झुका देती है। इस रिपोर्ट ने उन प्रक्रमों को पहचाना है जिनके माध्यम से बहुत कम शिक्षा, शिक्षा में असमान पहुंच तथा गलत प्रकार की शिक्षा समाजों को सशस्त्र संघर्षों के प्रति अधिक नाजुक बना सकती है।

- *सीमांत या खराब गुणवत्ता की शिक्षा, बेरोजगारी एवं गरीबी की ओर जाती है।* जब बहुत बड़ी संख्या में नवयुवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा में उनको पहुंच से वंचित किया जाता है तब परिणामस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी एवं निराशा का भाव पैदा होता है जो सशस्त्र आतंकियों की भर्ती के लिए सशक्त भर्ती एजेंट बन सकते हैं। नवयुवकों का उभरना यह तात्कालिकता बढ़ाता है कि शिक्षा से एक ऐसा सेतु बने जो रोजगार प्रदान करें। गुइनिया, लाइबेरिया, नाइजीरिया तथा सिएरालियोन जैसे देशों सहित कुछ देशों में 60% जनसंख्या, 25 वर्ष से कम आयु के युवा है एवं अनेक ओईसीडी देशों की तुलना में 25% कम रोजगार में हैं। रवांडा में बेरोजगारी, ग्रामीण पुरूष युवाओं की कम शिक्षित संख्या 1994 के मानव हत्या कांड के हत्यारों के रूप में उभरकर आए थे।

- *असमान पहुंच, शिकायतों को जन्म देती है तथा अन्याय का भाव पैदा करती है।* शिक्षा में असमानता, व्यापक भेदभावों को विकर्षित करती है तथा संघर्ष के जोखिम को बढ़ाती है। कोट डि आइवोरे में उत्तरी क्षेत्रों में शिक्षा की खराब स्थिति के कारण विद्वेष एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में प्रकट हुई और 2002–2004 तक गृह युद्ध के रूप में रही। वर्ष 2006 में उत्तर एवं उत्तर पश्चिम इलाकों में स्कूल में उपस्थिति दक्षिण की अपेक्षा आधी से भी कम थी। संदर्श यह है कि स्थानीय जनसंख्या को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है क्योंकि बहुतेरी जगहों में संघर्षों के पीछे संसाधनों के असमान वितरण का प्रतिमान एक घटक होता है। ये जगहें इंडोनेशिया का एकेह राज्य से लेकर नाईजीरिया का तेल–समृद्ध नाइजर बेसिन क्षेत्र हो सकती है।

- *पूर्वाग्रहों एवं हिंसा के प्रबलन हेतुः स्कूल व्यवस्था का उपयोग।* अनेक सशस्त्र संघर्षों में शिक्षा को राजनीतिक प्रभुत्व, सीमांत या लघु समूहों का अधीनीकरण तथा नृजातीय अलगाव आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। घृणा एवं धर्मान्धता को पोषित करने के लिए शिक्षा के उपयोग के कारण रवांडा से लेकर भी श्रीलंका तक संघर्ष में हिंसा को भागीदारी सन्निहित है। और अनेक देशों में, सांस्कृतिक पहचान हेतु व्यापक संघर्षों हेतु स्कूल एक आलोक बिन्दु बन जाते हैं। ग्वाटेमाला में; शिक्षा प्रणाली को सांस्कृतिक अधिपत्य एवं देशज भाषाओं को दमित करने के एक साधन के रूप में देखा गया, जिसके कारण व्यापक बेचैनी बढ़ी और गृह युद्ध का रूप लिया। यदि शांति प्रतिस्थापना शैक्षिक विलगाव पर आधारित होते हैं तो स्कूल व्यवस्था उस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है जो वर्गों को सशस्त्र संघर्ष के लिए नाजुक बनाती है जैसा कि बोसनिया एवं हर्जेगोविना के अनुभव चित्रित करते हैं (बाक्स–5)

गलत प्रकार की शिक्षा समाजों को सशस्त्र संघर्षों के प्रति अधिक नाजुक बना सकती हैं

संघर्ष प्रभावित देशों हेतु सहायता

प्रभावित देशों में, विकास सहायता की एक व्यापक भूमिका निभानी होती है। इसमें वह सक्षमता है कि संघर्ष एवं निम्न मानव विकास के द्वेषपूर्ण चक्र को तोड़ें, जिसमें अनेक देश फंसे हुए हैं और चिर स्थायी शांति के अंतरण को समर्थित करे। हालांकि अनेक मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रयासों के प्रभावीपन को कमजोर बनाया है।

एक छोटे समूह के देशों की ओर, जिन्हें सुरक्षा प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है, सहायता का मुड़ जाना, तुलनात्मक रूप से विश्व के अनेक गरीबतम देशों की उपेक्षा की ओर बढ़ जाता है। सत्ताइस संघर्ष प्रभावित विकासशील देशों में विकास सहायता का प्रवाह पिछले दशक से बढ़ा है जो एक वर्ष 2007–2008 में 36 बिलियन यूएस डालर पहुंच गया। हालांकि इन देशों ने कुल सहायता का एक चौथाई प्राप्त किया तथा इराक और अफगानिस्तान

बाक्स 5: खंडित अभिशासन, बोसनिया एवं हर्जेगोविना में खंडित शिक्षा

बोसनिया एवं हर्जेगोविना में, 1995 में डेयटन समझौते ने उच्च स्तरीय विकेन्द्रीकरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण हेतु एक आधार बनाने की मांग की थी। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्राधिकरण के विखंडन ने बहुनृजातीय, राष्ट्रीय पहचान को गठित करना और भी अधिक कठिन बना दिया। आज वहां पर शिक्षा के भिन्न 13 मंत्रालय हैं और ज्यादातर स्कूल नृजातीयता, धर्म एवं भाषा के आधार पर विभाजित हैं। इस प्रकार के विखंडन शिक्षा अभिशासन हेतु तमाम संबद्धताएं पैदा करते हैं।

एक सुदृढ़ संघीय मंत्रालय के अभाव में, राष्ट्रीय नियोजन प्रणाली को विकसित करने में नुकसान पहुंचता हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा में सुधार की समस्याओं को समन्वित करने हेतु क्षति पहुंच रही है। इसके साथ ही निधियों के आबंटन हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली के अभाव में छात्रों की निष्पादकता में व्यापक भौगोलिक विविधता की देन होती है तथा बेहतर गुणवत्ता के परिदृश्य दुर्बल होते हैं। इन सबमें शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि स्कूलों एवं छात्रों का सख्त अलगाव, बच्चों के अंदर बहु सामाजिक पहचान के भाव विकसित करने में मददगार नहीं होते, जिसके ऊपर शांति और सुरक्षा अंततः निर्भर होती है।

स्रोत : देखे बाक्स 3.9. 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

ने कुल सहायता का 38% भाग प्राप्त किया। अफगानिस्तान ने अकेले ही प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो, लाइब्रेरिया तथा सूडान की सम्मिलित सहायता राशि से भी अधिक निधि प्राप्त की।

प्राथमिक शिक्षा हेतु सहायता एक व्यापक आबंटन प्रतिमान को दर्शाती है (चित्र–12)। केवल पाकिस्तान में सहायता के अंतरण का प्रतिनिधित्व प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो तथा सूडान के आबंटन से दो गुना से ज्यादा था। हालांकि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राथमिक शिक्षा हेतु अफगानिस्तान के पांच गुना सहायता में वृद्धि हुई है जबकि चाड, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य जैसे देशों में वहीं ठहरी हुई है या नाममात्र को बढ़ा है जबकि कोटे–डि आइवोरे में घटी है।

सहायता वाष्पशीलता एक अन्य चिंता का विषय है। कमजोर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के चलते, संघर्ष प्रभावित विकासशील देशों को विकास सहायता के पूर्वानुमानितीय निधियों के प्रवाह की आवश्यकता होती है। अभी तक बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य तथा चाड जैसे देशों में सहायता प्रवाह उच्च स्तरीय अनिश्चिता से विशिष्टीकृत है। अनेक देशों ने दो वर्षीय चक्र में अनुभव किया जिसमें शिक्षा हेतु सहायता दो गुनी हो गई और फिर 50% घटा दी गई।

विकास सहायता एवं विदेश नीति लक्ष्य के बीच की रेखा का धुंधलापन शिक्षा के निहितार्थों हेतु दूरगामी होते हैं

विकास सहायता एवं विदेश नीति लक्ष्य के बीच की रेखा का धुंधलापन शिक्षा के निहितार्थों हेतु दूरगामी होते हैं। यद्यपि यहां पर सहायताओं को व्यापक नीति अवसंरचना के साथ जोड़ देने के पीछे कूटनीति एवं सुरक्षा को घेरने जैसे अच्छे कारण होते हैं तथापि वहां पर यह संबद्धता भी होती है कि व्यापक, रणनीतियों जैसे स्थानीय लोगों का 'दिल एवं दिमाग' जीतना के कारण विकास लक्ष्य अधीनीकृत हो जाते हैं जिनमें शिक्षा प्रचुरता से शामिल है। सैन्य जीवन–चर्या की वृद्धि के कारण सहायता की सिपुर्दगी ने इन चिंताओं को प्रज्जवलित किया है। अफगानिस्तान में 2008 में यूएस शिक्षा का लगभग दो तिहाई हिस्सा सैन्य मांगलिकता के तहत प्रचालन सुविधा के माध्यम से प्रचालित किया गया। अफगानिस्तान में प्रादेशिक निर्माण दल और पूरे इराक में नागरिक सैन्य प्रचालन ने असुरक्षित इलाकों में सहायता की सिपुर्दगी को विभाजित किया। इसके समतुल्य व्यवहार हार्न ऑफ अफ्रीका में भी प्रयुक्त किया गया।

चित्र 12. कुछ संघर्ष प्रभावित देशों में अन्य देशों की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा सहायता में अधिक बढ़ोत्तरी हुई।

कुछ संघर्ष प्रभावित देशों में कुल प्राथमिक शिक्षा हेतु सहायता
2002–2003 और 2007–2008 औसत

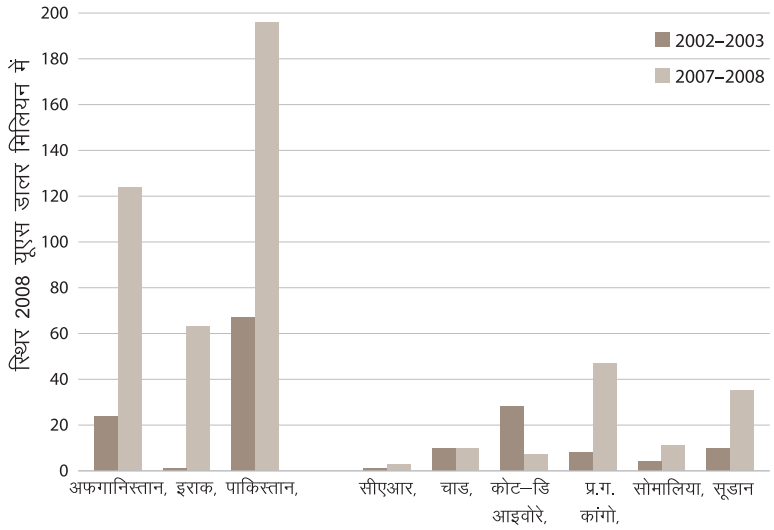

स्रोतः देखें चित्र 3.17–2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में सहायता वृद्धि का सुदृढ़ मामला है। यह मामला गहनता से सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की अग्रिमता के लिए मुख्यता अनिवर्चनीय है। दानदाताओं का भी गरीबी एवं अस्थिरता से लड़ने का अपना स्वार्थ है जो अनेक संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए भय बन जाता है। हालांकि, यहां पर सहायता सिपुर्दगी की वर्तमान एप्रोचों के साथ खतरा भी जुड़ा होता है कि यदि सहायता का उपयोग या मान लिया जाए कि विद्रोह दमन रणनीति का हिस्सा है या दानदाता देशों के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यसूची का हिस्सा है तो यह स्थानीय समुदायों एवं सहायता कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए जोखिम के प्रति विगोपित कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं पर हमलों में वृद्धि बेचैन करने वाली है और पिछले तीन सालों के दौरान 600 से अधिक सहायता कार्यकर्ताओं की हत्या एवं गंभीरता से घायल या अपहरण कर लेना एक संकेतक है। स्कूलों के निर्माण में प्रत्यक्ष यहां तक कि अप्रत्यक्ष सम्मिलन संभवतः स्कूलों में हमलों के जोखिम को बढ़ा देता है। कम की गई सुरक्षा व्याप्ति के साथ निजी निर्माणकर्ताओं का इस्तेमाल एवं विकास एक अन्य जोखिम घटक है।

अनेक प्रमुख दानदाताओं जिनमें संयुक्त राज्य एवं युनाइटेड किंगडम शामिल है–सहित अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान जैसे अनेक देशों के लिए महत्वपूर्ण रूप से समर्थन में वृद्धि की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण है कि नीतियां अनेक सवालों को संबोधित करती हैं। इसके अंतर्गत देशों के चयन के लिए मापदंड, विभिन्न देशों के पीछे भार देने का औचित्यीकरण, विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना तथा सहायता सिपुर्दगी की प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया आदि शामिल है। एक निर्णायक आवश्यकता यह है कि संगठन के प्रचालन दिशा निर्देश स्कूलों के निर्माण में सेनाओं की प्रत्यक्ष सम्मिलन को रोकने वाली हों।

संरक्षण की असफलता हेतु प्रतिक्रिया देना

सन् 1996 में ग्रैशियामैकेल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में बच्चों एवं सशस्त्र संघर्ष के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट ने बच्चों पर अनियमित आतंक एवं हिंसा की भर्त्सना की थी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया कि जो भी बच्चों पर हमले हैं उन्हें असहनीय एवं अस्वीकार्य के रूप में वर्णित किया जाए और, उसे समाप्त किया जाए। पन्द्रह साल गुजर चुके हैं और अनियंत्रित आतंक जारी है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार अरक्षणीय हमलों को सह रहा है।

मैकेल की रिपोर्ट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने एक निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रक्रम (एम आर एम) प्रतिस्थापित किया है जो छह प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों के प्रति गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघनों की पहचान करता है। संघर्ष प्रभावित देशों में बलात्कार एवं अन्य यौन उत्पीड़नों के खिलाफ संरक्षण को मजबूत बनाने के लक्ष्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनेक प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। अभी भी इस निष्कर्ष से बच निकलना कठिन है कि उन जगहों पर मानव अधिकार संरक्षण एवं सुरक्षा परिषद के

बलात्कार उत्तरजीवीयों सहित, नाजुक बच्चों के लिए एक घर में एक साथ पढ़ाई, प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो के गोमा में।

संकल्प सीमित सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं जहां कि उनकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, मुख्यतया अग्रिम मोर्चों पर बच्चों एवं नागरिकों के जीवन की सुरक्षा। यूएन एजेंसीज तथा कम संसाधन के बीच कमजोर समन्वयन एम आर एम प्रणाली के दायरे में ही समस्याओं में भागीदारी करते हैं। स्कूलों पर हमलों की रिपोर्टिंग विशेष रूप से कमजोर एवं परिसीमित है जिसमें अनेक घटनाएं बिना रिपोर्ट के ही रह जाती है। कहीं भी यह समस्याएं बलात्कार एवं अन्य यौन हिंसाओं के क्षेत्र की अपेक्षा यह समस्याएं अधिक दृश्य है। संयुक्त राष्ट्र महिला की महासचिव एवं कार्यकारी निदेशक ने अक्टूबर 2010 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि क्रियाकलापों के पास स्पष्ट दिशा निर्देशों की भारी कमी है या समय वृद्ध लक्ष्य एवं मंजिल का अभाव है जोकि क्रियान्वयन को बढ़ावा दे सकते हैं और उत्तर देयता को सुनिश्चत करते है। तथा यह प्रमाण है कि उनके सामूहिक प्रघात अपर्याप्त हैं।

इन असफलताओं के सामूहिक प्रयास दंड मुक्ति की संस्कृति को संपोषित करते हैं जोकि निजी रिपोर्टिंग प्रणाली में वर्णित की हुई है। यह रिपोर्ट प्रमुख तीन क्षेत्रों में सुधार की मांग करती है–

- निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रक्रम *(एम आर एम) प्रणाली प्रबलित करना।* बच्चों के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन के दायरे एवं पैमाने का अधिक विशाल लेखा जोखा उपलब्ध कराता है, जिसमें सतत दोषियों के नाम एवं सूचना परिषद को दी जाती है। सभी संयुक्त राष्ट्र अभिकर्ता संस्थान अधिक निकटता से साक्ष्यों का संग्रह, सत्यापन एवं संसूचित करते हैं। जो देश मानव अधिकार उत्पीड़नों को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना बनाने में क्रमबद्ध तरीके से असफल रहते हैं तो अंतिम उपाय के रूप में लक्षित एवं चयनित आधार पर दंडात्मक उपाय अनुपालित किए जाने चाहिए। जिन क्षेत्रों में, मानव अधिकार उल्लंघन युद्ध अपराध के रूप में विचारार्थ का कारण हो सकते हैं या मानवता के खिलाफ अपराध हो सकते हैं ऐसे मामलों को अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय में सुरक्षा परिषद को अधिक सक्रियता से संदर्भित करने का मामला मानना चाहिए।

- *शिक्षा पर रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाना।* शिक्षा से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग खराब ढंग से विकसित है। आज जरूरत है एक ऐसी रिपोर्टिंग प्रणाली की जो स्कूली बच्चों, स्कूलों तथा शिक्षकों पर हमलों की क्रमबद्ध एवं विशद रिपोर्टिंग को अभिलेखित करें और इसे तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए विस्तारित किया जाना चाहिए। जैसा कि यूनाइटेड नेशंस की अग्रणी एजेंसी।

- *संघर्ष के दौरान बलात्कारों एवं अन्य यौन हिंसाओं पर विनिर्णायक कार्यवाही हो।* पहले चरण के रूप में, सुरक्षा परिषद को चाहिए कि वह एक बलात्कार एवं अन्य यौन उत्पीड़नों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित करे जो संघर्ष प्रभावित देशों में समस्या के पैमाने को अभिलेखित करे, दोषियों को पहचाने और सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करे। इस आयोग का मुखिया संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यपालक निदेशक हों। कमीशन के प्रतिप्रेषण में यूएन रिपोर्ट के अंतर्गत पहचाने गए दंडमुक्ति वाले देशों में विस्तृत जांच–पड़ताल शामिल की जाए। आयोग के कार्य में अंतराष्ट्रीय दंड न्यायालय (आई सी सी) को एक सलाहकार की हैसियत से सम्मिलित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय को युद्ध अवरोधों एवं मानवता के खिलाफ अपरोधों से संबंधित राष्ट्रीय कर्ता–धर्ताओं की संभावित जिम्मेदारी को

यूनेस्को को अधिकृत एवं संसाधित किया जाना चाहिए कि वह एक प्रखर रिपोर्टिंग प्रणाली के विकास में नेतृत्व करें

मूल्यांकित करने में शामिल किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ उनकी भूमिका केवल बैठने भर की रह, बल्कि नागरिकों की संरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। यद्यपि प्रस्तावित आयोग सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करेगा तथापि साक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय को हस्तगत किए जाएंगे जोकि कानूनी कार्यवाही के लिए मामले का मूल्यांकन करेगा।

- *मानव अधिकार उल्लंघनों की समाप्ति हेतु राष्ट्रीय योजनाओं का समर्थन* – दानदाताओं को चाहिए कि कानूनी नियमों के अनुपालन को समृद्ध बनाने वाली लक्षित रणनीतियों एवं राष्ट्रीय योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए आगे बढ़ें। इस प्रकार की योजनाओं एवं रणनीतियों में, स्पष्ट तौर पर संरक्षण के लिए समय–बद्ध लक्ष्य, रोकथाम एवं कानूनी कार्यवाही शामिल होनी चाहिए। एक उदीयमान प्रयास यूएस कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया जो औरतों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय हिंसा अधिनियम है। यह गृह मंत्रालय को प्राधिकृत करता है कि 20 देशों तक यौन हिंसा को घटाने की योजनाऐं अपना सकता है।

2009 में, शिक्षा के लिए मानवीय सहायता की मात्रा 149 मिलियन यूएस डालर थी, जो कुल मानवीय सहायता का 2% भाग था

प्रावधान की असफलता – मानवीय सहायता प्रणाली को सुस्थिर बनाना

मानवीय सहायता का विहितार्थ जीवन बचाना, मूलभूत जरूरतें पूरी करना तथा मानव की मान–मर्यादा बनाए रखना होता है। इन भूमिकाओं को पूरा करने के क्रम में इसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की जीवन रेखा शिक्षा को उपलब्ध कराना चाहिए। तीन चौथाई मानवीय सहायता संघर्ष प्रभावित देशों को जाती है, अंशतः इसलिए क्योंकि बहुत सारे मानवीय सहायता कार्यकर्ता शिक्षा को 'जीवन रक्षक' के रूप में नहीं देखते हैं। परिणाम स्वरूप जो समुदाय विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा के अवसर जुटाने का संघर्ष कर रहे होते हैं, बहुत कम समर्थन प्राप्त कर पाते हैं। विस्थापित जनसंख्या भी शिक्षा में भीषण कठिनाइयों का सामना करती है।

शिक्षा मानवीय सहायता प्रणाली की एक गरीब पड़ोसन है, जोकि कम वित्त सहायता प्राप्त, अननुमेय (पूर्वानुमान रहित) तथा लघुकालिकता से अभिशासित होती है। यह दोहरी प्रतिकूलताओं को झेलती है। मानवीयता अपील, जो फंड प्राप्त करती है, के हिस्से में शिक्षा का एक छोटा अंश होता है। सबके लिए शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सर्वोत्तम अनुमान 2009 में है, जहां शिक्षा के लिए मानवीय सहायता की मात्रा 149 मिलियन यूएस डालर थी, जो कुल मानवीय सहायता का 2% भाग था (चित्र–13)। शिक्षा के लिए अनुरोध का ठीक एक तिहाई निधि के रूप में प्राप्त हुआ। इन आंकड़ों के पीछे चिरकालिक निम्न वित्तीय सहायता ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र एवं विस्थापित जनसंख्या के बच्चों का स्कूल से बाहर रखा।

शिक्षा हेतु निधि अनुरोध की कमी समस्या का केवल एक भाग है। प्रभावित जनसंख्या की मांग के हिस्से या आवश्यकताओं की किसी भी साख युक्त सहायता से असंबद्ध रहकर, अनुरोध अपने आप में अधूरा प्रकट होता है। चाड में, वर्ष 2010 में शिक्षा के लिए मानवीय सहायता की अपील केवल 12 मिलियन यूएस डालर थी, यह वह देश है जहां 170,000 अंतर–विस्थापित लोग तथा 300,000 शरणार्थी रहते हैं तथा 40% से भी कम विस्थापित बच्चे स्कूल में होते हैं। इसी तरह से प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो में, शिक्षा के लिए मानवीय सहायता का अनुरोध केवल 25 मिलियन यूएस डालर था, जिसका केवल 15% भाग 2010 में सिपुर्द किया गया। यह वह देश है, जहां 2 मिलियन से अधिक विस्थापित जनसंख्या है तथा संघर्ष प्रभावित क्षेत्र के लगभग दो तिहाई बच्चे स्कूल से बाहर है।

चित्र 13: मानवीय सहायता में शिक्षा की दोहरी प्रतिकूलता: अनुरोध का छोटा हिस्सा तथा अनुरोध का लघुतम हिस्सा जो फंड पाता है।

प्रति सेक्टर अनुरोध की गई राशि के खिलाफ प्राप्त निधियां, 2009 समेकित अपीलें एवं फ्लैश अपीलें

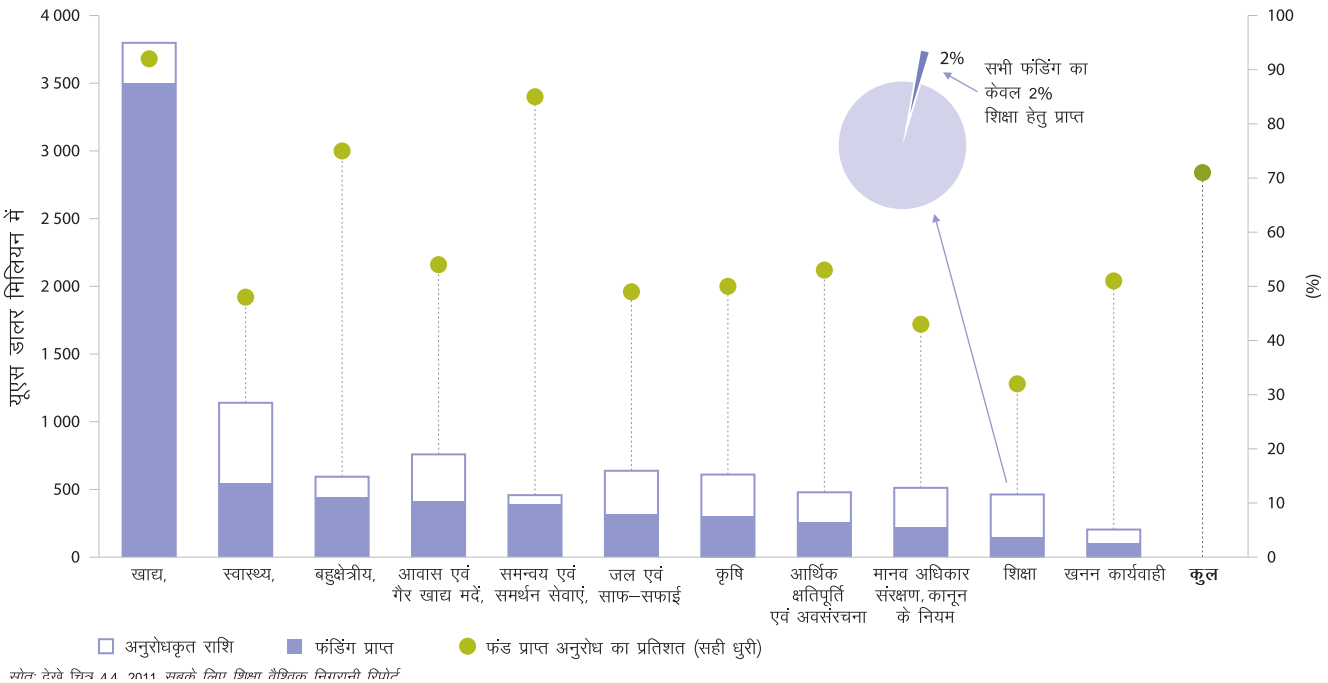

स्रोत: देखें चित्र 4.4, 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

वार्षिक बजट की सनकें आपात्काल के दौरान शिक्षा की वित्तीय सहायता की समस्याएं और भी अधिक जटिल बना देती हैं। यह परिस्थितियां विशेष रूप दीर्घकालिक विस्थापन में और भी सत्य साबित होती है। केन्या में, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिशनर फार रिफ्युजीज (यू एन एच सी आर) तथा अन्य एजेंसियां सोमालिया से आने वाले शरणार्थियों की वृद्धि के लिए शिक्षा में बहुस्तरीय नियोजन को आरोहित करने में असमर्थ रही (बाक्स–6)। और प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगों में विस्थापित बच्चों को सेवा देने वाले स्कूलों को बंद होने का भय है क्योंकि दानदाताओं की प्राथमिकताएं बदल गईं तथा लघुकालिक बजट व्यवस्था थी।

शिक्षा के लिए बलात् विस्थापन एक बड़ा प्रत्यक्ष डर है क्योंकि दोनों ही तरह के लोग शरणार्थी या आंतरिक विस्थापित लोग के नाम से श्रेणीकृत होते हैं। शरणार्थियों को सुपरिभाषित रूप से प्राथमिक शिक्षा का कानूनी अधिकार है। हालांकि, व्यवहार में, इन अधिकारों का दावा करना प्रायः कठिन होता है। बहुत सारे देश शरणार्थियों को एक कानूनी आब्रजक के रूप मे मानते हैं और प्रभावी तौर से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण से वंचित करते हैं। कुछ देश शरणार्थियों को उच्च स्तर का समर्थन प्रदान करते हैं और प्रायः ध्यान देने योग्य तनाव के बावजूद घरेलू शिक्षा प्रणाली में स्थान देते हैं। इसका एक उदाहरण जोर्डन है, जहां इराकी शरणार्थियों के बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में उपयोग की सुविधा दी गई है (बाक्स–7)।

शरणार्थियों की अपेक्षा आई डी पीएस (अंतरदेशीय विस्थापित लोग) के पास औपचारिक संरक्षण के कम अधिकार होते हैं। कोई भी यूएन एजेंसी प्रत्यक्ष तौर पर उनके हितों को बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं है। और ये लोग प्रायः राष्ट्रीय योजनाओं एवं दानदाता रणनीतियों में अदृश्य होते हैं। अभी भी यहां पर व्यावहारिक मापदंड हैं जिन्हें आई डी पीज के लिए शिक्षा के द्वार खुले रखने के लिए अपनाया जा सकता है। कोलंबिया में 1997 में आंतरिक विस्थापन

बाक्स 6: शरणार्थी लहरों (उमड़ने) हेतु प्रतिक्रिया – केन्या में दादाब से सबक

दादाब, उत्तर पूर्वी केन्या में विश्व का एक सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर परिसर है। यहां पर 250,000 सोमाली लोगों को शरण प्राप्त है जो संघर्ष उभरने पर अपने देश से भागकर आए और 20 वर्षों से अधिक समय से यहीं रह रहे हैं। चार सालों के भीतर दादाब की जनसंख्या दो गुना से अधिक हो गई। जो शिक्षा व्यवस्था 2005 में 30,000 बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही थी, वह अब 60,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा देने में जूझ रही है। अब प्रति कक्षा बच्चों की औसतन संख्या 82 से 113 तक है और जो स्कूल पहले 1000 से कम बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराते थे, वे अब 3000 से अधिक बच्चों को सेवाएं देते हैं। इसी दौरान 2005 में प्रति बच्चे प्राथमिक स्कूल के बच्चे का शेयर 100% से घटकर वर्ष 2010 में प्रति बच्चे 50% आ गया। जहां शिक्षा की जरूरतें बढ़ रही थीं, वहीं वित्तीय सहायता लगातार कमी को झेलती रही और भविष्य के बारे में ध्यान देने योग्य अनिश्चयता भी रही। यूएनएच सी आर तथा एन जी ओज – दोनों ही जो शिक्षा प्रचालन के लिए वार्षिक वित्तीय चक्र प्रदान कर रहे थे, यू एन एच सी आर निधि अनुरोध को आवृत करने में नाकाम रहा, अतः एनजीओज को वित्तीय सहायता के अन्य स्रोतों की ओर मुड़ना पड़ा। शिविरों में शिक्षा के आगे बढ़ाने हेतु एक टिकाऊ मापदंड, दानदाताओं से बहु स्तरीय नियोजित प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जिसे परिस्थितियों के बदलाव हेतु आकस्मिता निधि निर्माण की आवश्यकता है।

स्रोत : देखें–बाक्स 4.5, 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

बाक्स 7: जोर्डन में इराकी शरणार्थियों के जीवन का पुनर्निर्माण

अबु–रहमान, 15, तंगहाली के सम्मुख इराकी बच्चों की प्रतिस्कंदन (समुत्थान) का एक प्रमाण है तथा सरकार की प्रतिबद्धता एवं गैर सरकारी नवोन्मेष के संयोजन द्वारा विनिर्मित सुअवसर का परिणाम भी है। अबू रहमान एवं उसका परिवार सांप्रदायिक हिंसा की चपेट से बचकर जोर्डन आ गया और अब अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर रहा है। दो वर्ष स्कूल छूटने के बावजूद, वह अब शिक्षा मंत्रालय एवं क्वीस्टस्कोप एनजीओ के सहयोग से प्रचालित उनतालीस अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में से एक का छात्र है। ये स्कूल आठ–मासीय तथा तीन त्वरित शिक्षा चक्र उपलब्ध कराते हैं जो बच्चों को दो वर्ष के भीतर ग्रेड 1 से ग्रेड–10 तक ले जाते हैं। यहां से प्राप्त प्रमाण पत्र को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों या माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिकतर क्वीस्टस्कोप बच्चे जोर्डन नागरिक होते हैं जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी होती है, लेकिन अब यह केन्द्र अनुमानतः 1000 इराकी बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस केन्द्र का उपलब्धियां हासिल करने का उत्तम रिकार्ड रहा है और लगभग 75% बच्चे उस चक्र को पूरा कर लेते हैं जिसके लिए उन्हें भरती किया जाता है।

हालांकि अबू– रहमान का परिवार गरीब है, तथापि यूएनएचसीआर से प्राप्त उसके परिवार की लघु नकद अनुदान सहायता स्कूल आने–जाने की लागत को पूरा कर देती है। हालांकि जोर्डन सरकार की नीतियां मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराती हैं, अतः स्कूल वहन आसान हो जाता है। अबू–रहमान की स्कूल वापस आने की यात्रा काफी कठिन रही है। वह अभी भी इराक की क्षतियों एवं भीषण यादें अपने जेहन में वहन कर रहा है, फिर भी वह ऊर्जा जुटाता है, महत्वाकांक्षी है तथा आत्मविश्वास का भाव है, जिसे वह कहता है कि उसे स्कूल से प्राप्त होती है।

स्रोत : देखें बाक्स 4.9 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट*

मैक्सवेल ओजूका द्वारा बनाया गया चित्र ए रीवर ब्लू के सौजन्य से सरकारी सैनिकों एवं लार्डस रेसिसटेंस आर्मी के बीच उत्तरी युगांडा में संघर्ष के लिए एक बच्चे का दृष्टिकोण

दुनिया का एक खुलता द्वारः पूर्वी चाड इलाके में एक स्कूली इमारत

मानवीय सहायता समुदायों को अपनी कार्य–सूचियों में शिक्षा के स्थान के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता है।

पर कानून एवं तदन्तर संवैधानिक न्यायालय द्वारा कार्रवाई ने शिक्षा हेतु आई डी पी के अधिकारों को सुदृढ़ता प्रदान की है। अफ्रीका में आंतरिक विस्थापित लोगों के लिए संरक्षण एवं सहायता हेतु सम्मेलन को 2009 में यूगांडा, कंपाला में अफ्रीकन यूनियन सम्मेलन में अधिगृहीत किया गया था। जो शिक्षा में आई डी पी को सुदृढ़ कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह वह माडल हो सकता है जिसे अन्य अंचलों द्वारा अपनाया जा सकता है, यद्यपि अभी तक केवल अफ्रीकी सरकारों ने इस सम्मेलन को अभिपुष्टित किया है।

इस रिपोर्ट ने उन लोगों के लिए शिक्षा हेतु सुधारार्थ प्रावधान के लिए एक व्यापक कार्यसूची नियत की है जो लोग सशस्त्र संघर्ष में फंस जाते हैं या उनके कारण विस्थापित होते हैं। इनमें से प्रमुख तत्व हैं–

- *मानवीय मनोवृत्ति में बदलाव।* मानवीय सहायता समुदायों को अपनी कार्य–सूचियों में शिक्षा के स्थान के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता है। सबके लिए शिक्षा के लिए में सम्मिलित सभी एजेंसियों की साझेदारी को आवश्यकता है कि शिक्षा में वित्तीय सहायता एवं सिपुर्दगी हेतु व्यापक प्राथमिकताओं पर सर्वसम्मति से जोर दें।

- *आवश्यकताओं की ओर वित्त को बढ़ाना।* मानवीय सहायता हेतु एक विस्तारित एवं अधिक लचीली अवसंरचना की आवश्यकता है। संग्रह निधि हेतु बढ़ी हुई वित्तीय सहायताओं को शिक्षा वित्तीय सहायता अनुरोधों एवं सहायता सिपुर्दगी के बीच जरूरतों को छंटनी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही विस्मृत आपात्कालिक देशों एवं विस्मृत क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा आदि हेतु अधिक पूर्वानुमानित निधियों के प्रवाह को उपलब्ध करा सकते हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी अनशंसित किया है कि बहुतस्तरीय संगृहीत राशि निधि प्रक्रम जैसे कि केन्द्रीय आपात्कालिक प्रतिक्रिया निधि तथा सामान्य मानवीय निधि को उनके वर्तमान वार्षिक वित्तीय सहायता 730 मिलियन यूएस डालर के स्तर से लगभग 2 बिलियन यूएस डालर बढ़ाकर किया जाना चाहिए।

- *विश्वसनीय आवश्यकता मूल्यांकन व्यवहार।* संघर्ष प्रभावित समुदायों हेतु शिक्षा के प्रभावी प्रावधान के लिए एक विश्वसनीय मूल्यांकन की आवश्यकता का प्रारंभ बिन्दु है। वर्तमान व्यवस्था शरणार्थियों एवं विस्थापित लोगों, दोनों, ही के लिए विश्वसनीयता परीक्षण को खोजने में असफल रहा है। शिक्षा के लिए मानवीय मानवीय सहायता आवश्यकता मूल्यांकन के स्तर से संबद्ध बेहतर साप्ताहिक मूल्यांकन शरणार्थी शिविरों के लिए वित्तीय सहायता हेतु क्रमबद्ध विहंगम दृष्टि नहीं प्रदान करता और सबके लिए शिक्षा लक्ष्य हेतु अन्य आवश्यकताओं की भी नहीं, जबकि शिविरों से बाहर रहने वाले शरणार्थियों की आवश्यकताओं को व्यापक रूप से उपेक्षित किया जाता है। आइडी पीज के लिए किए गए मूल्यांकन वास्तविक जरूरतों को घोरतम कम आंकलित (न्यून प्राक्कलन) करते हैं। रिपोर्ट संस्तुत करती है कि शिक्षा समूह, अनुरोधों को समन्वयन के लिए जिम्मेदार मानवीय सहायता के अंतर्गत अंतर एजेंसी समूहों को विषेशीकृत एजेंसियों के साथ, जोकि आंकड़ा संग्रह में विषेशज्ञता प्राप्त है, शिक्षा के लिए प्रमुख संकेतकों के विकास हेतु तथा विषेश लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, वित्तीय सहायता की आवश्यकता के प्राक्कलन हेतु मिलकर काम करना चाहिए।

- *वित्तीय सहायता सुदृढ़ीकरण तथा विस्थापितों पर अभिशासन व्यवस्था।* शरणार्थियों एवं अंतर विस्थापित लोग (आई डी पी) के बीच कृत्रिम विभेद अधिक प्रभावी कार्यवाही के बीच बाधा ह जिसके लिए यूएन एच सी आर प्राधिकारों को सुदृढ़ीकृत बनाया जाए ताकि एजेंसियां शरणार्थियों एवं आई डी पीज को और अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान कर पाएं। यूनीसेफ को दी गई सक्षमता एवं संघर्ष

प्रभावित देशों में शिक्षा को समर्थन देना तथा इस क्षेत्र में यूएन एचसी आर की सीमित क्षमता को देखते हुए उनके पास शिक्षा हेतु समरूप (जुड़वा) अधिकार होने चाहिए। शरणार्थियों के परिपोषक देशों को उन नियमों को अपनाने वालों के रूप में देखा जाना चाहिए जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पहुंच को सुगमित करते हों तथा समृद्ध देशों को वैश्विक बोझ की भागीदारी के लिए और अधिक संसाधित होना चाहिए। वृहद आंतरिक विस्थापन वाले देशों को कोलंबिया का उदाहरण अनुपालित करना चाहिए तथा राष्ट्रीय विधायिका में उनके अधिकारों प्रविष्ट कराना चाहिए। आंचलिक निकायों को अफ्रीकन यूनियन कंपाला सम्मेलन के संस्करण को अपनाने पर विचार करना चाहिए और जहां तक संभव हो सके, कम से कम पन्द्रह देशों को अभिपुष्टित करना चाहिए ताकि यह देश का कानून बन जाए।

शिक्षा का पुनर्निमाण – शांति लाभांश को पकड़ना

संघर्ष उपरांत शिक्षा में पुनर्निमाण एक असीम चुनौती खड़ा करता है। सरकारें एक ऐसे वातावरण में काम करती हैं जो उच्च स्तरीय राजनैतिक अस्थिरता एवं अनिश्चयता वाली होती है तथा चिरकालिक वित्तीय अभावों शिक्षकों की कमी के सम्मुख एक टूटी हुई स्कूल व्यवस्था का निम्न स्तरीय पुनर्निमाण क्षमता के साथ बनाना, विशेष रूप से तीक्ष्ण समस्याएं खड़ी करते हैं। तब भी शिक्षा सफलता शांति को नई टेक, तर्क संगत सरकार की तथा भविष्य की अधिक शांति के लिए उपयुक्त समाज का निर्माण करने में सहायक हो सकती है। इस सुअवसर के गवाक्ष को पकड़ने में दानदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो कि शांति के साथ आती है।

जिन लोगों का जीवन सशस्त्र संघर्ष से भग्न हो चुका है, वे हिंसा से एक बेहतर भवष्यि के नई आशा एवं महत्वाकांक्षा से उभरते हैं। वे तत्काल परिणामों की आशा करते हैं तथा सरकारों को भी शांति की नींव डालने हेतु जल्द से जल्द परिणाम देकर जीतना होता है। एक व्यापक परिधि के संघर्ष प्रभावित देशों के अनुभवों के निष्कर्षों से इस रिपोर्ट ने उन रणनीतियों की पहचान की है जो जल्दी परिणाम सिपुर्द करती है। उपयोग शुल्क को हटाना, समुदाय के प्रयासों को समर्थन देना, त्वरित अधिगम अवसर उपलब्ध कराना, निशस्त्रीकरण के घटकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सैन्यविघटन तथा पुनः एकीकरण (डी डी आर) कार्यक्रम आदि उदाहरण हैं। रवांडा में, डी डी आर कार्यक्रम ने पूर्व युद्धकर्ताओं (लड़ाकों) को शिक्षा में वापसी को सुगमित किया और इनमें से अनेकों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर का लाभ उठाया।

कक्षाओं का निर्माण भी नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। दक्षिणी सूडान में, एक महत्वाकांक्षी कक्षा निर्माण कार्यक्रम ने प्राथमिक स्कूल में बच्चों की संख्या में वर्ष 2006 में 700,000 से बढ़ाकर वर्ष 2009 में 1.6 मिलियन बच्चे पहुंचाई। तत्काल परिणाम देने के लिए निम्न लागत, अर्ध–स्थाई अवसंरचना का इस उद्देश्य के साथ निर्माण कि उनकी जगह अधिक स्थाई एवं पक्का निर्माण भविष्य में किया जाएगा, आदि के प्रावधानों पर जोर देना चाहिए।

तुरंत दिलों को जीतने हेतु अधिक संतुलित राष्ट्रीय नियोजन एवं सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है। वे देश जो संघर्ष से उबरने में दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति के लिए अंतरण करते हैं जैसे कि इथोपिया, मोजांबिक, रवांडा तथा सिएरालियोन आदि देश दानदाताओं के साथ इस उद्देश्य के साथ साझेदारी निर्मित करते हैं कि शिक्षा क्षेत्र की रणनीतियों सहित विकास एवं क्रियान्वयन करते हैं जोकि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित, सुरक्षित वित्तीय सहायता वचनबद्धता से समर्थित होते हैं। शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली (ई एम आई एस) एक प्रमुख तत्व हैं क्योंकि सरकारों को संसाधन आबंटन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को पहचानने, तथा शिक्षकों के पारिश्रमिक को अवलोकित करने का साधन प्रदान करते हैं। (एक अकेला शिक्षा बजट में सबसे बड़ा बजट आइटम)। वर्ष 2006 तक, सिएरा–लियोन के गृह युद्ध की समाप्ति के चार वर्ष बाद देश ने एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली (ई एम आइ एस) के लिए अवसंरचना को सही जगह पर रख पाया।

पूर्वानुमेय एवं टिकाऊ दानदाता समर्थन शिक्षा में शांति से पुनर्निर्माण की अंतरण की सुविधाकृत करना निर्णायक होता है। इस क्षेत्र में सहायता प्रभावीपन को मानवीयता एवं विकास सहायताओं के बीच एक विभाजन हेतु अनेक समझौते करने पड़ते हैं। दानदाता प्रायः संघर्ष पश्चात राष्ट्रों को दीर्घकालिक सहायता के लिए एक कमजोर उम्मीदवार के रूप में देखते हैं; क्योंकि वे या तो संघर्ष के जोखिम की समीक्षा से संबद्धता खत्म मान लेते हैं या फिर संघर्ष पश्चात देश अधिक गहन रिपोर्टिंग आवश्यकता का पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे अनेक देश सीमित साधनों एवं अनुमेय (पूर्वानुमान रहित) मानवीय सहायता पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिए जाते हैं।

लाइबेरिया एवं सिएरा लियोन के विपरीत अनुभव अनुदेशात्मक हैं। लाइबेरियन गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात देश भारी मात्रा में मानवीय सहायताओं पर निर्भर था। इस प्रकार का समर्थन देश ने 2005–2006 तक लगभग आधा हिस्सा सहायता से ही प्राप्त किया। ठीक इसी अवधि के दौरान सिएरा लियोन के लिए मानवीय सहायता की प्राप्ति केवल 9% रही जो उसके लिए वृहद वित्तीय सहायता आवरण था। यद्यपि, केवल एक घटक, सिएरा लियोन में शिक्षा योजना के लिए अधिक सुरक्षित वित्तीय आधार ने अधिक तीव्र प्रगति को सुगमित बनाने में सहायता प्रदान की (बाक्स–8)।

निश्चित रूप से जोखिम का दानदाता परिदृश्य मानवीयता विकास विभाजन के प्रबलन में एक बाधा होती है, एक निश्चित प्रतिक्रिया जोखिम भागीदारी के लिए होती है। संसाधनों को एकत्रित करना तथा समन्वयपूर्वक काम करना दानदाताओं को जोखिम भगाने में सक्षम करता है तथा न्यासीय जो कि प्रबंधन, प्रारंभिक लागत एवं समन्वयन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सक्षम लाभ प्राप्त करता है। राष्ट्रीय कुल संगृहीत निधियां समन्वय के संभावित लाभों का प्रदर्शित करती है। अफगानिस्तान में बत्तीस दान दाताओं ने वर्ष 2002 से 2010 तक अफगानिस्तान पुनः निर्माण न्यास निधि के माध्यम से लगभग 4 विलियन यूएस डालर प्रणालित किए हैं। इस पोर्टफोलियो का शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग था। यहां पर महत्वपूर्ण रूप से परिणाम प्राप्त हुए जो न केवल स्कूल में अधिक बच्चे विशेष रूप से लड़कियों को लाने का था, बल्कि राष्ट्रीय नियोजन क्षमता के निर्माण में भी था।

वैश्विक एकत्रित निधियां संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों में एक वृहद भूमिका निभा सकती है। शिक्षा क्षेत्र के पास स्वास्थ्य में प्रचालित वैश्विक निधियों के मुकाबले काफी कम सुविधाएं हैं। फास्ट ट्रैक इनीसिएटिव (एफ टी आई अर्थात त्वरित लाभनीय प्रयास) अपनी शुरूआत 2002 से तीस देशों में अब तक 883 मिलियन यू एस डालर संवितरित किए हैं।

संघर्ष उपरांत पुनः निर्माण कार्यसूची में शिक्षा को और अधिक केन्द्रीय भूमिका दी जानी चाहिए

बाक्स 8: जल्दी शुरूआत एवं विनियोजित बने रहने ने सिएरा लियोन की मदद की

सिएरा लियोन में जो काफी कुछ किया गया, उसे संघर्ष उपरांत प्रारंभिक वर्षों में वापस जाकर देखा जा सकता है। नौ वर्षों के गृह युद्ध के बाद नाजुक या भुरभुरी शांति के साथ देश में, दानदाताओं ने दो निर्णयक नीति प्रतिबद्धताओं संकेतित किया सुरक्षा को बनाए रखना ताकि दीर्घकालिक शांति को समर्थित करना।

दानदाताओं ने वर्ष 2002 से, युद्ध की आधिकारिक बंदी की घोषणा से पूर्व ही विकास सहायता को बढ़ाना शुरू कर दिया और तदन्तर उस समर्थन को बनाए रखा। विकास सहायता की प्रतिबद्धता 2001–2002 से 2003–2004 के बीच 70% तक बढ़ी। प्रमुख दानदाताओं ने पुनर्निमाण के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनाए रखी, साथ ही साथ सरकारी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध तंत्र को मजबूत बनाया तथा सभी दानदाताओं ने दीर्घकालिक वित्तीय सहायता के साथ जिसमें प्रत्यक्ष बजट समर्थन राष्ट्रीय व्यय के एक तिहाई हिस्से के समतुल्य सहित देश की वित्तीय गरीबी उन्मूलन रणनीति (2008–2012) को समर्थित किया।

पुनर्निमाण प्रक्रिया में शिक्षा को केन्द्र में रखा गया, जिसमें समानता, विशेष रूप से सुधार के द्वितीय चरण पर सुदृढ़ ध्यान केन्द्रण रखा गया। बजट समर्थन वित्तीय अनुदान को, प्राथमिक शिक्षा में शुल्क समाप्ति तथा पुस्तकें उपलब्ध कराने के अनुपालानार्थ किया गया। वर्ष 2000–2004 तक दानदाताओं का समर्थन सरकारी प्रतिबद्धता से सुमेलित किया गया जो शिक्षा में प्रतिवर्ष 11% की दर से औसतन व्यय रहा।

स्रोत : देखें बाक्स 5.5 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट में*

जबकि इसके विपरीत एड्स तपेदिक एवं मलेरिया से लड़ने वाले वैश्विक फंड के तहत इन्हीं वर्षों के दौरान 10 बिलियन यूएस डालर संवितरित किए गए। 2011 सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट द्वारा संबोधित किए गए संवितरण एवं अभिशासन जैसे मुद्दों से संबंधित किया गया है और एक बड़ा वाह्य मूल्यांकन भी किया गया है। यदि सुधार को आद्योपांत एवं गहनता से किया गया होता तो एफ टी आई बहुस्तरीय वित्तीय प्रणाली का आलंब बन कर संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों की अत्यावश्यक जरूरतों को संबोधित करने में सक्षम हो सकता था। हालांकि; संघर्ष से उबरने वाले देशों के उपचार में व्यापक लचीलेपन की जरूरत होती है। इनमें से अनेक को वित्तीय समर्थन प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही इसे एक विस्तारित संसाधन आधार की जरूरत होती है–एफटीआई ने वर्ष 2009 में 222 मिलियन यूएस डालर संवितरित किए जबकि निम्न आय देशों के लिए वाह्य वित्तीय सहायता अंतराल 16 बिलियन डालर अनुमानित किया गया है।

इस रिपोर्ट का संदेश है कि संघर्ष उपरांत पुनः निर्माण कार्यसूची में शिक्षा को और अधिक केन्द्रीय भूमिका दी जानी चाहिए। यह रिपोर्ट चार प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई अनुशंसित करती है।

- *शिक्षा को अधिक किफायती एवं गमनीय बनाने के द्वारा त्वरित जीत हेतु अवसरों का पकड़ना* स्कूल की फीस को समाप्त करना, युद्ध पश्चात शांति के लाभांश के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। कौशलों, प्रशिक्षणों को सुदृढ़ीकृत करना तथा डी डी आर कार्यक्रमों में समर्थन हस्तक्षेप पूर्व लड़ाकों के लिए अवसरों को विस्तारित करने के द्वारा हिंसा की वापसी को संभावना को समाप्त किया जा सकता है। जबकि तीव्र किए गए अधिगम कार्यक्रम उन लोगों को शिक्षा में वापसी का रास्ता दिखाते हैं जो संघर्ष के वर्षों में वंचित रह गए थे।

- *दीर्घ कालिक क्षतिपूर्ति के लिए नींव या आधार बनाना* नियोजन के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण, ईएमआई प्रक्रम की निर्मित एवं शिक्षक वेतन प्रणाली की सुदृढ़ीकृत करना को तकनीकी संबद्धता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सक्षमता, उत्तरदायित्व एवं समावेशन बनाने के लिए आधारभूत है।

- *राष्ट्रीय संग्रहीत (एकत्रित) निधियन हेतु समर्थन वृद्धि* यह दानदाताओं के बीच व्यापक परिधि के लाभ हेतु समन्वय को बंधन मुक्त कर सकता है। सहायता एजेंसियों को सक्रियता के साथ विद्यमान संग्रहीत (एकत्रित) निधि व्यवस्था को संबंधित करने हेतु संभावनाओं को तलाशना चाहिए तथा उन देशों में नई निधियों को स्थापित करना चाहिए, जिन्होंने कम ध्यान आकर्षित किया है जिनमें चाड तथा प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगों आदि शामिल है।

- *अधिक प्रभावी वैश्विक संग्रहीत (पूल्ड) निधि हेतु–एक त्वरित पथगामी प्रयास (फास्ट ट्रैक इनीसिएटिव) बनाना* शिक्षा क्षेत्र को तत्काल एक संग्रहीत (पूल्ड) निधि प्रणाली की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रचालन की भांति सक्षम एवं पैमाने पर होना चाहिए। यह रिपोर्ट वर्ष 2011–2013 तक लगभग 6 बिलियन यूएस डालर की वित्तीय सहायता एफ टी आई के लिए संस्तुत करती है जिसका लगभग एक तिहाई शिक्षा बोंड से आ सकता है जैसा कि अध्याय 2 में प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, सुधार को उन देशों तक विस्तारित करने की जरूरत है जो संघर्ष से उबर रहे हैं जिसमें क्षतिपूर्ति हेतु दीर्घकालिक निधियों के साथ, तुरंत जीत की सक्षमता हेतु अल्पकालिक अनुदानों के प्रावधान भी शामिल है।

शांति के लिए शिक्षा को एक ताकत बनाना

जब समाज संघर्ष से एक भंगुर शांति में उभरते हैं तथा एक दीर्घकालिक शांति निर्माण की दिशा में यात्रा प्रारंभ करते हैं, तब शिक्षा नीति सरकारों को एक अवसर प्रदान करती है कि गुजरी हुई पैतृकता से लड़ते हुए एक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एक प्रेरक शिक्षा प्रणाली विकसित करें।

प्रारंभिक बिन्दु यह मानता है कि शिक्षा मायने रखती है। जैसा कि सरकार शिक्षा प्रणाली को पुनः निर्मित करना प्रारंभ करती है तो उन्हें संघर्षोपरांत वातावरण के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हिंसा की परंपरा (बपौती) एवं अविश्वास रातोंरात समाप्त नहीं होता है। सरकारों को विचार करना चाहिए कि समूहों व क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक प्रतिद्वन्द्वताओं एवं अंशतः समाधानित विवादों के आलोक में नीति विकल्पों को कैसे संदर्भित किया जाएगा। शिक्षा में संघर्ष संवेदी नियोजन तथा हिंसा की वापसी से बचाव के परिप्रेक्ष्य एवं यह मानना कि निर्णय के परिणाम शांति निर्माण के लिए होंगे। लोगों को क्या सिखाया गया है, उन्हें कैसे सिखाया–पढ़ाया गया है और शिक्षा प्रणाली को कैसे आयोजित किया गया है आदि चीजें समाजों को अधिक या कम हिंसात्मक संघर्ष के प्रति नाजुक बना सकते हैं।

शिक्षा ने व्यापक शांति निर्माण कार्यसूची में क्रमबद्ध उपेक्षा को झेला हैं। यह उपेक्षा संघर्ष बचाव तथा अधिक सहनशील समाजों के विकास हेतु एक नष्ट हुए सुअवसर का प्रतिनिधित्व करती है। इससे भी अधिक यह एक भय का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें एवं दानदाता, जो शिक्षा को उपेक्षित करते हैं, वे शांति निर्माण में

सरकारें एवं दानदाता, जो शिक्षा को उपेक्षित करते हैं, वे शांति निर्माण में शिक्षा की भूमिका की अनदेखी करते हुए देशों को कम सुरक्षित, अधिक हिंसक भविष्य के पथ पर स्थापित करते है।

मेडेलिन कोलंबिया में एक स्कूली लड़की, जहां सरकारी सेनाओं एवं अर्बन मिलीशिया के बीच गोलीबारी में स्कूल फंस गया।

© जीसस अबेद कोलोराडो

शिक्षा की भूमिका की अनदेखी करते हुए देशों को कम सुरक्षित, अधिक हिंसक भविष्य के पथ पर स्थापित करते है।

यूनाइटेड नेशंस के शांति निर्माण आयोग एक अंतर सरकारी सलाहकार समिति तथा उससे संबंधित पीसबिल्डिंग फंड (शांति निर्माण निधि) में सुस्पष्ट हैं यह फंड (निधि) यू एन की संघर्ष पश्चात विन्यासक के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरकर आया है। हालांकि, वित्तीय सहायता के रूप में पीबीएफ (शांति निर्माण फंड) निधि बहुत होती है (वर्ष 2006 तक कुल 347 मिलियन यूएस डालर वृद्धि हुई है) और कुल उपलब्ध कराई गई निधियों में ठीक 3% हिस्सा विशिष्ट परियोजनाओं का होता है। एक अन्य समस्या यह है कि शांति निर्माण निधि मुख्यतः कुछ एक परियोजनाओं समर्थन करती है जो कि दीर्घ कालिक नियोजन प्रक्रिया में कमजोर ढंग से संबद्ध हैं।

यह रिपोर्ट एक व्यापक क्रम विन्यास के चैनल को अन्वेषित करती है, जिसके माध्यम से शिक्षा शांति हेतु संदर्शों को प्रभावित कर सके। यह जोर देती है कि यहां पर अंतिम रूपरेखा (खाका) नहीं है। यद्यपि प्रारंभ बिन्दु यह है कि शिक्षा में एक प्रस्तुत नीति कितना नीति निर्माताओं हेतु हस्तक्षेप करती है, और सशस्त्र संघर्ष से संबद्ध शिकायतों को प्रबलित कर सकती है और नीति की संभावित जन संदर्शों को सावधानी पूर्वक महत्व दे सकती है तथा निम्न क्षेत्रों में संभावित परिणामों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी ले सकती है, यथाः

- *निर्देशों की भाषा*. संघर्ष उपरांत कठिन विकल्पों का सामना करने वाली सरकारों के पास बेहतर प्रदर्शन के लिए भाषा नीति के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता है। कुछ संदर्भों में, जैसे कि संयुक्त गणतंत्र तंजानिया में एक अकेली राष्ट्रीय भाषा के उपयोग ने स्कूलों में निर्देशों के माध्यम ने एक साझे पहचान के भाव को अपनाने में बहुत मदद की है। ग्वाटेमाला में, जहां शिक्षा में भाषा की नीति देशज लोगों के लिए एक गहन विद्वेष (मनोमालिन्य) का एक स्रोत थी। शिकायतों को संबोधित करने, संवाद को बढ़ावा देने तथा द्विभाषा के विकास हेतु एक पाठ्यक्रम निर्धारित करने एवं अंतर सांस्कृतिक शिक्षा—एक उपागम जो शायद व्यापक औचित्यपूर्ण हो सकता है—हेतु एक शिक्षा सुधार आयोग बनाया गया।

- *पाठ्यक्रम को सुधारना*. इतिहास एवं धर्म जैसे विषयों का पढ़ाना हिंसा हेतु एक अति संवेदनशीलता रखते हैं। एक बहु नृजातीय या बहुधर्मी समाज में पाठ्यक्रम यह आकार देने में सहायक होता है कि छात्र ''दूसरों के साथ'' संबंधों में खुद को कैसे देखता है। पहचान के मुद्दों से निपटने में शिक्षा सुधार कठिन विकल्पों/चुनावों से टकराते एवं समय लेते हैं। कंबोडिया की शिक्षा प्रणाली अब केवल जाति संहार के इतिहास को संबोधित कर रही है। रवांडा में, जहां शिक्षा प्रणाली को विभाजन के लिए प्रबलित किया गया, सरकार अभी तक देश का इतिहास पुनः नहीं प्रस्तुत कर पाई है। अभी तक दूसरी जगहों के अनुभव दर्शाते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से गहन समाए विभाजनों को दूर करने हेतु छात्रों को उनकी बहु पहचान से परिचित कराएं और उन्हें कौन सी चीज विभाजन से हटाकर एकीकृत कर सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तरी आयरलैंड के गुड फ्राइडे समझौते ने नागरिकता के व्यापक परिदृश्यों को खोल दिया, जिसमें छात्रों को संभावित पहचानोंकी परिधि को देखने हेतु एक विचार के लिए अनुमत कर प्रोत्साहित किया गया कि लोग आइरिश या ब्रिटिश दोनों ही हो सकते हैं या फिर केवल आइरिश, बिना उनकी धार्मिक जुड़ाव के। यह एक अच्छा उदाहरण है जिसे अमर्त्यसेन ने वर्णित किया है बहुपहचानों की ओर खिसकना तथा एक समूह के एकल जुड़ाव से दूर जाना।

- *शिक्षा अभिशासन का अवक्रमण या अंतरण*. विकेन्द्रीकरण एवं अंतरण (या अवक्रमण) को प्रायः व्यापक उत्तरदेयता के लिए एक स्वचलित मार्ग के रूप में देखा जाता है और साथ ही साथ शान्ति निर्माण के रूप में भी। जो मूल्यांकन कई बार वर्णित हो चुका है। कुछ देशों में, उच्च विकसित शिक्षा प्रणाली के साथ, केन्द्र सरकार की कमजोर भूमिका शांति निर्माण के प्रयास को हानि पहुंचा सकती है। इसका एक उत्तेजक उदाहरण बोसनिया एवं हर्जेगोबिना का है। 1995 डेयटन समझौते के अंतर्गत, लगभग 3.8 मिलियन लोगों के साथ एक देश को तेरह शिक्षा मंत्रालयों तथा एक संयुक्त स्कूल प्रणाली पर छोड़ दिया गया। संघीय सरकार ने शिक्षा पर प्रगतिशील सिद्धांत को अपना लिया। हालांकि, निम्नतम संघीय राष्ट्र की उपस्थिति में, बच्चों को लगातार तीन भिन्न पाठ्यक्रम—इतिहास संस्कृति तथा भाषा को पढ़ाया गया। कई बार पूवाग्रहों को प्रचलित करने के तरीके पढ़ाया गया। कुलमिलाकर इससे भी ज्यादा, कुछ स्कूल अभी भी कुछ समूह द्वारा देखे जा रहे हैं, वे अपने राष्ट्रीय हीरो तथा

शिक्षा किस प्रकार से गहन समाए विभाजनों को दूर करने हेतु छात्रों को उनकी बहु पहचान से परिचित कराएं और उन्हें कौन सी चीज विभाजन से हटाकर एकीकृत कर सकती है

हिंसात्मक संघर्ष के खिलाफ लचीलेपन के निर्माण में शिक्षा एक अत्यावश्यक भूमिका निभा सकती है।

शत्रुता के प्रतीकों को आगे बढ़ा रहे हैं।

- *स्कूलों को अहिंसक वातावरण बनाना.* शिक्षा के लिए एक रणनीति असंदिग्ध रूप से, बच्चों एवं शांति निर्माण तथा स्कूलों को अहिंसक जगह बनाने के लिए अच्छी है। समाज में हिंसा के सामान्यीकरण को चुनौती देना, शारीरिक दंड के प्रभावी रोकथाम के हिस्से में निर्भर करता है।

जैसाकि प्रत्येक सशस्त्र संघर्ष अंतर निहित तनावों एवं संघर्ष संकल्पों की असफलताओं के भिन्न स्वरूपों को प्रतिबिंबित करता है, अतः प्रत्येक संघर्षोपरांत संदर्श को शिक्षा प्राप्ति हेतु एक भिन्न भय एवं सुअवसरों को रूप में चिहिंत किया गया है जो रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित अन्य उपगमों के साथ हैः

- *यह मानना कि संघर्ष–पश्चात के वातावरण का एक भाग शिक्षा है* राष्ट्रीय सरकारें और दानदाताओं को यह अहसास करने की आवश्यकता है कि उनका चाहे जो विहितार्थ हो, संघर्ष की परंपरा के द्वारा निर्मित एक राजनीतिक वातावरण में शिक्षा नीति सुधार आगे बढ़ाया जाएगा। सभी नीति विकासों को संघर्ष पश्चात जोखिम मूल्यांकित अपरिणर्य रूप से किया जाना चाहिए।
- *शांतिनिर्माण निधि विस्तार.* एक व्यापक शांति निर्माण रणनीति में शिक्षा को समेकित करने में शांति निर्माण आयोग सरकारी प्रयासों को और अधिक सक्रियता से समर्थित करने में सहायक हो सकता है। पीबीएफ (शांति निर्माण निधि) के माध्यम से उपलब्ध से साधनों को 500 मिलियन यूएस डालर से बढ़ाकर 1 बिलियन यूएस डालर प्रतिवर्ष करने से शांति के द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसर के झरोखे को और अधिक प्रभावी ढंग से दोहित करने में सुगमता हो सकती है।
- *शांति निर्माण प्रयासों में यूनेस्को एवं यूनीसेफ की भूमिका को बढ़ाना.* दानदाता संघर्ष संवेदी शिक्षा नियोजना में भागीदारी कर सकते है। विनियोजन का पहला सिद्धान्त "हानि नहीं पहुंचाना" है। इसी कारण कोई भी शिक्षा नीति संभावित प्रभाव के कठिन मूल्यांकन का विषय होना चाहिए जो न केवल तकनीकी डाटा को परिकलन में लेना है, बल्कि जनता के परिप्रेक्ष्य एवं दीर्घकालिन शिकायतों को भी शामिल करें। केवल नियोजन एवं वित्तीय संसाधनों के अलावा टिकाऊ शान्ति निर्माण की ज्यादा आवश्यकता है। इसके साथ ही इसमें समर्पित उन व्यावसायिकों तथा एजेंसियों की आवश्यकता है जो पाठ्यक्रम विकास से लेकर पाठ्य पुस्तक विन्यास एवं शिक्षक प्रशिक्षण के परिधि क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हों। यह वह क्षेत्र है जिसमें यूनेस्को एवं यूनीसेफ को और अधिक निर्णायक भूमिका निभाने की आवश्यकता है और दोनो ही एजेंसियों को यूनाइटेड नेशंस शांति निर्माण आयोग में अधिक सक्रियता से भाग लेना चाहिए।

हिंसात्मक संघर्ष के खिलाफ लचीलेपन के निर्माण में शिक्षा एक अत्यावश्यक भूमिका निभा सकती है। इक्कीसवीं शदी में स्कूलों को बच्चों को ये सभी चीजें पढ़ाने की आवश्यकता है जो बहु–सांस्कृतिक –समाज के फूलने–फलने, तर्कणीय ढंग से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सजीव कौशल है– वह कौशल है अन्य लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहना। धार्मिक, नृजातीय, भाषाई तथा जातीय विविधता के प्रति जागरूकता को कक्षा–पाठन से बिल्कुल समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। उलटे विविधता को मान्यता एवं प्रशंसित किया जाना चाहिए। लेकिन स्कूल एवं कक्षाएं इन सबसे ऊपर वह जगह है, जहां बच्चे घुले–मिले, भागीदारी करें तथा दूसरों को सम्मान दें। कोई भी देश तब तक शांति के लिए चिर स्थायी आधार नहीं प्रतिस्थापित कर सकता, जब तक कि नागरिकों के बीच परस्पर सहमति की जगह नहीं होती और वह जगह कक्षा है, जहां से शुरूआत कर सकते हैं। ■

साउथ ओसेटिया, जार्टसेम का गांव जियोरिजियन में एक कक्षा, जो अगस्त 2008 के युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयी।

© सरगेई मैक्सीमिशन/पैनोस

गुप्त संकट:
सशस्त्र संघर्ष एवं शिक्षा

जब युद्ध शुरू होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान एवं निरंतर रूप से मीडिया रिपोर्टिंग मानवीय व्यथाओं की अति तत्काल छबियों को आलोकित करती है। यद्यपि इन छबियों की पृष्ठ भूमि में एक गुप्त संकट होता है। दुनिया भर के तमाम गरीबतम देशों में सशस्त्र संघर्ष न केवल स्कूल अवसंरचना को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की पीढ़ियों की आशाओं एवं महत्वाकांक्षाओं को विनष्ट करते हैं।

गुप्त संकट : सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा सशस्त्र संघर्ष के शिक्षा पर पड़े भयानक प्रभावों को अभिलेखित करती है। यह बच्चों को स्कूल से बाहर रखने वाले व्यापक मानव अधिकारों के दुरूपयोगों को परीक्षित करती है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रणाली पर आपत्ति करती है जो शिक्षा हेतु क्षतित करने वाले दुष्परिणामों के साथ संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों में असफल रही है। यह चेतावनी देती है कि स्कूलों को प्रायः असहनशीलता पूर्वाग्रह तथा सामाजिक अन्याय आदि को संचारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

यह रिपोर्ट सरकारों का आह्वान करती है कि स्कूली बच्चों एवं स्कूलों के आसपास होने वाले हमलों के लिए दंडाभाव की संस्कृति से लड़ने में व्यापक संकल्प प्रदर्शित करें। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहायता विन्यास को स्थिर करने हेतु एक कार्यसूची स्थापित की है। इसके साथ ही इसने शांति निर्माण में शिक्षा की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु रणनीतियों को भी पहचान लिया है।

यह 2011 *सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट* का सारांश है। इसकी पूरी रिपोर्ट के साथ–साथ विशद शिक्षा सांख्यकी एवं सूचकांक तथा अन्य भाषाओं के सरंस्करण www.efareport.unesco.org पर आन लाइन उपलब्ध है।

मैं दुनियाभर की सरकारों के लिए यूनेस्को के आह्वान का समर्थन करता हूँ कि बमों एवं बंदूकों पर कम निवेश करें तथा पुस्तकों, स्कूलों एवं शिक्षकों पर अधिक करें।

ऑस्कर एरियाज सांचेज
(नोबल शांति पुरस्कार, 1987)

मैं आशा करता हूँ कि सभी देशों के राजनैतिक नेता यूनेस्को के सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट *के संदेश पर ध्यान देंगे और याद रखेंगे कि शिक्षा को कभी भी युवाओं के मन में पूर्वाग्रह, असहनशीलता एवं अनादर का जहर भरने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। स्कूल शांति के लिए एक शक्तिवान बल हो सकते हैं।*

शिरिन इबादी
(नोबल शांति पुरस्कार 2003)

यूनेस्को की सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट *का एक प्रमुख संदेश यह है कि शिक्षा संघर्ष रोकने, संघर्ष के बाद देशों के पुनर्निर्माण एवं शांति निर्माण के लिए एक ताकत साबित हो सकती है। मै पूरे दिल से इस संदेश का समर्थन करता हूँ।*

जोसे रामोस–होर्ता
(नोबल शांति पुरस्कार, 1996)

यूनेस्को की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट *यौन हिंसा एवं बलात्कार के अनिष्टकारी संघात पर हमारी समझ को यह याद दिलाते हुए बढ़ाता है कि यह शिक्षा पर एक अतिरिक्त संघात है–एक ऐसी कडी जिसे बहुत–बहुत लंबे समय तक उपेक्षित किया गया है।*

मैरी रोबिन्सन
(मानव अधिकार हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग 1997–2002।

यूनेस्को रिपोर्ट काफी समय से अपेक्षित है। यह विश्व के सर्वाधिक सुकुमार कुछ लोगों के खिलाफ नृशंस अमानवीय हिंसा के नग्न विवरणों को अभिलेखित करती है, जिसमें स्कूली बच्चे शामिल हैं तथा यह दुनियाभर के सभी नेताओं चाहे गरीब हो या अमीर देशों को निर्णायक कार्यवाही करने हेतु चुनौती देती है कि दुनिया भर के नेताओं से मेरी अपील है कि वे एक साधारण वकतव्य पर दृढ़ संकल्प हों कि "बस अब बहुत हुआ।"

डेसमंड टूटू
(नोबल शांति पुरस्कार, 1984)

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

यूनेस्का
प्रकाशन

EFA GMR सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट

www.efareport.unesco.org